



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 15, 1999/आश्विन 23, 1921

No. 630]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1999/ASVINA 23, 1921

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 15 अक्टूबर, 1999

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

का.आ. 1035(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 और धारा 19 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 कहा जा सकेगा ।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) “अधिनियम” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) “विज्ञापन” के अंतर्गत :

(i) सूचनाएँ, विवरणिकाएँ, पुस्तिकाएँ, परिपत्र, शो कार्ड, सूचीपत्र, विज्ञापन पत्र, प्लेकार्ड, पोस्टर, समाचारपत्रों में अंतःस्थापन, चित्र, फिल्मों, प्रस्ताव दस्तावेज के आवेष्टक पृष्ठ हैं ;

(ii) कोई अन्य विषय जिसके लिए प्रचार मुद्रण माध्यम, रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रमों या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की माफ़त किया जाता है ।

(ग) “अंकक एजेंसी” से स्कीम के तकनीकी या वित्तीय अंकन संचालित करने के प्रयोजन के लिये बोर्ड के पास पैनलित एजेंसी अभिप्रेत है ;

(घ) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी या न्यासी के संबंध में “सहयुक्त”, के अंतर्गत वह व्यक्ति है :

(i) जो प्रत्यक्षतः या परोक्षतः, स्वयं उसके द्वारा, या अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ, यथास्थिति, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी या न्यासी पर नियंत्रण प्रयुक्त करता है, या

(ii) जिसकी बाबत सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी या न्यासी, यथास्थिति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः, स्वयं इसके द्वारा, या अन्य

व्यक्तियों के साथ-साथ, नियंत्रण प्रयुक्त करता है, या

- (iii) जिसका निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी, यथास्थिति सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी या न्यासी का निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी है ;
- (ड) “लेखापरीक्षक” से कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए अर्हित व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (च) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (छ) “प्रमाणपत्र” से इन विनियमों के विनियम 10 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;
- (ज) “सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित और इन विनियमों के अधीन बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत वह कंपनी अभिप्रेत है, जिसका उद्देश्य सामूहिक विनिधान स्कीम को संचालित करना, चलाना और प्रबंधित करना है ;
- (झ) “सामूहिक विनिधान स्कीम” का अर्थ इस विनियम के उप-विनियम (2) द्वारा इसको नियत है ;
- (ञ) “सीमित अवधि वाली स्कीम” से सामूहिक विनिधान स्कीम द्वारा चालू की गयी कोई स्कीम अभिप्रेत है, जिसमें स्कीम की परिपक्वता की कालावधि विनिर्दिष्ट है और स्कीम की परिपक्वता के अवसान के पूर्व पुनर्क्रय के लिये कोई उपबंध नहीं है ;

- (ट) “नियंत्रण या नियंत्रक हित” से प्रयुक्त नियंत्रण या धारित नियंत्रक हित अभिप्रेत है :
- (i) कंपनी के मामले में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समुच्चय द्वारा जो ऐसी कंपनी के मताधिकारों के 10% से अन्यून वाले शेयरों का प्रत्यक्षतः या परोक्षतः स्वामी होता है, नियंत्रण करता है या धारण करता है ; या
- (ii) जहाँ तक दो कंपनियों का संबंध है, यदि वही व्यक्ति या व्यक्तियों का समुच्चय, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः, दो कंपनियों में से प्रत्येक के मताधिकारों के 10% से अन्यून वाले शेयरों का स्वामी होता है, नियंत्रण करता है या धारण करता है ; या
- (iii) किसी कंपनी के निदेशकों की बहुसंख्या जो सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी पर नियंत्रण प्रयुक्त करने की स्थिति में है ।
- (ठ) “साख निर्धारण एजेंसी” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसी) विनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत निगमित निकाय अभिप्रेत है ;
- (ड) “निक्षेपागार” से निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) में यथा परिभाषित निगमित निकाय अभिप्रेत है ;
- (ढ) “आर्थिक अपराध” से वह अपराध अभिप्रेत है जिसको तत्समय आर्थिक अपराध (अभियोजन की परिसीमा) अधिनियम, 1974 (1974 का 12) लागू होता है ;
- (ण) “प्ररूप” से पहली अनुसूची में इस हैसियत से विनिर्दिष्ट प्ररूपों में से कोई अभिप्रेत

है;

- (त) “कपट”, का वही अर्थ है जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 17 में इसको नियत है ;
- (थ) “निरीक्षण अधिकारी” से इन विनियमों के अध्याय VII के अधीन बोर्ड द्वारा ऐसी हैसियत से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (द) कंपनी के संबंध में “मूल-कार्मिक”, से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो इसके कार्यकलापों का प्रभावी नियंत्रण प्रयुक्त करते हैं ;
- (ध) “शुद्ध-मूल्य” से समादत्त इक्विटी पूँजी और खुली आरक्षितियों (पुनर्मूल्यांकन में से सृजित निधियों को अपवर्जित करते हुए) का संकलित मूल्य, बट्टे खाते में न डाली गयी संचित हानियों और आस्थगित व्यय के संकलित मूल्य द्वारा घटायी गयी, जिसके अंतर्गत बट्टे खाते में न डाले गए प्रकीर्ण व्यय हैं, अभिप्रेत है;
- (न) “प्रस्ताव दस्तावेज” से कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जिसके द्वारा स्कीम की यूनिटों के अभिदाय के लिये आवेदन जनता से आमंत्रित किये जाते हैं ;
- (प) “विनियम” से इन विनियमों का भागरूप विनियम अभिप्रेत है ;
- (फ) “नातेदार” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6 में यथा परिभाषित नातेदार है ;
- (ब) “निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन रजिस्ट्रार और

शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 के अधीन निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(भ) “अनुसूची” से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में से कोई अभिप्रेत है ;

(म) “स्कीम” से सामूहिक विनिधान स्कीम अभिप्रेत है ;

(य) “स्कीम संपत्ति” के अंतर्गत :

(i) स्कीम में धन या नकद मूल्य की वस्तु (जिसके अंतर्गत बैंक निक्षेप हैं) का अभिदान ;

(ii) इस खंड की मद (i) में निर्दिष्ट धन के अभिदान, के साथ, या की आगमों के साथ, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अर्जित संपत्ति या

(iii) मद (i) या (ii) में निर्दिष्ट अभिदान धन या संपत्ति से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उद्भूत आय,

(कक) “प्रतिभूति विधियाँ” से :

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) ;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) ; और

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), समय-समय पर यथा संशोधित ;

अभिप्रेत है ;

- (खख) “स्टाक दलाल” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) नियम, 1992 में यथा परिभाषित स्टॉक दलाल अभिप्रेत है ;
- (गग) “न्यासी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यूनिट धारकों के फायदे के लिये न्यास में सामूहिक विनिधान स्कीम की संपत्ति रखता है, इन विनियमों के अनुसार ;
- (घघ) “यूनिट” के अंतर्गत स्कीम, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाये, के अधीन निर्गमित कोई लिखत है, यूनिट धारक के अभिदान के मूल्य का द्योतन करने वाली ;
- (डड) “यूनिटधारक” से स्कीम में यूनिट धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ।
- (2) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “सामूहिक विनिधान स्कीम” से किसी विवरण की संपत्ति की बाबत कोई स्कीम या इंतजाम अभिप्रेत है -
- (क) जिसका प्रयोजन विनिधानकर्ताओं को अभिदानों के तौर पर स्कीम या इंतजामों में भाग लेने और ऐसी संपत्ति या उसके किए गए विनिधानों के प्रबंधन से उद्भूत लाभ या आय या उत्पादन प्राप्त करने में समर्थ बनाना है ; और
- (ख) जिसमें विनिधानकर्ताओं के अभिदान चाहे किसी भी नाम से पुकारे जायें, एकत्र किये जाते हैं, स्कीमों या इंतजामों के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाते हैं ; और
- (ग) जिसमें संपत्ति या ऐसे अभिदानों का प्रबंध उन विनिधानकर्ताओं की ओर से किया जाता है, जो स्कीम के प्रबंध या प्रचालन

पर दैनंदिन नियंत्रण नहीं रखते हैं,

चाहे ऐसी संपत्तियाँ या अभिदान और उसके किए गए विनिधान पहचान ली जा सकने वाली संपत्तियों या से अन्यथा द्वारा साक्ष्यित हों या नहीं ;

परंतु यह कि निम्नलिखित को सामूहिक विनिधान स्कीम नहीं समझा जायेगा :

- (क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58क के अधीन कंपनियों या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1 में यथा परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निक्षेपों का प्रतिग्रहण ;
- (ख) चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) के निबंधनों के अनुसार चिट फंडों द्वारा निधियों का प्रतिग्रहण ;
- (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620क के अधीन निधि कंपनियों के रूप में घोषित कंपनियों द्वारा निधियों का प्रतिग्रहण, अधिनियम की धारा 637क के अधीन जारी निदेशों के अनुसार ;
- (घ) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन बीमा की संविदाएँ ;
- (ङ) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अनुसार नियोक्ता की कोई स्कीम ; या आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई अन्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि ;
- (च) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन सहकारी सोसाइटियों जिनके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त

किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियाँ हैं के इंतजाम ;

- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अधीन कोई स्कीम ; या
 - (ज) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से छूट-प्राप्त कोई अन्य स्कीम या इंतजाम, इन विनियमों के प्रवर्तन से ।
- (3) इन विनियमों में उपयोग किये गये और अपरिभाषित, किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः नियत हैं ।

अध्याय II

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी का रजिस्ट्रीकरण

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से 3.
भिन्न किसी व्यक्ति का स्कीम चालू न
करना

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति जिसने इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया हो सामूहिक विनिधान स्कीम नहीं चलायेगा या प्रायोजित नहीं करेगा या चालू नहीं करेगा।

प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये आवेदन 4.

इन विनियमों के प्रारंभ को या के पश्चात् सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के रूप में कोई क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति भाग क में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिये बोर्ड को आवेदन करेगा।

विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीमों 5.(1)
द्वारा आवेदन

कोई व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व स्कीम का प्रचालन कर रहा था, इन विनियमों के अध्याय IX के उपबंधों के अध्याधीन ऐसी तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये बोर्ड को आवेदन करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन में ऐसी विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी जैसी प्ररूप क में विनिर्दिष्ट हैं और विनियम 4 के अनुसरण में किए गए आवेदन के रूप में मानी जाएँगी और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदन के साथ आवेदन फीस 6.

विनियम 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ किया जायेगा ।

आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप 7.
करना

आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है या विनियम 6 या 9 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता है बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिया जायेगा ।

परंतु यह कि कोई ऐसा आवेदन नामंजूर करने से पूर्व, आवेदक को एक मास के भीतर ऐसी आपत्तियों का निराकरण करने का अवसर दिया जाये जो बोर्ड द्वारा उपदर्शित की जायें ।

परंतु यह और कि बोर्ड पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर ऐसी आपत्तियों का निराकरण करने में आवेदक को समर्थ बनाने के लिये समय बढ़ा सकेगा ।

जानकारी देना

8. (1)

बोर्ड आवेदक को ऐसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण देने के लिये निदेश दे सकेगा जो इसके द्वारा अपेक्षित किया जाये, आवेदन के प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिये ।

(2)

बोर्ड, यदि यह ऐसी वांछा करता है, आवेदक या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में निजी प्रतिनिधित्व के लिए बोर्ड के समक्ष हाजिर होने के लिए कह सकेगा ।

पात्रता के लिए शर्तें

9.

बोर्ड प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार नहीं करेगा जब तक कि आवेदक निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं करता है, अर्थात् :-

(क) आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के

अधीन कंपनी के रूप में स्थापित और रजिस्ट्रीकृत है ;

(ख) आवेदक ने, इसके संगम जापन में इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक के तौर पर सामूहिक विनिधान स्कीम का प्रबंधन विनिर्दिष्ट किया हो ;

(ग) आवेदक का शुद्ध-मूल्य पाँच करोड़ रुपये से अन्यून का है;

परंतु यह कि आवेदन करने के समय आवेदक के पास तीन करोड़ रुपये का न्यूनतम शुद्ध-मूल्य होगा जो रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर पाँच करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया जायेगा

(घ) आवेदक ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है ;

(ङ) आवेदक के पास इन विनियमों के उपबंध के अनुसार सामूहिक विनिधान स्कीम का प्रचालन करने में इसे समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना है ;

(च) आवेदक के निदेशक या मूल कार्मिक संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त वृत्तिक अनुभव रखने वाले ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों से गठित होंगे और नैतिक अधमता में अंतर्वलित होने वाले अपराध के लिए या किसी आर्थिक अपराध के लिए या किन्हीं प्रतिभूति विधियों के अतिक्रमण के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराये गये हैं ;

(छ) ऐसी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के निदेशकों का कम से कम पचास प्रतिशत उन व्यक्तियों से गठित होगा जो स्वतंत्र हैं

और प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उन व्यक्तियों से सहयुक्त नहीं हैं जिनका सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी पर नियंत्रण है ;

- (ज) किसी व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आवेदक से संबद्ध को भूतकाल में अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण नामंजूर न किया गया हो ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड विचार करेगा क्या, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, आवेदक से संबद्ध किसी व्यक्ति का प्रमाणपत्र के लिए पूर्वतन आवेदन बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिया गया है या अधिनियम या अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में से किसी अथवा विनियमों में से किसी के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है ।

- (झ) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के बोर्ड में, निदेशकों में से कम से कम एक, जो सेवानिवृत्ति के अध्यक्षीन नहीं है, न्यासी का प्रतिनिधि है ;

- (ञ) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी किसी सामूहिक विनिधान स्कीम की न्यासी नहीं है ।

- (ट) यदि आवेदक विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम है, यह इन विनियमों के अध्याय IX के उपबंधों का अनुपालन करता है ।

प्रमाणपत्र प्रदान करना

10. (1) बोर्ड, आवेदन की प्राप्ति पर और समाधान हो जाने पर कि आवेदक विनियम 9 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करता है, आवेदक को दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस संदत्त करने

की अपेक्षा कर सकेगा ।

- (2) रजिस्ट्रीकरण फीस की प्राप्ति पर, बोर्ड प्ररूप ख में प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो विनिधानकर्ताओं के हित में हैं और जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ।

अनुपालन किये जाने के लिये 11.
निबंधन और शर्तें

विनियम 10 के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा, अर्थात् :-

- (क) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी का कोई निदेशक किसी अन्य सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी में निदेशक नहीं होगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विनियम 9 के खंड (छ) में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक न हो और सामूहिक विनिधान कंपनियों जिसका ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र निदेशक है, के बोर्ड का अनुमोदन अभिप्राप्त न किया गया हो ;
- (ख) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी बोर्ड को पहले दी गयी जानकारी या विशिष्टियों में, जो इसके द्वारा प्रदान किये गये प्रमाणपत्र से संबंधित है, किसी तात्त्विक तब्दीली की तत्क्षण सूचना देगी ;
- (ग) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के निदेशक की नियुक्ति न्यासी के पूर्विक अनुमोदन से की जायेगी ;
- (घ) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगी ;
- (ङ) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के नियंत्रक हित में कोई परिवर्तन बोर्ड, न्यासी और स्कीम की यूनिट पूँजी के अभिहित मूल्य का कम से कम आधा

धारण करने वाले यूनिट धारकों का पूर्विक अनुमोदन अभिप्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

- (च) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी व्यथित विनिधानकर्ता से शिकायत की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठायेगी ।

प्रक्रिया जहाँ रजिस्ट्रीकरण 12. (1) प्रदान नहीं किया जाता है

जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिये विनियम 4 के अधीन किया गया आवेदन विनियम 9 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है, बोर्ड आवेदक को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा और आवेदक को इसकी सूचना दे सकेगा ।

- (2) आवेदक को विनिश्चय बोर्ड द्वारा ऐसे विनिश्चय के 30 दिनों के भीतर उसमें उन आधारों का कथन करते हुए संसूचित किया जायेगा जिन पर आवेदन नामंजूर किया गया है ।

अध्याय III

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के कारबार क्रियाकलाप और बाध्यताएँ

कारबार क्रियाकलापों पर 13.
निर्बंधन

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी :

- (क) स्कीम के प्रबंधन से भिन्न किसी क्रियाकलाप का जिम्मा नहीं लेगी ;
- (ख) किसी स्कीम के न्यासी के रूप में कार्य नहीं करेगी ;
- (ग) प्रतिभूतियों में विनिधान करने के प्रयोजन के लिये कोई स्कीम चालू नहीं करेगी ;
- (घ) इसके द्वारा चालू की गयी किन्हीं स्कीमों में विनिधान नहीं करेगी ।

परंतु यह कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी इसकी स्वयं की स्कीम में विनिधान कर सकेगी,

- (i) यदि यह स्कीम के प्रस्ताव दस्तावेज में विनिधान करने के इसके आशय का प्रकटीकरण करती है, और
- (ii) उस स्कीम में इसके विनिधान पर कोई फीस प्रभारित नहीं करती है ।

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी 14.
की बाध्यताएँ

प्रत्येक सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी :

- (क) यूनिट धारकों की ओर से स्कीम की निधियों या संपत्तियों का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगी ;

- (ख) सभी युक्तियुक्त कदम उठायेगी और सम्यक् तत्परता बरतेगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम का प्रबंध इन विनियमों, प्रस्ताव दस्तावेज और न्यास विलेख के उपबंधों के अनुसार किया जाता है ।
- (ग) स्कीम की आस्तियों और निधियों के प्रबंधन में सम्यक् तत्परता और सतर्कता बरतेगी ;
- (घ) इसके कर्मचारियों या व्यक्तियों जिनकी सेवाएँ इसके द्वारा ली गयी हैं द्वारा कार्यों या लोपों के कार्यों के लिये उत्तरदायी होगी ;
- (ङ) कार्य या लोपों के इनके कार्यों के लिये यूनिटधारकों के प्रति दायी रहेगी, किसी संविदा या करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ;
- (च) स्कीम से संबंधित इसके सहयुक्तों, या उनके नातेदारों के साथ या की माफ़त कोई संव्यवहार करने में अक्षम होगी :
- परंतु यह कि यदि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी स्कीम से संबंधित कोई संव्यवहार इसके सहयुक्तों में से किसी के साथ करती है, तो उस प्रभाव की रिपोर्ट तुरंत न्यासी को और बोर्ड को भेज दी जायेगी ।
- (छ) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं की नियुक्ति करेगी ;
- (ज) तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगी ;

- (झ) इसके द्वारा प्राप्त समस्त धनों के लिए रसीदें देगी और प्रत्येक मास बोर्ड को रिपोर्ट देगी, विशिष्टतः प्राप्तिओं और भुगतानों की ;
- (ञ) प्रत्येक तीन मास में कम से कम दो बार स्कीम के कामकाज पर विचार करने के लिए निदेशक बोर्ड की बैठक आयोजित करेगी ;
- (ट) सुनिश्चित करेगी कि इसके अधिकारी या कर्मचारी अपने ओहदे या जानकारी का अनुचित उपयोग, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभ के अभिलाष हेतु या स्कीम का अहित कारित करने हेतु नहीं करते हैं ।
- (ठ) स्कीम की संपत्ति के प्रति यथोचित बीमा अभिप्राप्त करेगी ;
- (ड) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों, निदेशों, परिपत्रों और अनुदेशों का पालन करेगी जो बोर्ड द्वारा समय समय पर, सामूहिक विनिधान स्कीमों के विषय पर जारी किए जाएँ ।

जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत 15. (1) करना

- (1) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी इसके क्रियाकलापों और इन विनियमों के अनुपालन के संबंध में स्थिति पर त्रैमासिक रिपोर्टें (अर्थात् मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर की समाप्ति पर) तैयार करेगी और उसे प्रत्येक तिमाही के अवसान के एक मास के भीतर न्यासियों को प्रस्तुत करेगी ।
- (2) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी न्यासी और बोर्ड के पास -

(क) इसके सभी निदेशकों की विशिष्टियाँ अन्य कंपनियों में उनके हित के साथ उनकी नियुक्ति के पंद्रह दिनों के भीतर ; और

(ख) निदेशकों के हितों में कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर

दाखिल करेगी ।

(3) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा की प्रति और वार्षिक अंकन रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण की प्रति यूनिट धारकों को वित्तीय वर्ष के बंद होने से दो मास के भीतर देगी ।

(4) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी बोर्ड और न्यासी को स्कीम के कामकाज से सरोकार रखने वाली ऐसी जानकारी और दस्तावेज देगी जो उनके द्वारा अपेक्षित की जाये।

अध्याय IV

न्यासी और उनकी बाध्यताएँ

- | | | | |
|--|-----|------|---|
| रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला न्यास विलेख | 16. | (1) | स्कीम न्यास के रूप में गठित होगी और न्यास की लिखत ऐसी लिखत में नामित न्यासियों के पक्ष में सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा निष्पादित भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत विलेख के रूप में होगी । |
| न्यासियों की नियुक्ति | (2) | | सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी न्यासी की नियुक्ति करेगी जो यूनिट धारकों के फायदे के लिए स्कीम की आस्तियाँ धारण करेगा । |
| न्यास विलेख की विषय-वस्तु | 17. | (1) | न्यास विलेख में ऐसे खंड जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और ऐसे अन्य खंड जो यूनिट धारकों के हित सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं अंतर्विष्ट होंगे । |
| | | (2) | किसी न्यास विलेख में ऐसा खंड अंतर्विष्ट नहीं होगा जिसका प्रभाव- |
| | | (i) | किसी स्कीम या यूनिट धारकों के संबंध में सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की बाध्यताओं और दायित्वों को सीमित करने या निर्वापित करने ; या |
| | | (ii) | यूनिट धारकों को उनके उपेक्षा के कार्यों या कार्यों अथवा लोपों के कार्यों द्वारा कारित हानि या नुकसान के लिए न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को क्षतिपूर्ति करने |
| | | | का है । |

न्यासी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता 18.

- (1) केवल भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के अधीन डिबेंचर न्यासी के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामूहिक विनिधान स्कीम के न्यासियों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होंगे।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति न्यासी के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये पात्र नहीं होगा, यदि वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उन व्यक्तियों से सहयुक्त है जिनका सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी पर नियंत्रण है।

- (2) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी बोर्ड को उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त न्यासियों की बाबत प्ररूप ग में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ देगी।

दोषी न पाये गये न्यासी की नियुक्ति 19.

कोई भी व्यक्ति स्कीम के न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि -

- (क) वह प्रतिभूति विधियों के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है या
- (ख) बोर्ड या किसी प्राधिकरण ने जिसको बोर्ड ने इसकी शक्ति प्रत्यायोजित की हो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध के अतिक्रमण के लिए अधिनियम के अधीन आदेश पारित किया हो।

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के साथ करार 20.

- (1) न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी स्कीम संपत्ति का प्रबंध करने के लिए करार करेंगे।

- (2) स्कीम संपत्ति का प्रबंध करने के लिए करार में ऐसे खंड जो पाँचवीं अनुसूची में

विनिर्दिष्ट हैं और ऐसे अन्य खंड जो स्कीम के उद्देश्यों की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं अंतर्विष्ट होंगे ।

न्यासी के अधिकार और 21.
बाध्यताएँ

(1) न्यासी के पास :-

(क) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से ऐसी जानकारी जो न्यासी द्वारा आवश्यक मानी जाती है अभिप्राप्त करने

(ख) स्कीम से संबंधित लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने

का अधिकार होगा ।

(2) न्यासी सुनिश्चित करेगा कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी :

(क) के पास आवश्यक कार्यालय अवसंरचना है;

(ख) ने स्कीमों के लिए सभी मूल कार्मिक जिनके अन्तर्गत प्रबंधक हैं नियुक्त किये हैं और उनके बायो-डाटा प्रस्तुत किए हैं जिसमें स्कीमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएँ और सुसंगत क्षेत्रों में पिछला अनुभव अंतर्विष्ट होगा ;

(ग) ने स्कीम के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों की सूची से लेखापरीक्षक नियुक्त किये हैं;

(घ) ने अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए और विनिधानकर्ता शिकायतों को दूर करने के लिए अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है ;

- (ड) ने निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता नियुक्त किया है;
- (च) ने अनुपालन निर्देशिका तैयार की है और आंतरिक नियंत्रण तंत्र जिनके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियाँ हैं परिकल्पित किये हैं ;
- (छ) ने स्कीम की आस्तियों के लिए यथोचित बीमा कराया है ;
- (ज) ने कंपनी के किन्हीं सहयुक्तों को कोई अनुचित या अक्रह्य लाभ नहीं दिया है या सहयुक्तों में से किसी के साथ किसी प्रकार से यूनिट धारकों के हित के लिए हानिकर व्यवहार नहीं किया है ;
- (झ) ने न्यास विलेख, इन विनियमों और स्कीम(मों) के प्रस्ताव दस्तावेज के उपबंधों के अनुसार स्कीम प्रवर्तित नहीं की है ;
- (ञ) ने केवल स्कीमों के प्रबंध करने के क्रियाकलाप का जिम्मा लिया है ;
- (ट) ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं कि एक स्कीम के विनिधानकर्ताओं के हित का समझौता किसी अन्य स्कीम के विनिधानकर्ताओं के हित के संप्रवर्तन के उद्देश्य के साथ नहीं किया जाता है ;
- (ठ) के पास सतत आधार पर न्यूनतम शुद्ध-मूल्य है और बोर्ड को किसी कमी की तुरंत सूचना देगी ;
- (ड) विपणन अभिकर्ताओं को पैनलित करने में और उनके क्रियाकलापों का अनुश्रवण

करने में तत्पर रही है ।

- (3) जहाँ न्यासी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि स्कीम के कारबार का संचालन इन विनियमों, न्यास विलेख और स्कीम के प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार नहीं है, न्यासी तत्क्षण ऐसे उपचारी कदम उठायेगा जो आवश्यक हैं और बोर्ड को की गई कार्रवाई की तुरंत सूचना देगा ।
- (4) न्यासी अपनी-अपनी स्कीमों की निधियों और संपत्ति, के लिए जवाबदार होगा और, का अभिरक्षक होगा और इन विनियमों और न्यास विलेख के उपबंधों के अनुसार यूनिट धारकों के फायदे के लिए न्यास में उन्हें धारण करेगा ।
- (5) न्यासी स्कीम को संदत्त की जाने वाली देय किसी आय की गणना के लिए और यूनिट धारकों को स्कीम में प्राप्त किसी आय के लिए भी उत्तरदायी होगा ।
- (6) न्यासी यूनिट धारकों का अधिवेशन बुलायेगा -
 - (क) जब कभी यूनिट-धारकों के हित में बोर्ड द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो ; या
 - (ख) जब कभी किसी स्कीम की यूनिट पूँजी के अभिहित मूल्य का कम से कम दसवाँ धारण करने वाले यूनिट धारकों द्वारा की गयी अध्यपेक्षा पर ऐसा करना अपेक्षित हो ; या
 - (ग) जब किसी स्कीम के मूलभूत लक्षणों में कोई परिवर्तन जो यूनिट धारकों के हित को प्रभावित करता है कार्यान्वित किये जाने के लिए प्रस्तावित है ।

परंतु यह कि कोई ऐसा परिवर्तन कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जब तक कि स्कीम की यूनिट पूँजी के अभिहित मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई धारण करने वाले यूनिट धारकों की सहमति अभिप्राप्त नहीं हो जाती है ।

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजनों के लिए “मूलभूत लक्षणों” से स्कीम का विनिधान उद्देश्य और निबंधन अभिप्रेत हैं।

(7) न्यासी :

(क) त्रैमासिक आधार पर (अर्थात् मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर की समाप्ति तक) प्रत्येक वर्ष सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा कार्यान्वित सभी क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन करेगा ।

(ख) निर्गम रजिस्ट्रारों और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं से संबंधित सभी सेवा संविदाओं का कालिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा और स्वयं का समाधान करेगा कि ऐसी संविदाएँ यूनिट धारकों के हित में ऋजु और युक्तियुक्त हैं ।

(ग) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा प्राप्त विनिधानकर्ता शिकायतों और उनके दूर किये जाने का पुनर्विलोकन करेगा ।

(8)(i) न्यासी सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी का शुद्ध-मूल्य उस प्रकार से अभिनियोजित नहीं है जो यूनिटधारकों के हित के लिए हानिकर है ।

- (ख) प्रत्येक स्कीम की संपत्ति स्कीम संपत्ति के रूप में स्पष्ट तौर पर पहचानी जा सकने वाली है और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की संपत्ति और किसी अन्य स्कीम की संपत्ति से पृथक्कृत: धारित है ।
- (ग) अनापत्ति या निराक्षेप प्रमाणपत्र, ऐसे प्राधिकारी से स्कीम की संपत्ति से संबंधित संव्यवहारों की बाबत अभिप्राप्त कर लिया है जो ऐसा अनापत्ति या निराक्षेप प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सक्षम है ।
- (ii) न्यासी तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा ।
- (9) न्यासी बोर्ड को त्रैमासिक आधार पर (मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर की समाप्ति तक) प्रत्येक वर्ष -
- (क) स्कीम के क्रियाकलापों पर रिपोर्ट;
- (ख) प्रमाणपत्र यह कथन करते हुए कि न्यासी ने स्वयं का समाधान कर लिया है कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के और विभिन्न स्कीमों के कार्यकलाप इन विनियमों और प्रत्येक स्कीम के विनिधान उद्देश्य के अनुसार संचालित हैं देगा ।
- (10) न्यासी :-
- (क) बोर्ड के पास पैनलित लेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संपरीक्षित की जाने वाली स्कीमों के लाभ और हानि लेखा और तुलनपत्र
- (ख) अंकन एजेंसी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंकन की जाने वाली प्रत्येक स्कीम

(ग) साख निर्धारण एजेंसी द्वारा रेटिंग की गयी स्कीम

कारित करेगा ।

(11) स्कीम के कार्यकलाप पर चर्चा करने के लिए न्यासियों का अधिवेशन वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तीन मास में कम से कम दो बार आयोजित किया जायेगा ।

(12) न्यासी इन विनियमों के किसी भंग की रिपोर्ट बोर्ड को देगा और, यूनिट धारकों के हितों पर तात्त्विक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, पड़ने की संभावना हो यथाशक्य उन्हें भंग का ज्ञान होता है ।

(13) न्यासी सुनिश्चित करेगा कि -

(क) स्कीम की फीसों और व्यय नौवी अनुसूची के भाग-I में यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हैं ;

(ख) स्कीमों के लेखे नौवी अनुसूची के भाग-II में यथा विनिर्दिष्ट लेखा मानों के अनुसार तैयार किये जाते हैं ;

(ग) स्कीम के लेखे नौवी अनुसूची के भाग-III में यथा विनिर्दिष्ट तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा के रूपविधान का अनुपालन करते हैं ।

न्यासिता का पर्यवसान

22. (1) न्यासी की न्यासिता समाप्त हो जायेगी -

(क) यदि न्यासी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के अधीन न्यासी नहीं रहता है ; या

(ख) यदि न्यासी परिसमाप्त किये जाने के अनुक्रम में है ; या

(ग) यदि स्कीम की यूनिट पूँजी के अभिहित मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई धारण करने वाले यूनिट धारक न्यासी को हटाने के लिए संकल्प पारित करते हैं और बोर्ड ऐसा संकल्प अनुमोदित करता है ; या

(घ) यदि यूनिट धारकों के हित में, बोर्ड, ऐसे कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किए जाएँगे उनके द्वारा किए गए अधिनियम या इन विनियमों के किसी अतिक्रमण के लिए न्यासी को हटाने का विनिश्चय करता है ; या

परंतु यह कि न्यासी को इस खंड के अधीन कार्रवाई किए जाने के पूर्व सुनवाई का उचित अवसर दिया जायेगा ;

(ङ) यदि न्यासी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी पर न्यासी के रूप में न बने रहने के इसके आशय को अभिव्यक्त करते हुए तीन मास से अन्यून की सूचना की तामील करता है ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन न्यासिता के पर्यवसान पर, अन्य न्यासी, विनियम 18 के अधीन नियुक्त किये जाने के लिए पात्र, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन नये न्यासी की नियुक्ति, उस तारीख से तीन मास के भीतर पूरी की जायेगी जिसको पूर्वतन न्यासिता समाप्त हुई थी ।

(4) बोर्ड विनियम 18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को न्यासी

के रूप में नियुक्त कर सकेगा यदि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी उप-विनियम (2) और (3) के अधीन न्यासी नियुक्त करने में असफल रहती है ।

- (5) उप-विनियम (3) और (4) के अधीन नियुक्त न्यासी उन सभी दस्तावेजों में न्यासी के रूप में प्रतिस्थापित हो जाएगा जिनमें इस प्रकार हटाया गया न्यासी पक्षकार था ।
- (6) बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति स्कीम को परिसमाप्त करने के लिए सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को निदेश देने वाले आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करेगा ।
- (7) विनियम 16 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में न्यास विलेख सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा इस प्रकार नियुक्त न्यासी के पक्ष में निष्पादित किया जायेगा और ऐसी नियुक्ति की तारीख से, न्यासी विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सभी अधिकारों और कर्तव्यों के अध्वधीन होंगे ।
- (8) इस प्रकार हटाया गया न्यासी ऐसी तारीख से न्यास विलेख के अधीन बाध्यताओं के अनुपालन से सेवोन्मुक्त कर दिया जायेगा किंतु ऐसे हटाये जाने के पूर्व उनके द्वारा की गयी किसी कार्रवाई के लिए दायी रहेगा ।

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी 23.
के साथ करार का समापन

- (1) न्यासी द्वारा सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के साथ किया गया विनियम 20 में निर्दिष्ट करार समाप्त किया जा सकेगा -
- (क) यदि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के

अनुसार परिसमाप्त किये जाने के अनुक्रम में है या ;

- (ख) यदि स्कीम की यूनिट पूँजी के अभिहित मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई धारण करने वाले यूनिट धारक सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के साथ करार समाप्त करने के लिए संकल्प पारित करते हैं और बोर्ड का पूर्विक अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया गया हो, या
- (ग) यदि यूनिट धारकों के हित में बोर्ड या न्यासी, बोर्ड का पूर्विक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के साथ करार समाप्त करने का विनिश्चय करते हैं ।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन करार के समापन पर, अन्य सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत, ऐसे समापन की तारीख से तीन मास के भीतर न्यासी द्वारा नियुक्त की जायेगी ।
- (3) इस प्रकार हटायी गयी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी न्यासी के विवेकाधिकार पर ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखेगी या न्यासी स्वयं सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के रूप में ऐसे समय तक कार्य कर सकेगा जब तक नयी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी नियुक्त नहीं हो जाती ।
- (4) उप-विनियम (2) के अधीन नियुक्त सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी उन सभी दस्तावेजों में पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित हो जायेगी जिनमें इस प्रकार हटायी गयी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी पक्षकार थी ।

- (5) इस प्रकार हटायी गयी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी ऐसे समापन के होते हुए भी कार्यों और लोप के सभी कार्यों के लिए दायी रहेगी ।
- (6) यदि, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी में से कोई भी, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, तीन मास की अतिरिक्त कालावधि के भीतर सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के रूप में नियुक्त किये जाने की सहमति नहीं देती है, तब न्यासी स्कीम परिसमाप्त कर सकेगा ।
- (7) स्कीम संपत्ति का प्रबंध करने के लिए करार विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सभी अधिकारों और कर्तव्यों के अध्यधीन नयी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जायेगा ।

अध्याय V

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की स्कीमें

- स्कीमें चालू करने के लिए प्रक्रिया 24. (1) कोई स्कीम सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा चालू नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी स्कीम न्यासी द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाती ।
- रेटिंग (2) कोई स्कीम सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा साख निर्धारण एजेंसी से रेटिंग अभिप्राप्त किये बिना चालू नहीं की जायेगी ।
- अंकन (3) कोई स्कीम सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा अंकन एजेंसी द्वारा स्कीम का अंकन कराये बिना चालू नहीं की जायेगी ।
- सीमित अवधि वाली स्कीम और स्कीम अवधि (4) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी :
- (क) केवल सीमित अवधि वाली स्कीमें चालू करेगी ;
- (ख) स्कीमों की अवधि तीन कैलेंडर वर्षों से न्यून की नहीं होगी ।
- बीमा (5) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी स्कीम संपत्ति के संरक्षण के लिए यथोचित बीमा पॉलिसी अभिप्राप्त करेगी ।
- कोई गारंटीकृत प्रतिलाभ नहीं 25. कोई स्कीम गारंटीकृत या आश्वासित प्रतिलाभों का उपबंध नहीं करेगी ।
- परंतु यह कि उपदर्शी प्रतिलाभ केवल प्रस्ताव दस्तावेज में उपदर्शित किया जा

सकेगा, यदि वह अंकन एजेंसी द्वारा निर्धारित है और मुद्रा रूप में अभिव्यक्त है।

- प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण** 26. (1) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी कोई स्कीम चालू करने के पूर्व बोर्ड के पास विनियम 24 के उप-विनियम (1) में यथा निर्दिष्ट स्कीम के प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति दाखिल करेगी और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दाखिल करने की फीस संदत्त करेगी।
- (2) प्रस्ताव दस्तावेज में ऐसी जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- (3) प्रस्ताव दस्तावेज में स्कीम का सही और ऋजु चित्र और संसूचित विनिश्चय करने में विनिधानकर्ताओं को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त प्रकटीकरण भी अंतर्विष्ट होंगे।
- (4) बोर्ड विनिधानकर्ताओं के हित में सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से प्रस्ताव दस्तावेज में ऐसे उपांतरण करने की अपेक्षा कर सकेगा जो यह ठीक समझे।
- (5) यदि बोर्ड द्वारा दाखिल करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर प्रस्ताव दस्तावेज में कोई उपांतरण नहीं सुझाये जाते हैं, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी जनता को प्रस्ताव दस्तावेज जारी कर सकेगी।

विज्ञापन सामग्री

27. (1) प्रत्येक स्कीम की बाबत विज्ञापन सातवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विज्ञापन संहिता के अनुरूप होंगे।
- (2) प्रत्येक स्कीम के लिए विज्ञापन विनिधान उद्देश्यों के अतिरिक्त, स्कीम संपत्ति के

			मूल्यांकन की पद्धति और कालिकता का प्रकटीकरण करेगा ।
अंकन एजेंसी	28.		अंकन एजेंसी जिसकी अंकन रिपोर्ट प्रस्ताव दस्तावेज का भाग होती है और जिसने प्रस्ताव दस्तावेज में अंकन रिपोर्ट के सम्मिलित होने के लिए लिखित सहमति दी है अंकन रिपोर्ट में किसी उस कथन के लिए दायी होगी जो भ्रामक, गलत या मिथ्या है ।
भ्रामक कथन	29.	(1)	प्रस्ताव दस्तावेज और विज्ञापन सामग्रियाँ भ्रामक नहीं होंगी या में कोई वह कथन या राय अंतर्विष्ट नहीं होगी जो गलत या मिथ्या हैं।
		(2)	जहाँ प्रस्ताव दस्तावेज या विज्ञापन के अंतर्गत कोई कथन या राय है जो गलत या मिथ्या या भ्रामक हैं, प्रत्येक व्यक्ति -
		(i)	जो प्रस्ताव दस्तावेज के जारी करने के समय सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी का निदेशक है ;
		(ii)	जिसने प्रस्ताव दस्तावेज जारी किया हो और अधिनियम के अधीन दंडनीय होगा जब तक कि वह या तो यह साबित नहीं करता कि कथन या राय तत्वहीन थी या यह कि उसके पास प्रस्ताव दस्तावेज या विज्ञापन के जारी करने के समय विश्वास करने का यह युक्तियुक्त आधार था कि कथन सही था ।
प्रस्ताव कालावधि	30.		कोई स्कीम 90 दिनों से अधिक के लिए अभिदान के लिए नहीं खुलेगी ।
यूनिटों का आबंटन और धन के प्रतिदाय	31.	(1)	सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी प्रस्ताव दस्तावेज में, -

(क) न्यूनतम और अधिकतम अभिदान रकम जो यह स्कीम के अधीन जुटाना चाहती है; और

(ख) अत्याभिदान के मामले में अत्याभिदत्त रकम के आबंटन की प्रक्रिया

विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी आवेदकों को आवेदन धन का प्रतिदाय करेगी, -

(i) यदि स्कीम उप-विनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट न्यूनतम अभिदान रकम प्राप्त करने में असफल रहती है।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन प्रतिदेय किसी रकम का प्रतिदाय अभिदाय सूची के बंद होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर, आवेदकों को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा और "पा/खाता" चिह्नांकित चेक या माँगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

(4) उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रकमों का प्रतिदाय करने में असफल रहने की दशा में, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी आवेदकों को अभिदान सूची के बंद होने की तारीख से छह सप्ताह के अवसान पर प्रतिवर्ष पंद्रह प्रतिशत की दर पर ब्याज संदत्त करेगी।

यूनिट प्रमाणपत्र

32.

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी आवेदक को जिसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो, यथासंभव शीघ्र किंतु अभिदान सूची के बंद होने की तारीख से छह सप्ताह के अपश्चात् यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगी।

परंतु यह कि यदि यूनिटों का निर्गमन निक्षेपागार की मापत किया जाता है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 और निक्षेपागार की उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार यूनिट प्रमाणपत्र के बदले में रसीद जारी की जायेगी।

यूनिटों का अंतरण

33. (1) स्कीम के अधीन जारी यूनिट प्रमाणपत्र निर्बाध रूप से अंतरणीय होगा।

(2) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, सुसंगत यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण की लिखत के पेश करने पर, अंतरण को रजिस्टर करेगी और ऐसे पेश किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अंतरिती को यूनिट प्रमाणपत्र लौटायेगी।

परंतु यह कि यदि यूनिटें निक्षेपागार में धारित हैं ऐसी यूनिटें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 और निक्षेपागार की उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार अंतरणीय होंगी।

पृथक् खाते में रखा जाने वाला धन और धन का उपयोग

34. (1) प्राप्त अभिदान रकम स्कीम के नाम में पृथक् बैंक खाते में रखी जायेगी और -

(क) केवल, प्रस्ताव दस्तावेज में यथा कथित, जनता से प्राप्त की हुई, न्यूनतम अभिदान रकम के संबंध में न्यासी को निर्गम रजिस्ट्रारों और शेयर अंतरण अभिकर्ता से कथन प्राप्त होने के पश्चात् ही यूनिटों के आबंटन के प्रति समायोजन के लिये, या

(ख) धन के प्रतिदाय के लिए यदि न्यूनतम अभिदान रकम, प्रस्ताव दस्तावेज में यथा कथित, प्राप्त न की गयी हो या अत्याभिदान के मामले में

उपयोग की जायेगी ।

- (2) प्रस्ताव दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अभिदान रकम, परियोजना जिसके लिए स्कीम चालू की जा रही है के पूरा होने के लिए आवश्यक, न्यूनतम रकम, अंकन एजेंसी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, से कम नहीं होगी ।
- (3) स्कीम के खाते में जमा धन स्कीम के और प्रस्ताव दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगा ।
- (4) स्कीम के खाते में पड़ी उपयोग न की गयी कोई रकम प्रस्ताव दस्तावेज में यथा प्रकटीकृत रीति से विनिहित की जायेगी ।

निधियों के विनिधान और 35.
पृथक्करण

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी :

- (क) प्रस्ताव दस्तावेज में यथा प्रकटीकृत स्कीम के उद्देश्य से भिन्न प्रयोजनों के लिए स्कीम की निधियाँ विनिहित नहीं करेगी ।
- (ख) विभिन्न स्कीमों की स्कीम आस्तियों का पृथक्करण करेगी ।
- (ग) अन्य स्कीमों में स्कीम का कॉर्पस विनिहित नहीं करेगी ।
- (घ) एक स्कीम से अन्य स्कीम में निधियाँ अंतरित नहीं करेगी ।

परंतु यह कि स्कीम संपत्ति का अंतः स्कीम अंतरण न्यासी और बोर्ड के पूर्विक अनुमोदन से स्कीम के पर्यवसान के समय अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

- | | | |
|------------------------|-----|--|
| स्कीमों का सूचीबद्धकरण | 36. | प्रत्येक स्कीम की यूनिटें प्रस्ताव दस्तावेज में यथा उल्लिखित स्टाक एक्सचेंजों में से प्रत्येक पर यूनिटों के आबंटन की तारीख के ठीक पश्चात् और स्कीम के बंद होने की तारीख से छह सप्ताह से अपश्चात् सूचीबद्ध की जायेंगी । |
|------------------------|-----|--|
-
- | | | |
|-------------------|-----|--|
| स्कीम का परिसमापन | 37. | <p>(1) स्कीम, स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर या स्कीम का प्रयोजन पूरा होने पर परिसमाप्त की जायेगी ।</p> <p>(2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्कीम-</p> <p>(क) किसी घटना के घटित होने पर जो, न्यासी की राय में, स्कीम को परिसमाप्त किये जाने के लिए अपेक्षित है और बोर्ड का पूर्विक अनुमोदन अभिप्राप्त है ; या</p> <p>(ख) यदि स्कीम की यूनिट पूँजी के अभिहित मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई धारण करने वाले स्कीम के यूनिट धारक संकल्प पारित करते हैं कि स्कीम परिसमाप्त की जाये और बोर्ड का अनुमोदन अभिप्राप्त है ; या</p> <p>(ग) यदि बोर्ड की राय में, स्कीम का जारी रहना यूनिट-धारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ; या</p> <p>(घ) यदि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की राय में, स्कीम का प्रयोजन पूरा नहीं किया जा सकता है और यह न्यासियों का और स्कीम की यूनिट पूँजी के अभिहित मूल्य का कम से कम $\frac{3}{4}$ धारण करने वाले स्कीम के यूनिट धारकों का भी अनुमोदन इस संकल्प के साथ अभिप्राप्त करती है कि स्कीम परिसमाप्त की जाये और बोर्ड का</p> |
|-------------------|-----|--|

अनुमोदन अभिप्राप्त है

परिसमाप्त भी की जा सकेगी ।

- (3) जहाँ स्कीम उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अधीन परिसमाप्त की जानी है, न्यासी स्कीम के परिसमापन में परिणत होने वाली परिस्थितियों को प्रकट करते हुए राष्ट्र व्यापी परिचालन वाले दैनिक समाचारपत्र में और उस प्रदेश की भाषा में प्रकाशित समाचारपत्र में सूचना देगा जहाँ सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी रजिस्ट्रीकृत है ।
- (4) न्यासी उस स्कीम के यूनिट धारकों के
- (क) सर्वोत्तम हित में संबद्ध स्कीम की आस्तियों का व्ययन करेगा ।
- (ख) खंड (क) के अधीन प्राप्त विक्रय की आगमों का, पहले पहल उपयोग ऐसे दायित्वों के निर्वहन हेतु किया जायेगा जो स्कीम के अधीन देय और संदेय हैं और ऐसे परिसमापन से संबद्ध व्यय की पूर्ति करने के लिए समुचित उपबंध करने के पश्चात्, अतिशेष यूनिट धारकों को उनकी यूनिट धारिता में अनुपात में संदत्त किया जायेगा ।
- (5) परिसमापन के पूरा होने पर, न्यासी बोर्ड और यूनिट धारकों को
- (क) स्कीम की आस्तियों की वसूली के लिए उठाये गये कदमों, परिसमापन के लिए व्यय और यूनिट धारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों पर रिपोर्ट और
- (ख) स्कीम के लेखापरीक्षकों से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि स्कीम की सभी आस्तियों

की वसूली कर ली गयी है और आगमों के वितरण के ब्यौरे

अप्रेषित करेगा ।

- (6) परिसमापन के समय अदावाकृत धन यदि कोई हो न्यासी द्वारा विनिधानकर्ताओं के दावों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए तीन वर्षों की कालावधि के लिए बैंक खाते में पृथक रूप से रखा जायेगा और तत्पश्चात् विनिधानकर्ता संरक्षण निधि में अंतरित किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

परिसमापन कार्यवाहियों के 38.
प्रारंभ का प्रभाव

विनियम 37 के उप-विनियम (3) के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख को और से, यथास्थिति, न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी इस प्रकार परिसमाप्त स्कीम की बाबत कोई कारबार क्रियाकलाप करना बंद कर देंगे ।

स्कीम का अस्तित्वहीन होना 39.

यदि, विनियम 37 के उप-विनियम (5) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, बोर्ड का समाधान हो जाता है कि स्कीम के परिसमापन के लिए सभी उपायों का अनुवर्तन कर लिया गया है, स्कीम अस्तित्वहीन हो जायेगी ।

अध्याय VI

साधारण बाध्यताएँ

- समुचित लेखा बहियाँ और 40. (1) प्रत्येक सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी -
अभिलेख, इत्यादि बनाये रखना
- (क) प्रत्येक स्कीम के लिए, समुचित लेखा बहियाँ, अभिलेख और दस्तावेज रखेगी और बनाये रखेगी कि इसके संव्यवहारों का स्पष्टीकरण किया जा सके और प्रत्येक स्कीम की वित्तीय स्थिति को किसी भी समय-बिंदु पर प्रकट किया जा सके और विशिष्टितया स्कीम के कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र दिया जा सके और
- (ख) बोर्ड और न्यासियों को उस स्थान की सूचना देगी जहाँ ऐसी लेखा बहियाँ, अभिलेख और दस्तावेज जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर अभिलेख हैं बनाये रखे जाते हैं।
- (2) प्रत्येक सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, प्रत्येक स्कीम के बंद होने के पश्चात् पाँच वर्षों की कालावधि के लिए, इसकी लेखा बहियों, अभिलेखों, कम्प्यूटर आँकड़ों और दस्तावेजों का बनाये रखना और परिरक्षण करना जारी रखेगी।
- वित्तीय वर्ष 41. सभी स्कीमों के लिए वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा।
- वारंटों और आगमों का प्रेषण 42. सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी,
- (क) यूनिट धारकों को अंतरिम प्रतिलाभों की घोषणा के 42 दिनों के भीतर वारंट प्रेषित करेगी।

- (ख) स्कीम के बंद होने या परिसमापन के 30 दिनों के भीतर मोचन आगमें प्रेषित करेगी ।
- लेखा विवरण और वार्षिक रिपोर्ट 43. (1) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी :
- (क) नौवी अनुसूची के भाग-I में यथा विनिर्दिष्ट स्कीम की बाबत व्यय या फीसों पर अधिकतम सीमाएँ नहीं बढ़ायेगी ।
- (ख) नौवी अनुसूची के भाग-II में यथा विनिर्दिष्ट लेखा मानों के अनुसार स्कीम के लेखे तैयार करेगी ;
- (ग) नौवी अनुसूची के भाग-III में यथा विनिर्दिष्ट तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखों के रूपविधान का अनुवर्तन करेगी ;
- (2) प्रत्येक स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बाबत तैयार किये जायेंगे।
- (3) प्रत्येक सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बंद होने की तारीख से दो मास के भीतर बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करेगी ।
- लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 44. (1) प्रत्येक स्कीम के पास उस लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण होंगे जो बोर्ड के पास पैनलित है और जो किसी प्रकार से सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के लेखापरीक्षक से सहयुक्त नहीं है।
- (2) लेखापरीक्षक न्यासी द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।
- (3) लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट न्यासी को

अग्रेषित करेगा और ऐसी रिपोर्ट स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी ।

(4) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :-

(क) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि :-

(i) उसने समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण जो, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे अभिप्राप्त कर लिये हैं ;

(ii) तुलनपत्र और राजस्व खाता उस लेखा कालावधि के लिए स्कीम, स्कीम में कार्यकलाप की स्थिति और अधिशेष या कमी जिससे तुलनपत्र या, यथास्थिति राजस्व खाता संबंधित है का सही और ऋजु चित्र देते हैं ;

(iii) लेखा विवरण नौवी अनुसूची के भाग II में यथा विनिर्दिष्ट लेखा नीतियों और मानकों के अनुसार तैयार किया गया है ;

(iv) कोई अन्य मामला जो बोर्ड की राय में महत्वपूर्ण है और स्कीमों से संबंधित है ।

स्कीम के लेखापरीक्षकों के कृत्य 45.

(1) स्कीम का लेखापरीक्षक, यथासंभव शीघ्र, बोर्ड और न्यासी को लिखित रूप में सूचित करेगा यदि उसके पास यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि विनियमों का उल्लंघन हुआ है या यदि स्कीमों में ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संचालित नहीं हैं ।

(2) स्कीम :

(क) के लेखापरीक्षक के पास सभी युक्तियुक्त

समयों पर स्कीम की बहियों तक पहुँच रखने का अधिकार होगा ; और

- (ख) का लेखापरीक्षक सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के किसी कर्मचारी से लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए जानकारी और स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

लेखापरीक्षकों का हटाया जाना 46.
या का त्यागपत्र

- (1) न्यासी, न्यासी के पूर्विक अनुमोदन के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किए जाएँगे लेखापरीक्षक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् अवचार या अदक्षता के लिए स्कीम के लेखापरीक्षक को हटा सकेगा ।

परंतु यह कि स्कीम के लिए अन्य लेखापरीक्षक की नियुक्ति न्यासी द्वारा तुरंत बोर्ड के पास पैनलित लेखापरीक्षकों से की जाती है ।

- (2) स्कीम का लेखापरीक्षक सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को और न्यासी को तीन मास की लिखित सूचना देते हुए त्यागपत्र दे सकेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट और उसके सार 47.
का प्रकाशन

- (1) स्कीम-वार वार्षिक रिपोर्ट या उसका संक्षिप्त रूप यथासंभव शीघ्र किंतु लेखों के अंतिम रूप देने की तारीख से दो कैलेंडर मास से अपश्चात् राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित किया जायेगा ।

- (2) वार्षिक रिपोर्ट में नौवी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे जो सामूहिक विनिधान स्कीम के प्रचालनों का सही और ऋजु चित्र उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं अंतर्विष्ट होंगे ।

- (3) रिपोर्ट यदि संक्षिप्त रूप में प्रकाशित है में एक टिप्पण होगा कि पूरी वार्षिक रिपोर्ट सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के प्रधान कार्यालय और सभी शाखा कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगी ।

कालिक और सतत प्रकटीकरण 48.

- (1) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी और न्यासी, ऐसे प्रकटीकरण करेंगे या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जैसी उनसे बोर्ड द्वारा करने या प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किए जाएँ ।

- (2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी स्कीम की ओर से बोर्ड को निम्नलिखित कालिक रिपोर्टें देगी, अर्थात् :

- (क) सम्यक् रूप से संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरणों की प्रतियाँ जिनके अंतर्गत प्रत्येक स्कीम की बाबत तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा हैं, वर्ष में एक बार ;

- (ख) त्रैमासिक अपरीक्षित लेखाओं की प्रति ;

- (ग) स्कीमों में से प्रत्येक के लिए शुद्ध आस्तियों में परिवर्तनों का त्रैमासिक विवरण ।

त्रैमासिक प्रकटीकरण

49.

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, स्कीम की ओर से प्रत्येक तिमाही की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर से एक मास के अवसान के पूर्व अपने अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम राष्ट्र व्यापी परिचालन वाले एक दैनिक समाचारपत्र में और उस प्रदेश की भाषा में प्रकाशित समाचारपत्र में प्रकाशित करेगी जहाँ सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी का प्रधान कार्यालय स्थित है ।

परंतु यह कि इस उप-विनियम में निर्दिष्ट त्रैमासिक अलेखापरीक्षित रिपोर्ट में विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे जो स्कीम के प्रचालनों का सही और ऋजु चित्र उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं अंतर्विष्ट होंगे ।

विनिधानकर्ताओं को
प्रकटीकरण

50.

न्यासी सुनिश्चित करेगा कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी यूनिट धारकों को ऐसे प्रकटीकरण करेगी जो उन्हें किसी मामले जिसका उनके विनिधानों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है के बारे में सूचित रखने के लिए आवश्यक हैं ।

यूनिट धारकों का अधिवेशन 51.
बुलाना, यूनिटों का अंतरण
और पारेषण

यूनिट धारकों का अधिवेशन बुलाना और साथ ही स्कीम की यूनिटों का अंतरण और पारेषण आठवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार होगा ।

अध्याय VII

निरीक्षण और लेखा-परीक्षा

बोर्ड का निरीक्षण और 52.
अन्वेषण करने का अधिकार

- (1) बोर्ड न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की लेखा बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और अवसंरचना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिये या कामकाज का अन्वेषण करने के लिये निरीक्षण अधिकारी के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिये नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :-
 - (क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा लेखा-बहियाँ इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से बनायी रखी जा रही हैं ;
 - (ख) यह अभिनिश्चित करने के लिये कि क्या न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है ;
 - (ग) यह अभिनिश्चित करने के लिये कि क्या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और रक्षोपाय पर्याप्त हैं ;
 - (ङ) विनिधानकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति से न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के क्रियाकलापों से संबंध रखने वाले किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों का अन्वेषण करने के लिये ;

निरीक्षण और अन्वेषण के पूर्व 53.
सूचना

- (1) विनियम 52 के अधीन निरीक्षण का आदेश देने के पूर्व बोर्ड यथास्थिति सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी या न्यासी को दस दिनों से अन्तून सूचना देगा।
- (2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि विनिधानकर्ताओं के हित में कोई ऐसी सूचना दिए जाने के लिए अपेक्षित नहीं है, यह, लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निरीक्षण या अन्वेषण ऐसी सूचना के बिना तुरंत किया जाये।
- (3) निरीक्षण या अन्वेषण के दौरान, न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी जिसके विरुद्ध निरीक्षण या अन्वेषण किया जा रहा है विनियम 54 में यथा उपबंधित उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिये आबद्ध होंगे।

निरीक्षण और अन्वेषण के 54.
दौरान बाध्यताएँ

- (1) यह न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी का, जिनके कामकाज निरीक्षित या अन्वेषित किये जा रहे हैं, और उसके प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी का कर्तव्य होगा, इसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसी बहियाँ, लेखे, अभिलेख, और अन्य दस्तावेज पेश करना और उसे न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के रूप में क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और जानकारी देना, जैसी निरीक्षण अधिकारी अपेक्षा करे, ऐसी युक्तियुक्त कालावधि के भीतर जो निरीक्षण अधिकारी विनिर्दिष्ट करे।
- (2) न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी निरीक्षण अधिकारी को इसके द्वारा या इसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

अधिभोगित परिसरों तक युक्तियुक्त पहुँच रखने की अनुज्ञा देंगे और न्यासी तथा सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी या ऐसे अन्य व्यक्ति के कब्जे में रखी किन्हीं बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कम्प्यूटर आँकड़ों की परीक्षा करने के लिये आवश्यक अवसंरचना भी उपलब्ध करायेंगे और दस्तावेजों या अन्य सामग्री जो निरीक्षण अधिकारी की राय में निरीक्षण के प्रयोजन के लिये सुसंगत हैं की प्रतियाँ भी उपलब्ध करायेंगे ।

बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना 55.

निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण या अन्वेषण के पूरा होने पर, बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, वह अंतरिम रिपोर्टें भी प्रस्तुत करेगा ।

निष्कर्षों, आदि की संसूचनाएँ 56. (1)

बोर्ड, विनियम 55 में निर्दिष्ट रिपोर्ट का विचार करने के पश्चात्, यथास्थिति न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को निष्कर्ष संसूचित करेगा, और उसे ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों के भीतर सुने जाने का अवसर देगा ।

(2) अधिनियम और इन विनियमों के अधीन आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने के इसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से उत्तर, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर इससे ऐसे उपचारी उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा बोर्ड इस निमित्त निदेश दे और इन विनियमों के अध्याय VIII के अधीन कार्रवाई भी आरंभ कर सकेगा ।

लेखापरीक्षक की नियुक्ति और 57. (1) व्ययों की वसूली

विनियम 52 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के पास, स्कीमों की बाबत न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की लेखा-बहियों या कामकाज का, यथास्थिति, निरीक्षण या अन्वेषण करने के लिये लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी :

परंतु यह कि इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षक के पास निरीक्षण अधिकारी की वही शक्तियाँ होंगी जो विनियम 52 में कथित हैं और विनियम 54 में सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी या न्यासी और उनके अपने-अपने कर्मचारियों की बाध्यता, इस विनियम के अधीन निरीक्षण को लागू होगी ।

बोर्ड को निरीक्षण फीस का (2) संदाय

बोर्ड ऐसे व्यय जिनके अंतर्गत लेखापरीक्षकों को संदत्त फीस है वसूल करने का हकदार होगा जो न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की लेखा-बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा उपगत किये जायें ।

अध्याय VIII

व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई के लिये प्रक्रिया

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| सक्षम प्राधिकारी | 58. | इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो सक्षम प्राधिकारी से बोर्ड का वह अधिकारी अभिप्रेत है जो प्रभाग मुख्य के दर्जे से नीचे का न हो, जिसे बोर्ड अध्याय VIII के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करता है । |
| प्रमाणपत्र का निलंबन | 59. | <p>सक्षम प्राधिकारी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर सकेगा यदि ऐसी कंपनी :-</p> <p>(क) अधिनियम और इन विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है ;</p> <p>(ख) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिये कोई जानकारी देती है जो मिथ्या या भ्रामक है या किसी तात्त्विक जानकारी को छिपाती है;</p> <p>(ग) अधिनियम या इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा संचालित किसी निरीक्षण, अन्वेषण या जाँच में सहकार नहीं करती है ;</p> <p>(घ) अधिनियम या विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहती है ;</p> <p>(ङ) विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर</p> |

करने में असफल रहती है या बोर्ड को इस निमित्त समाधानप्रद उत्तर देने में असफल रहती है जब बोर्ड द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो ।

- (ब) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के किसी उपबंध का भंग करती है
- (छ) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस संदत्त करने में असफल रहती है ;
- (ज) रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का भंग करती है ;
- (झ) सूचीबद्धकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहती है या मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में स्कीम के यूनिट सूचीबद्ध करने में असफल रहती है ।

प्रमाणपत्र का रहकरण

60.

सक्षम प्राधिकारी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को प्रदान किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, यदि -

- (क) कंपनी कपट की दोषी रही हो, या किसी आर्थिक अपराध की सिद्धदोष ठहरायी गयी हो ;
- (ख) विनियम 59 में विनिर्दिष्ट स्वरूप के व्यतिक्रमों की पुनरावृत्ति की दोषी रही हो;
- (ग) कंपनी की वित्तीय स्थिति का ऐसे विस्तार तक क्षय हुआ हो कि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इसका जारी रहना यूनिटधारकों के हित में नहीं है ।
- (घ) स्कीम संपत्ति के प्रबंध के लिये करार समाप्त हो गया हो ।

(ड) कंपनी दिवालिया या परिसमाप्त घोषित की जाती है ।

रद्दकरण या निलंबन का आदेश 61.
करने की रीति

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के विरुद्ध मक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का कोई आदेश विनियम 62 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाँच किये बिना नहीं किया जायेगा ।

परंतु यह कि निम्नलिखित मामलों में जाँच करना आवश्यक नहीं होगा :

(क) जहाँ कंपनी दिवालिया घोषित की जाती है या परिसमाप्त हो जाती है ;

(ख) जहाँ कंपनी बोर्ड को फीस संदत्त करने में असफल रहती है ;

(ग) जहाँ स्कीम संपत्ति के प्रबंधन के लिए करार समाप्त हो जाता है ;

(घ) जहाँ कंपनी बोर्ड को इसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करती है ;

(ड) जहाँ कंपनी शुद्ध-मूल्य बनाये रखने में असफल रहती है ;

(च) जहाँ स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशकों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से नीचे आ जाती है ।

परंतु यह और कि इस विनियम के प्रथम परंतुक के अधीन कोई कार्रवाई किये जाने से पूर्व सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा ।

कारण बताओ सूचना और 62.
आदेश

- (1) जहाँ विनियम 59 या 60 के अधीन कार्रवाई प्रस्तावित है, सक्षम प्राधिकारी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को, इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या इसके कारबार के मुख्य स्थान पर, उन आधारों को जिन पर इसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है उपवर्णित करते हुए और इससे सूचना की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की कालावधि के भीतर ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा ।
- (2) सक्षम प्राधिकारी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को उप-विनियम (1) के अधीन जारी इसकी सूचना के उसके उत्तर के समर्थन में निवेदन करने में इसे समर्थ बनाने के लिये सुनवाई का उचित अवसर देगा ।
- (3) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या तो वैयक्तिक रूप से या उसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की माफ़र्त हाजिर हो सकेगी ;

परंतु यह कि कोई अधिवक्ता वैयक्तिक सुनवाई में सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ;

परंतु यह और कि जहाँ अधिवक्ता बोर्ड द्वारा इस विनियम के उप-विनियम (5) के अधीन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो, कंपनी के पास अधिवक्ता की माफ़र्त अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

- (5) यदि यह आवश्यक माना जाता है, सक्षम

प्राधिकारी बोर्ड से इसका मामला प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा।

- (6) सक्षम प्राधिकारी, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के उत्तर, अभिलेख पर साक्ष्य, और वैयक्तिक सुनवाई के समय निवेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा यह ठीक समझे जिसके अंतर्गत प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का आदेश है।
- (7) उप-विनियम (6) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश स्वतः पूर्ण होगा और उसमें कथित निष्कर्षों के लिए कारण देगा जिसके अंतर्गत उस आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, के लिए न्यायोचित्य है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के 63.
निलंबन या रद्दकरण का प्रभाव

- (1) प्रमाणपत्र के निलंबन की तारीख को और से, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी निलंबन की कालावधि के दौरान कोई क्रियाकलाप करना बंद कर देगी, और इसके क्रियाकलापों से संबंधित, किन्हीं अभिलेखों, दस्तावेजों, या आस्तियों जो इसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में हों, के विषय में बोर्ड के निदेशों के अध्याधीन होगी।
- (2) प्रमाणपत्र के रद्दकरण की तारीख को और से, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, कोई क्रियाकलाप करना बंद कर देगी।

निलंबन या रद्दकरण के आदेश 64.
का प्रकाशन

विनियम 62 के उप-विनियम (6) के अधीन पारित निलंबन या रद्दकरण का आदेश, दो समाचारपत्रों में बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया जायेगा जिनमें से कम से कम एक का परिचालन राष्ट्र व्यापी होगा।

बोर्ड द्वारा निदेश

65.

बोर्ड, प्रतिभूति बाज़ार और विनिधानकर्ताओं के हितों में और इस अध्याय के अधीन कार्रवाई आरंभ करने के इसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 24 के अधीन आपराधिक अभियोजन आरंभ करना है, ऐसे निदेश दे सकेगा जैसा यह इन विनियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे, जिनके अंतर्गत, :

- (क) संबद्ध व्यक्ति से, विनिधानकर्ताओं से कोई धन संग्रहित न करने या कोई स्कीम चालू न करने की अपेक्षा करने वाले ;
- (ख) संबद्ध व्यक्ति को इन विनियमों के अतिक्रमण में अर्जित स्कीम की संपत्तियों में से किसी के व्ययन से प्रतिषिद्ध करने वाले ;
- (ग) संबद्ध व्यक्ति से स्कीम की आस्तियों का उस रीति से जैसी निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये व्ययन करने की अपेक्षा करने वाले ;
- (घ) संबद्ध व्यक्ति से स्कीम के अधीन संग्रहित, किसी धन या आस्तियों का प्रतिदाय संबद्ध विनिधानकर्ताओं को अपेक्षित ब्याज या अन्यथा के साथ करने की अपेक्षा करने वाले ;
- (ङ) संबद्ध व्यक्ति को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए पूँजी बाज़ार में प्रचालन से या पूँजी बाज़ार में पहुँच से प्रतिषिद्ध करने वाले

निदेश हैं ।

मध्यवर्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

66.

बोर्ड अधिनियम की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाले

मध्यवर्ती के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के लिये कार्रवाई आरंभ कर सकेगा जो इसके कृत्यों के पालन में सम्यक् तत्परता बरतने में असफल रहता है या इन विनियमों के अधीन इसकी बाध्यताओं की अनुपालना करने में असफल रहता है:

परंतु यह कि कोई ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मध्यवर्ती को लागू विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाता है।

केंद्रीय सरकार को अपील

67.

इन विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी या बोर्ड के :

- (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करने वाले ; या
- (ख) ऐसा प्रमाणपत्र रद्द करने वाले ; या
- (ग) विनियम 65 के अधीन निदेश जारी करने वाले

आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (केंद्रीय सरकार को अपील) नियम, 1993 के अनुसार।

अध्याय IX

विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीमें

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त
करने के लिए विद्यमान स्कीमें

68. (1) कोई व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ के समय सामूहिक विनिधान स्कीम का प्रचालन कर रहा हो विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम समझा जायेगा और इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन भी करेगा।

स्पष्टीकरण : 'सामूहिक विनिधान स्कीम का प्रचालन' पद के अंतर्गत विनिधानकर्ताओं जिन्होंने स्कीम में अभिदान किया हो के साथ किये गये विभिन्न दस्तावेजों में जिम्मा ली गयी बाध्यताओं को निभाना होगा।

- (2) विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम विनियम 5 में विनिर्दिष्ट रीति से बोर्ड को आवेदन करेगी।
- (3) उप-विनियम (2) के अधीन किये गये आवेदन पर निम्नलिखित रीति में से किसी से कार्यवाही की जायेगी :

(क) विनियम 71 के उप-विनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हुए;
(ख) विनियम 10 के अधीन बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए;
(ग) विनियम 12 के अधीन बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर करते हुए।

रजिस्ट्रीकरण प्रदान किये जाने तक 69
किसी स्कीम को चालू न किया जाना

कोई विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम कोई नयी स्कीम चालू नहीं करेगी या विनिधानकर्ताओं से विद्यमान स्कीम के अधीन भी कोई धन नहीं जुटायेगी, जब तक कि विनियम 10 के अधीन बोर्ड द्वारा इसको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं

किया जाता है।

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने
के लिए आवेदन पर विचार करना

70

(1)

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र माने जाने के प्रयोजन के लिए आवेदक बोर्ड का समाधान करेगा कि

(क) आवेदक की स्कीमें सामूहिक विनिधान स्कीमों के स्वरूप की हैं;

(ख) आवेदक के कार्यकलाप विद्यमान विनिधानकर्ताओं के हित के लिए हानिकर रीति से संचालित नहीं किये जा रहे हैं;

(ग) आवेदक के पास आवेदन करते समय कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशक हैं;

स्पष्टीकरण : "स्वतंत्र निदेशकों" से वे निदेशक अभिप्रेत हैं जो विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम प्रचालित करने वाले व्यक्तियों के सहयुक्त नहीं हैं।

(घ) इससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध, किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया गया है;

2) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए बोर्ड, अन्य बातों के साथ, आवेदक की स्कीमों, लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा

3) बोर्ड आवेदक से ऐसे व्यय जिनके अंतर्गत लेखापरीक्षक, अंकक एजेंसी को संदत्त फीस हैं वसूल करेगा जो इसके द्वारा आवेदक की स्कीमों, लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए उपगत किये जायें।

4) बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी नहीं की जाती हैं आवेदन नामंजूर कर सकेगा और तब आवेदक विनियम 73 में विनिर्दिष्ट रीति से इसकी विद्यमान

स्कीम (में) परिसमाप्त कर देगा।

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना

71.

(1)

बोर्ड यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि विनियम 70 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी की गयी हैं आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) आवेदक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर साख निर्धारण एजेंसी द्वारा विद्यमान स्कीमों की रेटिंग करवायेगा;
(ख) आवेदक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर लेखा परीक्षक द्वारा विद्यमान स्कीमों की लेखा परीक्षा करवायेगा;

(ग) आवेदक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर अंकक एजेंसी द्वारा विद्यमान स्कीमों का अंकन करवायेगा;

(घ) आवेदक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर इन विनियमों के अध्याय IV में विनिर्दिष्ट रीति से न्यास सृजित करेगा और न्यासियों की नियुक्ति करेगा;

(ङ) आवेदक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर नौवी अनुसूची के भाग - II में यथा विनिर्दिष्ट इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व चालू की गयी स्कीमों की बाबत लेखा और मूल्यांकन मानों का अनुपालन करेगा ;

(च) आवेदक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर एक करोड़ रुपये के न्यूनतम शुद्ध-मूल्य की पूर्ति करेगा जो अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से दो वर्षों, तीन वर्षों, चार वर्षों और पाँच वर्षों के भीतर प्रति एक करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया जायेगा ।

(छ) आवेदक स्कीम के प्रस्ताव दस्तावेज के

अधीन उद्भूत बाध्यताओं की पूर्ति करने से भिन्न स्कीम संपत्ति का व्ययन नहीं करेगा।

(ज) आवेदक विनियम 11 में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा;

(झ) ऐसी अन्य शर्तें जो बोर्ड अधिरोपित करे।

(2) आवेदक उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के लिए बोर्ड को लिखित वचन देगा।

(3) आवेदक जिसे बोर्ड द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र माना गया हो दूसरी अनुसूची के अनुसार अनंतिम रजिस्ट्रीकरण फीस संदत्त करेगा।

(4) आवेदक जो अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उप-विनियम (1) और विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है विनियम 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पात्र नहीं माना जायेगा और विनियम 73 में विनिर्दिष्ट रीति से स्कीम परिसमाप्त करेगा।

विद्यमान स्कीम को रजिस्ट्रीकरण

72

(1) विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम जो बोर्ड का समाधान करती है कि विनियम 9 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ और विनियम 71 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी की गयी हैं, को दूसरी अनुसूची के पैरा 2 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय पर और ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ विनियम 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(2) विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम जिसे उप-विनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ, नयी स्कीम में चालू करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

प्रतिसंदेय और परिसमापन की रीति 73

- (1) विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम;
 (क) जो बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल हुई हो ; या
 (ख) जिसे बोर्ड द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया गया हो ; या
 (ग) जो अनंतिम प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने पर विनियम 71 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती हो ;

विद्यमान स्कीम को परिसमाप्त करेगी।

- (2) उप-विनियम (1) के अधीन परिसमाप्त होनेवाली विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम उन विनिधानकर्ताओं जिन्होंने स्कीमों को अभिदत्त किया हो को सूचना ज्ञापन भेजेगी बोर्ड से प्रशापना की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर, स्कीम के कार्यकलाप की स्थिति, प्रत्येक विनिधानकर्ता को प्रतिसंदेय रकम और वह रीति जिसमें ऐसी रकम अवधारित की जाती है, के ब्यौरे देते हुए।
- (3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना ज्ञापन तारीखबद्ध और स्कीम के सभी निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
- (4) बोर्ड सूचना ज्ञापन में किये जानेवाले ऐसे अन्य प्रकटीकरण विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो यह ठीक समझे।
- (5) सूचना ज्ञापन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर विनिधानकर्ताओं को सूचना ज्ञापन भेजा जायेगा।
- (6) सूचना ज्ञापन में स्पष्टतः कथन होगा कि स्कीम में बने रहने की वांछ करनेवाले विनिधानकर्ताओं को सूचना ज्ञापन की तारीख से एक मास के भीतर स्कीम में बने रहने की निश्चयात्मक सहमति देनी होगी।

- (7) विनिधानकर्ता जो उप-विनियम 6 के अधीन निश्चयात्मक सहमति देते हैं, उनके जोखिम और उत्तरदायित्व पर स्कीम में बने रहेंगे।
परंतु यह कि यदि स्कीम में बने रहने की निश्चयात्मक सहमति, विद्यमान विनिधानकर्ताओं की कुल संख्या के केवल पच्चीस प्रतिशत या कम से प्राप्त होती है स्कीम परिसमाप्त कर दी जायेगी।
- (8) विनिधानकर्ताओं को संदाय, सूचना जापन की तारीख से तीन मास के भीतर किया जायेगा।
- (9) परिसमापन के पूरा होने पर, विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम बोर्ड के पास ऐसी रिपोर्टें दाखिल करेगी, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ।

रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की 74.
वांछा न करने वाली विद्यमान स्कीम
- प्रतिसंदाय करना

विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम जो बोर्ड से अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा करने वाली नहीं है प्रतिसंदाय की स्कीम की विनिर्मिति करेगी और विनियम 73 में विनिर्दिष्ट रीति से विद्यमान विनिधानकर्ताओं को ऐसा प्रतिसंदाय करेगी।

अध्याय X**विविध**

स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड 75.
की शक्ति

इन विनियमों के लागू होने या निर्वचन में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड के पास टिप्पणों या परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति होगी जो न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी या पूँजी बाज़ार में किसी अन्य मध्यवर्ती पर बाध्यकारी होंगे ।

[फा. सं. भाप्रविबो/19418/99]

देवेन्द्र गज मेहता, अध्यक्ष

पहली अनुसूची - प्ररूप

प्ररूप क

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

(विनियम 4,5(2))

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम :

2. संपर्क व्यक्ति :

3. अनुपालन अधिकारी का नाम :

दूरभाष सं. :

फैक्स सं. :

4. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

पिन कोड :

दूरभाष सं. :

फैक्स सं. :

5. पत्र-व्यवहार के लिए आवेदक का पता :

पिन कोड :

दूरभाष सं. :

फैक्स सं. :

6. आवेदक के शाखा कार्यालयों (भारत एवं विदेश में) का पता, यदि कोई हो :

(क)

(ख)

(ग)

7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए क्या कोई अन्य आवेदन किया गया है, यदि ऐसा है, उसके ब्यौरे :
8. सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के निगमन की तारीख और स्थान :
(निगमन प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें)
9. सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के उद्देश्य
(संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रति संलग्न करें)
10. मुख्य उद्देश्य :
11. आनुषंगिक उद्देश्य :
(संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में सामूहिक विनिधान स्कीम की बाबत आवश्यक खंड होना चाहिए और विद्यमान संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन, यदि कोई हो, सम्मिलित किए जाने होंगे ।)
12. पूँजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न
(5% या अधिक मताधिकार रखने वाले प्रमुख शेयर धारकों की सूची और उनकी शेयर धारिताओं की प्रतिशतता दें, सबसे पश्चात् की तारीख को)
13. कंपनी का शुद्ध मूल्य
(सबसे पश्चात् की तारीख को)
14. कारबार क्रियाकलापों का/के वर्तमान प्रकार :
(इतिवृत्त, प्रमुख उपलब्धियाँ और वर्तमान क्रियाकलाप)

15. वित्तीय जानकारी :

(टीक पूर्ववर्ती 3 वर्षों के लिए तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा संलग्न करें)

16. लेखा नीतियाँ :

(महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण दें)

17. प्रतिभूति बाज़ार से संबंधित क्रियाकलाप करने वाली और भाप्रविबो द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रदत्त सहयुक्त कंपनियों/समुत्थानों के नाम और क्रियाकलाप :

18. सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी का प्रबंधतंत्र :

19. निदेशक बोर्ड :

(निदेशकों के नाम, अर्हताएँ, पृष्ठभूमि, अनुभव , चाहे निदेशक पद पूर्णकालिक/अंश-कालिक आधार पर हो, अन्य निदेशक पद उपदर्शित करें । क्या निदेशकों में से कोई कहीं और पूर्ण नियोजन में है, उसके ब्यौरे दें। यदि निदेशकों में से कोई वृत्तिक निकाय जैसे भा.स.ले.सं. या भा.कं.स.सं. का एक सदस्य है, तो आवेदक के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए वृत्तिक निकाय की अनुज्ञा प्रस्तुत करें ।)

20. मूल प्रबंध कार्मिक :

(मूल प्रबंध कार्मिक के नाम, अर्हताएँ, अनुभव दें उनका अनुभव उपदर्शित करते हुए । साथ ही , नियुक्ति पत्र की स्वीकृति का सबूत, सबसे पश्चात् की वेतन पर्चियाँ भी प्रस्तुत करें ।)

21. अन्य कर्मचारी :

(अन्य कर्मचारियों के नाम, अर्हताएँ, अनुभव दें)

22. अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे :

23. कार्यालय स्थान:

(उस स्थान पर उपलब्ध क्षेत्र के विस्तार का वर्णन करें जहाँ मुख्य क्रियाकलाप किया जाएगा; सभी अवस्थानों पर उपलब्ध कार्यालय स्थान का व्यौरा; परिसरों में से प्रत्येक की बाबत सुसंगत विक्रय विलेख/पट्टा विलेख/किराया करार इत्यादि की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जानी हैं ।)

24. कार्यालय उपस्कर :

(इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय उपस्कर, कम्प्यूटरों, फैक्स, टेलीफोन इत्यादि के व्यौरों का वर्णन करें; उपर्युक्त उपस्करों के क्रय का सबूत प्रस्तुत करें ।)

25. मामलों में अंतर्वर्तन

(क) न्यायालय मामले/मुकदमे जिनमें आवेदक अंतिम 3 वर्षों में अंतर्वर्तित रहा हो ।

(ख) अंतिम 3 वर्षों में आवेदक के निदेशकों, कर्मचारियों का नैतिक अधमता/आर्थिक अपराधों से संबंधित किसी अपराध में अंतर्वर्तन ।

26. लेखा परीक्षक

27. अन्य जानकारी

आवेदक द्वारा दी गयी सेवाओं के स्वरूप से सुसंगत मानी गई कोई अन्य जानकारी ।

आवेदक के लेखापरीक्षकों के नाम और पते :

28. दस्तावेज

निम्न की प्रतियाँ प्रस्तुत करें :

[क] प्रारूप न्यास विलेख ; और

[ख] प्रारूप विनिधान प्रबंध करार

प्रारूप भरने के लिए अनुदेश :-

(क) आवेदकों को संपूरित आवेदन प्रारूप समुचित समर्थक दस्तावेजों के साथ बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहिए ।

(ख) यह महत्वपूर्ण है कि यह आवेदन प्रारूप विनियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए ।

(ग) आवेदन जो संपूर्ण नहीं है अस्वीकृत किए जाने के लिए दायी है ।

(घ) उत्तर टंकित और सुपाठ्य होने चाहिए ।

(ङ) जानकारी जिसकी अधिक ब्यौरों में दिए जाने की आवश्यकता है पृथक् पन्नों पर दी जाए जो आवेदन प्ररूप से संलग्न किए जाने चाहिए ।

(च) आवेदन ऐसे सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जो ऐसा करने के लिए प्राधिकृत हो और सभी हस्ताक्षर मूल रूप में होने चाहिए ।

प्ररूप ख

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

[विनियम 10]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा _____ को सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के लिए रजिस्ट्रीकरण कोड साविप्रकं/सविस्की/ / / है।

तारीख

आदेश द्वारा

ह/-

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और की ओर से

प्ररूप ग

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

[विनियम 18(2)]

सामूहिक विनिधान स्कीम का न्यासीपद

1] निम्नलिखित विशिष्टियाँ दें :

[क] संस्था का नाम

[ख] पता/टेलीफोन/टेलेक्स/फैक्स सं.

[ग] संपर्क व्यक्ति का नाम

[घ] भाप्रविबो रजिस्ट्रीकरण सं. :

[ङ] न्यासी का प्रबंधतंत्र
 निदेशक बोर्ड
 मूल कार्मिक
 अन्य कर्मचारी

[च] अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे
 कार्यालय स्थान
 कार्यालय उपस्कर

[छ] न्यायलय मामले/मुकदमे जिनमें न्यासी अंतिम तीन वर्षों में अंतर्वलित रहा हो और क्या मामला लंबित है या न्यायनिर्णीत किया गया है।

[ज] अंतिम 3 वर्षों के दौरान भाप्रविबो द्वारा या अन्य विनियामक निकायों द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति।

[झ] न्यासी द्वारा दी गयी सेवाओं के स्वरूप से सुसंगत मानी गई कोई अन्य जानकारी ।

2] प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

(प्ररूप क देखें)

दूसरी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

[विनियम 6, 10, 26(1), 59 (छ), 71 (3), 72(1)]

फीस

1.

क. आवेदक द्वारा संदेय आवेदन फीस :	पच्चीस हजार रुपये
ख. विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम द्वारा संदेय अनंतिम रजिस्ट्रीकरण फीस : [नीचे पैरा 2 देखें]	पाँच लाख रुपये
ग. सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस :	दस लाख रुपये
घ. प्रस्ताव दस्तावेज के लिए दाखिल करने की फीस	पच्चीस हजार रुपये
2. आवेदक, जिसने पैरा 1 के उप-पैरा ख के अधीन 5 लाख रुपये की अनंतिम रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय किया है, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के समय 5 लाख रुपये की शेष रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेगा।
3. ऊपर पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट फीसों, “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड” के पक्ष में मुम्बई में या प्रादेशिक कार्यालयों में जहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है एक बैंक ड्राफ्ट के द्वारा संदत्त की जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

[विनियम 14 (ज), 21 (8), 59 (घ)]

आचार संहिता

1. यूनिट धारकों के सभी वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाए

सामूहिक विनिधान स्कीम के संगठन, परिचालन और प्रबंध और उनमें आस्तियों का सृजन निम्न में संचालित होगा -

(क) स्कीम के यूनिट धारकों के सभी वर्गों के हित में और

(ख) ना कि केवल कंपनी के निदेशकों या सहयुक्त व्यक्तियों या यूनिट धारकों के किसी विशेष वर्ग के हित में

2. जानकारी का प्रसारण

(क) न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सभी यूनिटधारकों को स्कीम की विनिधान नीतियों, विनिधान उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और सामान्य कामकाज के बारे में पर्याप्त, सही, और सुस्पष्ट जानकारी का समय पर प्रसारण सुनिश्चित करेगी।

(ख) ऐसी सभी जानकारी ऋजुता से सरल भाषा में प्रस्तुत होगी।

3. हित-टकराव

न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी स्कीमों के कामकाज के प्रबंधन में हित-टकराव से बचेंगे और सभी मामलों में सभी यूनिटधारकों के हित को सर्वोपरि मानेंगे।

4. पृथक्करण

न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी निधियों और यथासृजित आस्तियों का स्कीमवार पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे।

5. सत्यनिष्ठा, उद्देश्यों के अनुसार विनिधान इत्यादि

न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी

- (क) प्रस्ताव दस्तावेजों में कथित विनिधान उद्देश्यों के अनुसार कारबार और विनिधान करेंगे तथा विनिधान विनिश्चय केवल यूनिट धारकों के हित में करेंगे;
- (ख) उनकी स्कीमों के विपणन के लिए कोई अनैतिक साधन नहीं अपनायेंगे या यह करने के लिए किसी विनिधानकर्ता को उत्प्रेरित नहीं करेंगे।
- (ग) उनके सभी क्रियाकलाप यूनिटधारकों के हित में और सर्वथा सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी से करेंगे।

चौथी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

[विनियम 17(1)]

न्यास विलेख की विषय-वस्तु

1. प्रमुख खंड

न्यास विलेख में निम्न खंड अंतर्विष्ट होंगे अर्थात् :-

- [क] स्कीम की आस्तियों के संरक्षण के लिए न्यासी के उत्तरदायित्व, बाध्यताएँ और अधिकार।
- [ख] यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कि स्कीम संपत्ति का प्रबंधन प्रस्ताव दस्तावेज और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- [ग] सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के उत्तरदायित्व, बाध्यताएँ और अधिकार।
- [घ] स्कीम के निर्गम, यूनिटों के मूल्य निर्धारण और व्यय जिसके अंतर्गत फीस का संदाय और आय और अभिलाभों का वितरण है, और लेखा के लिए नीतियाँ।

- [ड] विनिधानकर्ताओं को प्रस्ताव दस्तावेजों और विज्ञापनों में विभिन्न स्कीम उद्देश्यों के और विनिधान उद्देश्यों के प्रकटीकरणों और वार्षिक और अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट करने की अपेक्षाओं के लिए नीतियाँ।
- [च] स्कीम का लेखापरीक्षक सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के लेखा परीक्षक से भिन्न होगा सुनिश्चित करने के लिए उपबंध। इसके अतिरिक्त, इसमें स्कीम के लेखापरीक्षक की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, हटाये जाने और प्रतिस्थापन की शर्तें अंतर्विष्ट होंगी।
- [छ] पूँजी या आय को व्यय के आबंटन से संबंधित व्यापक नीतियाँ।
- [ज] न्यास संपत्ति में से किसी आस्ति जिसमें किसी ऐसी देयता की धारणा अंतर्लित हो जो असीमित है या किसी भी रूप में न्यास संपत्ति के विल्लंगम के रूप में परिणामित नहीं होगा, का अर्जन स्पष्टतः निषिद्ध करने के लिए उपबंध।
- [झ] न्यासी को संदेय न्यासीपद फीस, यदि कोई हो।
- [ञ] इस आशय के उपबंध कि बोर्ड और यूनिट धारकों के पूर्विक अनुमोदन के बिना न्यास विलेख में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।
- [ट] यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कि सभी मामलों में न्यासी को हटाने के लिए बोर्ड का पूर्विक अनुमोदन अपेक्षित होगा और नये न्यासी की नियुक्ति और उनके हटाये जाने से संबंधित उपबंध विनिर्दिष्ट किये जाएँ।
- [ठ] यूनिट धारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया
- [ड] विनिधानकर्ताओं की शिकायतों के समाधान और अवधि जिसमें ऐसी शिकायतों का समाधान किया जायेगा के लिए उपबंध।
- [ढ] परिस्थितियाँ जिनके अधीन न्यासी के अनुमोदन से आस्तियों का व्ययन किया जा सकेगा।
- [ण] यूनिटों के अंतरण, यूनिट धारकों की बैठकों और यूनिटधारकों के अद्यतन रजिस्टर के अनुरक्षण से संबंधित उपबंध।
- [त] अवधि जिसमें आबंटन के बाद यूनिट प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगे और अवधि जिसमें यूनिटों का अंतरण पूरा किया जायेगा।
- [थ] बोर्ड के पास दाखिल किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी दस्तावेज पर सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के कम से कम दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो सुनिश्चित करने के लिए उपबंध।
- [द] यूनिटधारकों और विनिधानकर्ताओं के निरीक्षण के लिए न्यास विलेख की सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपबंध।

[ध] न्यास संपत्ति में यूनिटधारकों का लाभप्रद हित केवल अपनी अपनी स्कीमों में व्यक्तिगत धारिता तक ही सीमित होगा सुनिश्चित करने के लिए उपबंध ।

2. उचित तौर पर जानकारी के संबंध में न्यासी के कर्तव्य इत्यादि

न्यास विलेख में अधिकथित होगा कि न्यासी :

[क] सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से आवश्यक जानकारी और तिमाही रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा।

[ख] यूनिटों के मूल्य निर्धारण और स्कीम में तथा से संदाय और स्कीम की आय का समुचित लेखाकरण और व्ययों का प्रभारीकरण और यथाअनुज्ञेय संवितरण के संबंध में सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की यादृच्छिक निगरानी करेगा।

[ग] अन्य कंपनियों, या संस्थाओं, या वित्तीय मध्यवर्तियों या किसी निगम निकाय जिससे यह सहयुक्त हो, परस्पर दूरी का संबंध बनाये रखेगा।

[घ] स्कीम की सभी संपत्ति उनकी अभिरक्षा में या उनके नियंत्रण के अधीन रखेगा और इसे यूनिट धारकों के लिए न्यास में धारण करेगा।

[ङ] यूनिटधारकों के हित में कार्य करेगा।

[च] यूनिट धारकों और बोर्ड को जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जानकारी उपलब्ध करायेगा या करवायेगा।

[छ] स्कीम संपत्ति के प्रबंधन के लिए सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के साथ इस प्रयोजन के लिए एक करार करेगा, और उसे न्यास विलेख से संलग्न करेगा।

[ज] न्यास विलेख, प्रस्ताव दस्तावेज और विनियमों के अनुसार स्कीम को संदत्त किये जाने के लिए देय किसी आय और कर की चुकौती का दावा करने के लिए तथा धारकों के लिए न्यास में प्राप्त किसी आय के धारण के लिए संग्रहण का पर्यवेक्षण करेगा।

[झ] सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा चालू की गयी और प्रबंधित स्कीमों के अधीन निधियाँ न्यास विलेख, प्रस्ताव दस्तावेज और विनियमों के अनुसार है सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा।

[ञ] सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को केवल विशिष्ट दशाओं में विनियमों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से ही हटाना होगा।

[ट] स्कीम के संबंध में इसके सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और स्कीम की आस्तियों के अभिरक्षक के रूप में भी कार्य करेगा।

3. कंपनी की बाध्यताएँ

न्यास विलेख में अधिकथित होगा कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी :

- [क] न्यासी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् स्कीम के लिए स्कीमें चालू करेगी, और विभिन्न स्कीमों के अधीन जुटायी गयी निधियों का प्रबंध न्यास विलेख, प्रस्ताव दस्तावेज और विनियमों के उपबंधों के अनुसार करेगी।
- [ख] स्कीम के कॉर्पस का विनिधान अन्य स्कीम में नहीं करेगी।
- [ग] न्यासी के अनुमोदन के बिना यूनिट खरीदने के लिए आमंत्रण या यूनिटों के विक्रय मूल्य या स्कीम से प्रत्याशित आय की बाबत कथन अंतर्विष्ट करनेवाले किसी विज्ञापन का प्रकाशन न तो करेगी या करवायेगी।
- [घ] इसके कारबार को समुचित और सक्षम रीति में करने के लिए और संचालन के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम जिससे विलेख संबंधित है समुचित और सक्षम रूप में की जाती हैं और संचालित है, इसका श्रेष्ठ प्रयास करेगी।
- [ङ] न्यासी या लेखापरीक्षकों को निरीक्षण के लिए स्कीम की सभी बहियाँ उपलब्ध करायेगी।
- [च] न्यासी या लेखापरीक्षकों को ऐसी मौखिक या लिखित जानकारी देगी जिसकी न्यासी या लेखापरीक्षक स्कीम से संबंधित सभी मामलों की बाबत या अन्यथा स्कीम के कार्यकलापों से संबंधित अपेक्षा करे।
- [छ] सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा धारित स्कीम से संबंधित किन्हीं यूनिटों की बाबत मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगी।

पाँचवी अनुसूची
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999
[विनियम 20(2)]

स्कीम संपत्ति के प्रबंधन के लिए करार की विषय-वस्तु

विनिधान प्रबंध करार में निम्न खंड अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-

1. सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की बाध्यताएँ :

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी :

- क) न्यासी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् स्कीम चालू करने और न्यास विलेख, प्रस्ताव दस्तावेज और विनियमों के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न स्कीमों के अधीन जुटायी गयी निधियों का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगी;
- ख) न्यास विलेख, प्रस्ताव दस्तावेज और विनियमों के अनुसार विभिन्न स्कीमों के अधीन जुटायी गयी निधियों का विनिधान करेगी;
- ग) स्कीम संपत्ति में से कोई आस्ति अर्जित नहीं करेगी, जिसमें किसी देयता की ऐसी धारणा, जो कि असीमित है, या जो किसी भी रूप में स्कीम की संपत्ति के विल्लंगम के रूप में परिणामित हो सकेगी अंतर्वर्तित हो;
- घ) विनियमों के उल्लंघन में ऋण या ऋण की गारंटी नहीं देगी या कोई क्रियाकलाप नहीं करेगी;
- ङ) सुनिश्चित करेगी कि कोई भी आवेदन प्रपत्र, या भावी विनिधानकर्ताओं को जारी विक्रय सामग्री या अन्य मुद्रित सामग्री, या विज्ञापन, या रिपोर्ट और या यूनिट धारकों के सामान्य निकाय को, अथवा जनता को, अथवा प्रेस को, अथवा अन्य संचार मीडिया को संबोधित आख्यापन न्यासी के लिखित रूप में पूर्वानुमोदन के बिना जारी या प्रकाशित नहीं किया जाता है, और उसमें न्यासी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित न्यास विलेख या प्रस्ताव दस्तावेज स्कीम विशिष्टियों से बाहरी कोई कथन या सामग्री अंतर्विष्ट नहीं है;
- च) न्यासी को स्कीमों की कार्यप्रणाली पर तिमाही या ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो न्यासी या बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो;

2. न्यासी :

- क) को सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा प्रबंधित विभिन्न स्कीमों के परिचालनों से संबंधित सभी जानकारी ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति में प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो न्यासी द्वारा सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी न्यास विलेख, प्रस्ताव दस्तावेज और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन कर रही है।
- ख) के पास विनियम के अनुसार केवल बोर्ड के अनुमोदन से विशिष्ट दशाओं में ही सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को हटाने की शक्ति होगी।

3. हानियों की पूर्ति करना

सामूहिक विनिधानकर्ता प्रबंध कंपनी या इसके अधिकारियों या सामूहिक विनिधानकर्ता प्रबंध कंपनी द्वारा प्रत्यायोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपगत किसी हानि या नुकसान या व्यय की पूर्ति न्यास संपत्ति में से नहीं की जायेगी।

छठी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

[विनियम 26(2)]

प्रस्ताव दस्तावेज की विषय-वस्तु

1) विषय वस्तु

बोर्ड के पास दाखिल किये गये प्रस्ताव दस्तावेज में विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्न जानकारी विनिधानकर्ताओं को स्कीम में विनिधान पर सही, ऋजु और संसूचित विनिश्चय करने में समर्थ करने हेतु अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:

1. प्रावरण

1.1 प्रारंभिक बाह्य मुख पृष्ठ

i) बोर्ड के पास दाखिल प्रस्ताव दस्तावेज के प्रारंभिक बाह्य मुखपृष्ठ में केवल निम्न ब्यौरे ही अंतर्विष्ट होंगे:

स्कीम का नाम, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी और न्यासी के नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, उनके टेलिफोन नंबर और फैक्स नंबर सहित।

ii) प्रस्तावित यूनिटों का स्वरूप, संख्या, कीमत और राशि

iii) सामान्य जोखिम की बाबत निम्न खंड सम्मिलित किया जाना चाहिए :

"यूनिटों में विनिधान में जोखिम की मात्रा अंतर्वर्तित रहती है और विनिधानकर्ताओं को इस प्रस्ताव में किन्हीं भी निधियों का तब तक विनिधान नहीं करना चाहिए जब तक कि वे उनके विनिधान को खो देने का जोखिम उठाने की क्षमता नहीं रखते हों। विनिधानकर्ताओं को इस प्रस्ताव के संबंध में कोई विनिधान विनिश्चय करने से पूर्व जोखिम कारकों को सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। विनिधान विनिश्चय करने के लिए, विनिधानकर्ताओं को अंतर्वर्तित जोखिमों सहित स्कीम और प्रस्ताव के बारे में केवल उनके अपने परीक्षण पर ही निर्भर करना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भाप्रविबो) द्वारा यूनिटों की सिफारिश या अनुमोदन नहीं किया गया है, न ही भाप्रविबो इस दस्तावेज की यथार्थता या पर्याप्तता की गारंटी देता है।"

'सामान्य जोखिम' में जोखिम कारकों के संक्षिप्त और ब्यौरेवार विवरण की पृष्ठ संख्याएँ उपदर्शित करते हुए उनकी ओर विनिधानकर्ताओं का ध्यान विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा।

iv) "सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी" का आंत्यतिक उत्तरदायित्व खंड निम्नानुसार सम्मिलित किया जाए :

"सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, सभी युक्तियुक्त जाँच करते हुए, इसके लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करती है और पुष्टि करती है कि इस प्रस्ताव दस्तावेज में स्कीम के संबंध में सभी जानकारी अंतर्विष्ट हैं और कि प्रस्ताव दस्तावेज में अंतर्विष्ट जानकारी सभी तात्विक पहलुओं से सत्य और सही है और किसी तात्विक विषय में भ्रामक नहीं है, कि इसमें अभिव्यक्त विचार और आशय ईमानदारीपूर्वक अभिनिर्धारित हैं और कि ऐसा कोई अन्य तथ्य नहीं है जिसका लोप इस दस्तावेज को पूर्ण रूप से या ऐसी कोई भी जानकारी या ऐसे किसी विचार या आशय की किसी भी अभिव्यक्ति को किसी भी प्रकार से तात्विक रूप में भ्रामक बनाता है।"

- v) निर्गम रजिस्ट्रार का नाम और पता, टेलिफोन संख्या और फैक्स संख्या सहित।
- vi) स्कीम के लेखापरीक्षक का नाम और पता।
- vii) प्रस्ताव के लिए खुलने की, बंद करने की और पूर्वतम बंद करने की तारीख (यदि कोई हो)
- viii) साख निर्धारण - साख निर्धारण एजेंसी का नाम, दी गयी रेटिंग, रेटिंग की अवधि।
- ix) अनुपालन अधिकारी का नाम।
- x) मूल्यांकनकर्ता एजेंसी का नाम - एक संक्षिप्त मूल्यांकन रिपोर्ट
- xi) प्रारंभिक मुखपृष्ठ सफेद होगा। इस पृष्ठ पर कोई आकृति या तस्वीर मुद्रित नहीं होगी।
- xii) मुखपृष्ठ की मोटाई पर्याप्त होगी (अधिमानतः न्यूनतम 100 जीसीएम कोटि)।

1.2 प्रारंभिक आंतरिक मुखपृष्ठ

अनुक्रमणिका प्रारंभिक आंतरिक मुखपृष्ठ पर दी जायेगी।

1.3 अंतः मुखपृष्ठ

प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किये जाने के अतिरिक्त अन्य जोखिम कारक पृष्ठ i के रूप में संख्यांकित प्रथम अंतः मुखपृष्ठ से शुरू होकर स्पष्ट सुपाठ्य अक्षरों में (अधिमानतः न्यूनतम 10 पॉइंट आकार के) मुद्रित किये जायेंगे (और, यदि आवश्यक हुआ तो, अनुवर्ती पृष्ठ ii, iii आदि पर जारी रहेंगे, प्रस्ताव दस्तावेज की पृष्ठ संख्या से भिन्न रूप में जो 1,2,3 आदि होगी)।

1.4 पिछला मुखपृष्ठ

पिछला आंतरिक मुख पृष्ठ और पिछला बाह्य मुखपृष्ठ सफेद और कोरा होगा। प्रधानता दिये जाने के लिए अपेक्षित कोई भी 'टिप्पणी' जोखिम कारकों, वे जहाँ कहीं भी प्रकट हों के तुरंत बाद प्रकट होगी।

2. जोखिम कारक

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी जोखिम कारकों को, वह जो स्कीम के लिए विशिष्ट और आंतरिक हैं और वह जो बाहरी हैं और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के नियंत्रण के बाहर हैं के रूप में वर्गीकृत करेगी। सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की आंतरिक और बाहरी जोखिम कारकों की अवधारणा को प्रत्येक जोखिम कारक के तुरंत बाद दिया जायेगा और प्रबंध धारणा के अधीन पृथक् शीर्ष के रूप में नहीं दिया जायेगा।

3. दावा-त्याग खंड

प्रस्ताव दस्तावेज में बड़े और स्पष्ट अक्षरों में निम्न दावा-त्याग खंड अंतर्विष्ट होगा।

यह सुस्पष्टतः समझा जाए कि भाप्रविबो को प्रस्ताव दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण को किसी भी रूप में यह नहीं समझा जायेगा या उसका यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि इसे भाप्रविबो द्वारा निपटायें गये या अनुमोदित किया गया है। भाप्रविबो न तो ऐसी किसी भी स्कीम, जिसके लाभ के लिए निर्गम प्रस्तावित है, की वित्तीय सुदृढ़ता की और न ही प्रस्ताव दस्तावेज में किये गये कथनों या अभिव्यक्त विचारों की शुद्धता की जिम्मेदारी लेता है। सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, _____ ने प्रमाणित किया है कि प्रस्ताव दस्तावेज में किये गये प्रकटीकरण सामान्यतः पर्याप्त हैं और वर्तमान में प्रवृत्त भाप्रविबो (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम 1999 के अनुरूप हैं। यह अपेक्षा यूनिटधारकों के लिए प्रस्तावित निर्गम में विनिधान करने के लिए संसूचित विनिश्चय करना सुकर बनाने के लिए है।

यह भी स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी प्रस्ताव दस्तावेज में सभी सुसंगत जानकारी की शुद्धता, पर्याप्तता और प्रकटीकरण के लिए प्रमुख तौर पर उत्तरदायी है।

हम सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी पुष्टि करते हैं कि :

भाप्रविबो को प्रेषित प्रस्ताव दस्तावेज निर्गम से सुसंगत दस्तावेजों, सामग्रियों और पत्रों से सुसंगत हैं; कथित निर्गम से संबंधित सभी विधिक अपेक्षाओं, साथ ही इस निमित्त भाप्रविबो, सरकार और किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेशों इत्यादि का सम्यक् अनुपालन किया गया है; और प्रस्ताव दस्तावेज में किये गये प्रकटीकरण सत्य, ऋजु और विनिधानकर्ताओं को प्रस्तावित स्कीम में विनिधान करने के लिए सुसंयोजित विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि हमारे अतिरिक्त, प्रॉस्पेक्टस में दर्शाये गये सभी मध्यवर्ती भाप्रविबो से रजिस्ट्रीकृत हैं और आज की तारीख तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण वैध है।

4. सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से वचनबंध

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा निम्न वचन प्रस्ताव दस्तावेज में सम्मिलित किया जायेगा :

- i) कि स्कीम की यूनिटों के निर्गम की बाबत प्राप्त शिकायतों का समाधान शीघ्रतापूर्वक और संतोषप्रद रूप में किया जायेगा।
- ii) कि रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रतिदाय आदेशों / आबंटन पत्रों / प्रमाणपत्रों के प्रेषण के लिए अपेक्षित निधियाँ सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा निर्गम रजिस्ट्रार को उपलब्ध करायी जायेगी।
- iii) कि अनिवासी भारतीयों को यूनिटों के प्रमाणपत्र / प्रतिदाय आदेश समय पर प्रेषित किये जायेंगे।

- iv) कि प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख अर्थात् तारीख जब प्रस्ताव दस्तावेज बोर्ड के पास दाखिल किया जाता है, के छह महीने के पश्चात् जनता को कोई यूनिट निर्गमित नहीं किये जायेंगे।

5. काल्पनिक आवेदन

कोई व्यक्ति, जो स्कीम के किसी यूनिट के अर्जन या अभिदान के लिए काल्पनिक नाम में आवेदन करता है, या अन्यथा स्कीम को आबंटन के लिए उत्प्रेरित करता है या, उसमें उसे या कल्पित नाम में किसी अन्य व्यक्ति को यूनिटों के किसी अंतरण का रजिस्ट्रीकरण करता है, भाप्रविबो अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

6. न्यूनतम अभिदान खंड

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी स्कीम को चालू करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक यूनिटों का न्यूनतम अभिदान कथित करेगी।

प्रस्ताव दस्तावेज में न्यूनतम अभिदान खंड निम्नानुसार सम्मिलित किया जाना है :

"यदि स्कीम निर्गम की बंद होने की तारीख तक जनता से यूनिटों का ऊपर कथित न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं करती है, तो प्राप्त संपूर्ण अभिदान राशि तत्काल लौटायी जायेगी।"

7. अधिकतम अभिदान खंड

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी यूनिटों की अधिकतम संख्या कथन करेगी जो प्रस्ताव दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तावित की जायेगी।

न्यूनतम और अधिकतम - मूल्यांकनकर्ता एजेंसी द्वारा - तुलना की गयी।

8. वर्तमान निर्गम के निबंधन

8.1 संदाय के निबंधन

8.2 विनिधानकर्ताओं के अधिकार

8.3 आवेदन कैसे करें - प्रपत्रों की उपलब्धता, प्रस्ताव दस्तावेज और संदाय की रीति

8.4 स्कीम में विनिधान के लिए कोई विशेष कर फायदा

9. परियोजना का मूल्यांकन

मूल्यांकन करनेवाली मूल्यांकनकर्ता एजेंसी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाए और मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं के ब्यौरे दिये जाएँ। मूल्यांकन की तारीख के साथ मूल्यांकन की परिधि और प्रयोजन प्रकट किये जाएँ। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार

परियोजना की लागत और वित्त के साधन भी प्रकट किये जाएँ। मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गयी कमजोरियाँ और आशंकाएँ भी, यदि कोई हों, जोखिम कारकों के माध्यम से प्रकट की जानी चाहिए।

10. स्कीम से संबंधित परियोजना

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी प्रकट करेगी -

- i) ब्यौरेवार विशिष्टियाँ जो स्कीम का सही स्वरूप प्रकट करने के लिए पर्याप्त हो।
- ii) संपत्ति का स्वरूप और वर्णन तथा शर्तें या परिस्थितियाँ, जिसके अधीन यह न्यासियों के पास निहित हो जायेंगी।
- iii) स्कीम के संबंध में खरीदी गयी या अर्जित की गयी या खरीदे जाने या अर्जन के लिए प्रस्तावित संपत्ति की बाबत, निम्न दिये जायेंगे -

विक्रेता (ओं) का नाम और पता

विक्रेता या प्रत्येक विक्रेता को, यथास्थिति, संदत्त या संदेय नकद राशि या अन्य प्रतिफल

संपत्ति से संबंधित किसी संव्यवहार की संक्षिप्त विशिष्टियाँ, जिसमें संपत्ति का कोई भी विक्रेता या कोई व्यक्ति जो संव्यवहार के समय सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी में नियंत्रण या नियंत्रणकारी हित रखता है या था या का निदेशक है या था या

प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से संबंधित है या था

(यदि न्यासी द्वारा अर्जित की जानेवाली संपत्ति पट्टे पर ली जानी है तो "विक्रेता" शब्द का अर्थ पट्टाकर्ता लगाया जायेगा, "क्रय धन" पद में पट्टे के लिए प्रतिफल सम्मिलित होगा)

- iv) - की राशि या अनुमानित राशि
- v) स्कीम के गठन के लिए व्यय; और
- vi) निर्गम का व्यय, और व्यक्तियों के नाम जिनके द्वारा इन व्ययों में किसी का संदाय किया गया है या संदेय है।

11. स्कीम का प्रबंधन

11.1 यह अनुभाग रीति का वर्णन करेगा जिसमें स्कीम का प्रबंधन किया जाता है। प्रकटीकरण में निम्न सम्मिलित होगा -

- i) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की पहचान और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के प्रमुख कार्मिक का नाम, जो स्कीम के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा, उसकी अर्हता, अनुभव और पृष्ठभूमि सहित;
- ii) विनिधानकर्ता संपर्क अधिकारी का नाम और पता
- iii) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी का नाम और पता तथा सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के बोर्ड के निदेशकों के नाम और पते, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के अनुभव के संक्षिप्त वर्णन के साथ;
- iv) विनिधान प्रबंध करार करने की तारीख का प्रकटन।

- v) न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनों के पारिश्रमिक / प्रतिकर से संबंधित अलग अलग पूरी जानकारी; रीति जिसमें वह पारिश्रमिक / प्रतिकर उपलब्ध कराया जाता है, और परिवर्तन (यदि कोई हो) जो उस पारिश्रमिक / प्रतिकर के रूप में स्कीम की किसी भी यूनिट के विक्रय या के लिए अभिदान में और स्कीम के संबंध में आय और पूँजी के संवितरण पर या अन्यथा किये जायेंगे।

11.2 ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की पहचान जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक या कारबार प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करता है और प्रदत्त सेवाओं तथा उसके लिए संदत्त किये जानेवाले प्रतिकर का संक्षिप्त वर्णन;

11.3 रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों के नाम और मुख्य कारबार का पता। इस आशय का कथन कि न्यासी और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी ने सुनिश्चित किया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदनों के प्रसंस्करण और विनियम में विहित समय सीमा में यूनिट धारकों को यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण के संबंध में उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का समुचित सामर्थ्य है तथा निवेशक शिकायतों के निपटान का भी पर्याप्त सामर्थ्य है।

11.4 स्कीम के लिए कानूनी लेखापरीक्षक की पहचान और नाम तथा पता

12. सामूहिक विनिधान स्कीम का गठन

इस शीर्ष के अधीन, निम्न पर चर्चा की जायेगी :

- i) स्कीम के उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन
- ii) सामूहिक विनिधान स्कीम के घटकों अर्थात् सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी और न्यासी के कृत्य और दायित्व ;
- iii) न्यासी के निदेशकों के नाम और पते तथा उनकी मुख्य उपजीविकाओं और चालू निदेशकपद के ब्यौरे
- iv) न्यास विलेख के महत्वपूर्ण उपबंधों का सारांश जो यूनिटधारकों के लिए तात्त्विक रुचि का हो सकेगा।

13. यूनिट और प्रस्ताव

प्रस्तावित होनेवाले यूनिटों का स्वरूप और अति महत्वपूर्ण विशेषताओं का संक्षिप्त रूप में वर्णन करें, निम्न को सम्मिलित करते हुए :

- i) प्रस्ताव पर यूनिटों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या और इस राशि से अधिक राशि का प्रतिदाय प्रकट किया जायेगा।
- ii) परिस्थितियाँ जिसके अधीन प्रतिदाय होगा और अवधि जिसके भीतर प्रतिदाय किया जायेगा।
- iii) खुलने, बंद होने, पूर्ववर्ती बंद होने, आबंटन और प्रमाणपत्रों का प्रेषण उपदर्शित करनेवाला कैलेण्डर।
- iv) अवधि जिसमें प्रमाणपत्रों का आबंटन और प्रेषण पूरा किया जायेगा और इस संबंध में सुसंगत विनियम इस आशय के कथन के साथ कि आबंटन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद शीघ्र ही एक विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

- v) स्कीम की परिपक्वता कालावधि या अवधि।
- vi) परिस्थितियाँ जिसके अधीन स्कीम परिसमाप्त की जायेगी (विनियमों के अनुसरण में)।
- vii) यूनिटों के अंतरण और पारेषण के लिए अनुगमन की जानेवाली प्रक्रियाएँ।
- viii) यूनिटधारकों के अधिकार, मतदान, बैठकें बुलाना इत्यादि को सम्मिलित करते हुए।
- ix) पता, जहाँ यूनिटधारकों का रजिस्टर रखा जाता है या रखा जायेगा और दिन जब तथा घंटे जिस दौरान रजिस्टर जनता के लिए पहुँचयोग्य होगा।
- x) स्कीम की किसी यूनिट के लिए अभिदान हेतु या अभिदान करने के करार के लिए अथवा अभिदान उपाप्त करने या अभिदान उपाप्त करने के करार के लिए कमीशन के रूप में संदत्त या संदेय राशि, यदि कोई हो, या ऐसे किसी कमीशन की दर। साथ ही, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी में नियंत्रण या नियंत्रणकारी हित रखनेवाले व्यक्तियों के या उसके निदेशक का नाम जो ऐसा कोई कमीशन प्राप्त करने के हकदार हैं या उस कमीशन की राशि या दर।
- xi) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी में नियंत्रण या नियंत्रणकारी हित रखनेवाले व्यक्तियों या के निदेशक को यूनिटों के निर्गम के आगमों में से संदत्त या दी गयी या संदत्त करने या देने के लिए आशयित कोई राशि या फायदे, और राशि या फायदे को संदत्त करने या देने के लिए प्रतिफल।
- xii) स्कीम के संबंध में किये गये किसी विनिधान या धारित संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित नीति।
- xiii) यूनिटधारकों को स्कीम से व्युत्पन्न आय के संवितरण से संबंधित नीति।

14. विद्यमान मुकदमे, व्यतिक्रम, देयताएँ इत्यादि

- i) सभी लंबित मुकदमों, जिनमें सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी अंतर्वलित हैं, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं / बैंकों के प्रति व्यतिक्रमों और कानूनी देयताओं को असंदाय में अंतर्वलित राशि और ऐसे मुकदमों / व्यतिक्रमों की वर्तमान प्रास्थिति सहित प्रस्ताव दस्तावेज में सूचीबद्ध किया जायेगा।
- ii) उपर्युक्त जानकारी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के विरुद्ध या किसी अन्य सत्ता के विरुद्ध मुकदमा जिसका परिणाम स्कीम की स्थिति पर तात्त्विक रूप से प्रतिकूल होता है, के अतिरिक्त प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- iii) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के निदेशक के विरुद्ध आर्थिक अपराधों के लिए आरंभ किये गये लंबित मुकदमे उनके वर्तमान प्रास्थिति उपदर्शित करते हुए पृथक् रूप से प्रकट किये जायेंगे। सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी पिछले मामलों जिसमें संबंधित प्राधिकरण द्वारा शास्तियाँ अधिरोपित की गयी थीं के ब्यौरे प्रस्तुत करेगी।
- iv) विवाद-ग्रस्त कर देयताओं आदि सहित स्कीम के परिचालनों और वित्तों को संभाव्य रूप से प्रभावित करनेवाले मामलों से संबंधित विद्यमान मुकदमों, व्यतिक्रमों आदि को प्रस्ताव दस्तावेज में प्रस्तुत किया जायेगा।

- v) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी प्रस्ताव दस्तावेज में और जोखिम कारकों के रूप में स्कीमों के विरुद्ध लंबित मुकदमों, व्यतिक्रमों, कानूनी देयताओं के असंदाय और आर्थिक अपराधों / सिविल अपराधों के लिए आरंभ की कार्यवाहियों को समुचित रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगी।
- vi) यदि ऊपर उल्लिखित मुकदमों आदि में से कोई प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के पश्चात् उद्भूत होते हैं तो प्रस्ताव दस्तावेज में (और जोखिम कारकों के रूप में) तथ्य समुचित रूप से सम्मिलित किये जायेंगे। यदि ऐसे कोई मामले नहीं हैं तो प्रस्ताव दस्तावेज में इस संबंध में एक सुस्पष्ट नकारात्मक कथन करना अपेक्षित है।
- vii) भाप्रविबो अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये विनियम के अधीन जाँच / न्यायनिर्णयन कार्यवाहियाँ जो स्कीम या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से किसी भी हैसियत में सहयुक्त किसी कंपनी, न्यासी या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के निदेशकों में से किसी या प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध चालू है, प्रकट की जायेंगी।

15. विनिधानकर्ता शिकायत और समाधान प्रणाली पर प्रकटीकरण

प्रस्ताव दस्तावेज में विनिधानकर्ता की शिकायतों के समाधान के लिए सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा व्यवस्थाएँ या विकसित कोई तंत्र को प्रकट करना चाहिए। अतिरिक्त जानकारी के रूप में, कंपनी को विनिधानकर्ताओं की विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निपटान के लिए इसके द्वारा सामान्यतः लिये जानेवाला समय प्रकट करना चाहिए। साथ ही, विद्यमान स्कीम के पिछले तीन राजकोषीय वर्षों के लिए विनिधानकर्ताओं की शिकायतों का इतिहास और उनके समाधान तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करें। प्रस्ताव दस्तावेज में सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के पास प्राप्त, निपटायी गयी और लंबित शिकायतों की संख्या का स्कीम प्रारंभ करने से 30 दिन पूर्व का अद्यतन आँकड़ा सम्मिलित किया जाना चाहिए।

16. स्टॉक इन्वेस्ट संबंधी प्रकटीकरण

स्टॉक इन्वेस्ट अभिप्राप्त करने की रीति, और स्टॉक इन्वेस्ट युक्त आवेदनों के निपटान, स्टॉक इन्वेस्ट आहरित करने की रीति, तीसरे पक्ष द्वारा स्टॉक इन्वेस्ट के उपयोग, क्रेता द्वारा स्टॉक इन्वेस्ट के उपयोग की कालावधि संबंधी प्रकटीकरणों को इस संबंध में भारिबैं के प्रचलित अनुदेशों के अनुरूप प्रस्ताव दस्तावेज में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंक, जिसके माध्यम से स्टॉक इन्वेस्ट निर्मोचित किये जायेंगे, का नाम प्रस्ताव दस्तावेज में दिया जायेगा। साथ ही उपयुक्त स्थान पर निम्न पैरा प्रकट किया जायेगा।

"न्यासी द्वारा निर्गम रजिस्ट्रार को निर्गमकर्ता बैंक से स्टॉक इन्वेस्ट के आगमों के निर्मोचन के लिए या लिखत पर गैर-आबंटन सूचना चिपकाने के लिए या गैर-आबंटितियों अथवा अंशतः सफल आबंटितियों जिन्होंने एक से अधिक स्टॉक इन्वेस्ट संलग्न किये थे, के स्टॉक इन्वेस्ट रद्द करने के लिए न्यासी की ओर से प्राधिकृत किया गया है। ऐसे रद्द किये गये स्टॉक इन्वेस्ट रजिस्ट्रारों द्वारा सीधे विनिधानकर्ताओं को वापस भेजे जायेंगे।"

स्टॉक इन्वेस्ट पर आदाता के खाते में चिह्नित होना चाहिए और सामूहिक विनिधान स्कीम - खाता स्कीम अंतर्लिखित होना चाहिए।

17. प्रतिपाद्य आदेश प्रेषित करना

प्रस्ताव दस्तावेज में निम्न खंड सम्मिलित किया जाना चाहिए :

"न्यासी 1500/- रु. से अधिक मूल्य के प्रतिदाय आदेशों और यूनिट प्रमाणपत्रों का केवल रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषण सुनिश्चित करेगा और इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रारों को पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध करायी जायेगी।"

18. आबंटन पत्रों / प्रतिदाय आदेशों के प्रेषण में विलंब के मामले में ब्याज

वर्तमान निर्गम के निबंधनों के अधीन सारांश कथन प्रकट होगा और उसमें निम्न अंतर्विष्ट होगा :

"न्यासी करार करता है कि यथासंभव जनता को प्रस्तावित यूनिटों का आबंटन निर्गम बंद होने के 30 दिनों के भीतर किया जायेगा। न्यासी आगे और करार करता है कि यदि आबंटन पत्र / प्रतिदाय आदेश निर्गम बंद होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित नहीं किये गये हैं तो यह 15% वार्षिक दर से ब्याज का संदाय करेगा।"

19. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

नियुक्त अनुपालन अधिकारी का नाम टेलिफोन संख्या, फैक्स संख्या और पता जहाँ वह उपलब्ध होगा / होगी, जैसे ब्यौरों सहित प्रस्ताव दस्तावेज में वर्णित किया जायेगा। विनिधानकर्ताओं का ध्यान किन्हीं निर्गमपूर्व / निर्गमोत्तर संबंधी समस्याओं के मामले में अनुपालन अधिकारी से संपर्क करने की ओर आकृष्ट किया जायेगा।

20. वचन के मुकाबले में कार्यनिष्पादन

"वचन के मुकाबले में कार्यनिष्पादन - सभी पूर्ववर्ती स्कीमें" शीर्षकवाला एक पृथक् पैरा यह उपदर्शित करते हुए दिया जायेगा कि क्या सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा चालू की गयी पूर्ववर्ती स्कीमों के संबंध में संबंधित प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित सभी उद्देश्य पूरे कर लिये गये थे और क्या कथित प्रस्ताव दस्तावेज में किये सभी प्रक्षेपण पूरे किये गये थे। यदि नहीं, तो उद्देश्यों / प्रक्षेपणों का पूरा न किया जाना सुस्पष्टतः प्रकट किया जायेगा (कमी / विलंब का परिमाण दिया जाना है)।

21. तीसरे पक्षों द्वारा स्टॉक इन्वेस्ट का उपयोग

स्टॉक का उपयोग क्रेता(ओं) द्वारा किया जाना चाहिए और क्रेता का नाम / क्रेताओं में से एक का नाम शेयर आवेदन प्रपत्र में प्रथम आवेदक के रूप में सदैव उपदर्शित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि स्टॉक इन्वेस्ट पर क्रेता के हस्ताक्षर और आवेदन प्रपत्र पर प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं तो आवेदन को तीसरे पक्ष के स्टॉक इन्वेस्ट के संग्रहण के रूप में समझा जाना चाहिए।

22. 10 दिनों के भीतर स्टॉक इन्वेस्ट का उपयोग

क्रेता (ओं) को निर्गम के 10 दिनों के भीतर स्टॉक इन्वेस्ट का उपयोग करना होता है और इस प्रयोजन के लिए, बैंक को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्टॉक इन्वेस्ट के उपयोग का अंतिम दिवस स्टॉक इन्वेस्ट के अग्रभाग पर ".....से पूर्व उपयोग किये जाने के लिए" अंकन के साथ उपदर्शित किया जाता है।

23. सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र

- i) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करते समय, एक सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।

ii) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी :-

क) यह भी प्रमाणित करेगी कि बोर्ड द्वारा सुझाये गये सभी संशोधनों / किये गये सभी संप्रेक्षणों को प्रस्ताव दस्तावेज में कार्यान्वित किया गया है;

ख) निर्गम के खुलने से तुरंत पहले एक नया प्रमाणपत्र भी देगी कि इसकी ओर से किसी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

ग) अभिधान के लिए निर्गम के खुलने के पश्चात् परंतु इसके बंद होने के पूर्व एक नया प्रमाणपत्र भी देगी।

24. सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी प्रस्ताव दस्तावेज के साथ निम्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी :-

- i) पिछले निर्गमों के सभी प्रतिदाय आदेश विहित समय में और विहित रीति में प्रेषित कर दिये गये थे।
- ii) सभी यूनिट प्रमाणपत्र विहित समय में और विहित रीति में आबंटितियों को प्रेषित कर दिये गये थे; और

25. अन्य मध्यवर्तियों की नियुक्ति

- i) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को जहाँ भी अपेक्षित हो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियुक्त किये जानेवाले मध्यवर्ती बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हैं। सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी विभिन्न मध्यवर्तियों की निर्गम प्रबंध की क्षमता और सामर्थ्य का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करेगी।
- ii) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आज्ञापक संग्रहण केंद्रों में निर्गम बैंककार नियुक्त किये गये हैं।
- iii) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत निर्गम रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गयी है।
- iv) निर्गम रजिस्ट्रार जो सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से संप्रवर्तक या निदेशक के रूप में सहयुक्त है को उस निर्गम के लिए रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

26. प्रस्ताव दस्तावेज को सार्वजनिक किया जाना

बोर्ड के पास दाखिल किये गये प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को बोर्ड के पास प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने की तारीख से 21 दिन की कालावधि के लिए सार्वजनिक किया जायेगा। सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी जनता को प्रस्ताव दस्तावेज की प्रतियाँ उपलब्ध करायेगी। सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी प्रति के लिए अनुरोध करनेवाले व्यक्ति से समुचित राशि प्रभारित कर सकती है।

27. निर्गम सामग्री का प्रेषण

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव दस्तावेज और अन्य निर्गम सामग्रियाँ निर्गम बैंककारों, निवेशक संघों आदि को अग्रिम रूप में प्रेषित की गयी हैं।

28. कोई शिकायत न होने का प्रमाणपत्र

प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के सार्वजनिक किये जाने की तारीख से 21 दिनों की कालावधि के पश्चात् सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी भाप्रविबो के पास एक विवरणी दाखिल करेगी :

- i) इसके द्वारा प्राप्त शिकायतों की सूची देते हुए,
- ii) इसके द्वारा एक कथन कि क्या प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को संशोधित करना प्रस्तावित है या नहीं, और;
- iii) उन संशोधनों पर प्रकाश डालते हुए।

29. आज्ञापक संग्रहण केंद्र

कम से कम 30 आज्ञापक संग्रहण केंद्र होने चाहिए जिसमें सदैव वे स्थान शामिल होने चाहिए जहाँ स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं।

30. प्राधिकृत संग्रहण एजेंट

- i) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी भी प्राधिकृत संग्रहण एजेंटों को प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित होनेवाले ऐसे एजेंटों के नाम और पते सहित आवश्यक प्रकटीकरणों के अध्यक्षीन नियुक्त करने के लिए अनुज्ञात है। यद्यपि संग्रहण एजेंटों के चयन और नियुक्ति की रीति को सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार चयनित एजेंट इस प्रयोजन के लिए अवसंरचना और जनशक्ति संबंधी अपेक्षाओं दोनों के अनुरूप समुचित रूप से लैस हैं।
- ii) संग्रहण एजेंटों को ऐसे आवेदनों जो चेकों, ड्राफ्टों और स्टॉक इन्वेस्टों द्वारा संदत्त आवेदन धन के संदाय युक्त हैं के संग्रहण की अनुज्ञा होनी चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में उन्हें नकद रूप में आवेदन धन संग्रह करने की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए।
- iii) इस प्रकार संग्रहित आवेदनों को या तो उसी तारीख को या अगले कार्यदिवस तक पदनामित अनुसूचित बैंक के पास विशेष यूनिट आवेदन खाता में जमा कर दिया जायेगा। निर्गम बंद होने की तारीख से दो सप्ताह की कालावधि के भीतर, चेकों की वसूली के पश्चात् और चेक के वापस लौटने के मामलों की बाबत आवेदनों की छँटाई के पश्चात् सम्यक् रूप में समाधान की गयी अनुसूचियों सहित आवेदन प्रपत्रों को निर्गम रजिस्ट्रारों के पास प्रेषित किया जायेगा।
- iv) स्टॉक इन्वेस्टों से संलग्न आवेदनों को निर्गम बंद होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अनुसूचियों के साथ सीधे निर्गम रजिस्ट्रारों को भेज दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव दस्तावेज और आवेदन प्रपत्रों में विशेष रूप से उपदर्शित होना चाहिए कि संग्रहण एजेंटों द्वारा दी गयी आवेदन धन की प्राप्ति की अभिसूचना वैध और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी और निर्गम से संबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगी।

- v) उन स्थानों से जहाँ आशपक संग्रहण केंद्र और प्राधिकृत संग्रहण एजेंट अवस्थित हैं, भिन्न स्थानों के विनिधानकर्ता उनके आवेदन स्टॉक इन्वेस्टों के साथ रजिस्ट्री रसीदों द्वारा सीधे निर्गम रजिस्ट्रारों को भेज सकते हैं और ऐसे आवेदनों को निर्गम रजिस्ट्रारों द्वारा सामान्य प्रकार से बरता जायेगा।

31. क) निर्गमोत्तर अनुश्रवण रिपोर्ट

सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी अधिदान के स्तर का विचार किये बिना निर्गमोत्तर अनुश्रवण रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करेगी। इन रिपोर्टों को नियत तारीखों से 3 कार्यदिवसों के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ख) 3 दिवस निर्गमोत्तर अनुश्रवण रिपोर्ट

इस रिपोर्ट के लिए नियत तारीख निर्गम के अधिदान के बंद होने की तारीख से तीसरे दिन होगी।

ग) 98 दिवस निर्गमोत्तर अनुश्रवण रिपोर्ट

इस रिपोर्ट के लिए नियत तारीख निर्गम के अधिदान के बंद होने की तारीख से 98 वें दिन होगी।

32. निर्गम बैंककार

न्यासी सुनिश्चित करेगा कि निर्गम के अनुसरण में प्राप्त धनराशियों का उपयोग केवल प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित न्यूनतम अधिदान प्राप्त हो जाने और निर्गम रजिस्ट्रारों द्वारा इस आशय का कथन दिये जाने के बाद ही किया जायेगा।

33. निर्गमोत्तर विज्ञापन

33.1 सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सुनिश्चित करेगी कि सभी निर्गमों में, अत्याधिदान, आबंटन का आधार, स्टॉक इन्वेस्ट के साथ प्राप्त आवेदनों की संख्या, मूल्य और प्रतिशत, सफल आबंटितियों, जिन्होंने स्टॉक इन्वेस्ट के माध्यम से आवेदन किया है, की संख्या, मूल्य और प्रतिशत, प्रतिदाय आदेशों का प्रेषण पूरा होने की तारीख, प्रमाणपत्रों के प्रेषण की तारीख से संबंधित ब्यौरे देनेवाला विज्ञापन विभिन्न कार्यकलापों के समापन की तारीख से 10 दिनों के भीतर कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिकों में प्रकाशित किया गया है।

33.2 सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सुनिश्चित करेगी कि सलाहकारों / दलालों या निर्गम से संबंधित अन्य कोई एजेंसियाँ उस कालावधि के दौरान जब सार्वजनिक निर्गम जनता से अधिदान के लिए अभी खुला ही है, यह कथन करते हुए कि निर्गम अत्याधिदत्त हो गया है या निर्गम के प्रति विनिधानकर्ताओं की प्रतिक्रिया उपदर्शित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित नहीं करती है।

33.3 विज्ञापन निर्गम की वास्तविक समाप्ति के पश्चात् यह कथन करते हुए जारी किया जा सकेगा कि अधिदान सूची बंद कर दी गयी है।

34. अन्य दायित्व

34.1 अभिदान राशियों / अधिक अभिदान के प्रतिदाय में विलंब के मामले में, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सुनिश्चित करेगी कि आवेदकों की विलंब अवधि, जैसा कि प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित है के लिए ब्याज का संदाय किया जाता है।

34.2 सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सुनिश्चित करेगी कि प्रतिदाय आदेशों / आबंटन पत्रों / शेयर प्रमाणपत्रों का प्रेषण यथाप्रयोज्य रजिस्ट्रीकृत डाक / डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के रूप में किया जाता है।

35. स्टॉक इन्वेस्ट की वसूली से संबंधित प्रमाणपत्र

- i) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी आबंटन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, न्यासी को यह प्रमाणित करते हुए कि स्टॉक इन्वेस्ट जिनके आधार पर आबंटन को अंतिम रूप दिया गया है, निर्मोचित किये गये हैं एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।
- ii) स्कीम के लिए अभिदान सूची को 90 कार्यदिवसों से अधिक दिनों के लिए खुला नहीं रखा जायेगा और यह तथ्य प्रारूप दस्तावेज में प्रकट किया जायेगा।

36. अतिअभिदान का प्रतिधारण

निर्गम का परिमाण प्रस्ताव दस्तावेज में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा। तथापि, आबंटन को अंतिम रूप देते समय 100 के निकटतम गुणज में पूर्णांकन के प्रयोजन के लिए उल्लिखित राशि के 10 % की सीमा तक अत्यभिदान अनुज्ञेय है।

37. प्रस्ताव दस्तावेज को अद्यतन बनाना

- i) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उसमें अंतर्विष्ट विशिष्टियाँ (लेखापरीक्षित विवरणी) निर्गम खुलने की तारीख से 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होंगी।
- ii) यूनियों के अंतरण और पारेषण पर निर्बंधन, यदि कोई हो।
- iii) स्कीमों के विनिधानों का कर परिकलन।

स्कीम के यूनितधारकों को उपलब्ध विभिन्न कर फायदों और प्रभारित करों का विस्तृत आलेख।

38. आबंटन का आधार

जनता को यूनियों के प्रत्येक निर्गम में जो कि अत्यभिदत्त हो गया है, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी और निर्गम रजिस्ट्रार, सुनिश्चित करेंगे कि आबंटन निम्न रीति में किये जाते हैं :

क) समानुपातिक आबंटन प्रक्रिया :

आबंटन नीचे स्पष्ट किये गये अनुसार आनुपातिक आधार पर विपण्य लॉट में आबंटन के अध्यक्षीन होंगे :

- (i) आवेदक आवेदित यूनियों की संख्या के अनुसार श्रेणीबद्ध किये जायेंगे।

- (ii) समग्र तौर पर प्रत्येक प्रवर्ग में आबंटित किये जानेवाले यूनिटों की कुल संख्या आनुपातिक आधार पर परिनिर्धारित की जायेगी अर्थात् उस प्रवर्ग में आवेदित यूनिटों की कुल संख्या (प्रवर्ग में आवेदकों की संख्या X आवेदित यूनिटों की संख्या) का अत्यभिदत्त अनुपात के व्युत्क्रम से गुणा, जैसा कि नीचे दृष्टांत दिया गया है :

100 के प्रवर्ग में आवेदकों की कुल संख्या - 1500

आवेदित यूनिटों की संख्या - 1,50,000

अत्यभिदत्त होने की संख्या - 3

प्रवर्ग में समानुपातिक आबंटन - $1,50,000 \times \frac{1}{3}$
 $= 50,000$

सफल आबंटितियों को आबंटित किये जानेवाले यूनिटों की संख्या का परिनिर्धारण समानुपातिक आधार पर होगी अर्थात् उस प्रवर्ग में प्रत्येक आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों की कुल संख्या का अत्यभिदान अनुपात के व्युत्क्रम से गुणा।

प्रत्येक आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों की संख्या - 100

अत्यभिदत्त होने की संख्या - 3

प्रत्येक सफल आवेदक को समानुपातिक आबंटन - $100 \times \frac{1}{3} = 33$

(100 में पूर्णांकन किया जाए)

- (iii) सभी आवेदन, जहाँ आनुपातिक आबंटन 100 यूनिट प्रति आवेदक से कम निकलता है, आबंटन निम्नानुसार किये जायेंगे:

* प्रत्येक सफल आवेदक को न्यूनतम 100 यूनिट आबंटित किये जायेंगे; और

- iv) * उस प्रवर्ग के कुल आवेदकों में से सफल आवेदकों का निर्धारण ऐसी रीति से लॉट का आहरण करके किया जायेगा कि उस प्रवर्ग में आबंटित यूनिटों की कुल संख्या उपर्युक्त (ii) में गणना किये यूनिटों की संख्या के बराबर हो।
- v) यदि आवेदक को आनुपातिक आबंटन की गणना ऐसी संख्या में आती है जो 100 से अधिक है पर 100 का गुणज नहीं है (जो विषण्य लॉट है), 100 के गुणज से अधिक की संख्या 100 के उच्चतर गुणज में पूर्णांकित होगी यदि वह संख्या 50 या उससे उच्चतर है। यदि वह संख्या 50 से कम है, तो वह 100 के निम्नतर गुणज में पूर्णांकित होगी। (दृष्टांत के तौर पर, यदि आनुपातिक आबंटन की गणना 250 आती, तो आवेदकों को 300 यूनिट आबंटित होंगे। तथापि यदि आनुपातिक आबंटन की गणना 240 आती है तो आवेदकों को 200 यूनिट आबंटित होंगे।) ऐसे प्रवर्ग में सभी आवेदकों को ऐसे पूर्णांकन के बाद परिनिर्धारित यूनिट आबंटित होंगे।
- vi) यदि किसी प्रवर्ग को आनुपातिक आधार पर आबंटित यूनिट उस प्रवर्ग के आवेदकों को आबंटित यूनिटों से अधिक हैं, आबंटन के लिए उपलब्ध शेष यूनिट पहले यूनिट की 1000 संख्या के लिए आवेदन करनेवाले आवेदकों को समाविष्ट करनेवाली प्रवर्ग के प्रति समायोजित किये जायेंगे और तत्पश्चात् शेष, यदि कोई अधिशेष अभी भी रह जाए, को अगले उच्चतर प्रवर्ग के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए और इसी प्रकार जब तक कि अधिशेष का पूरी तरह उपयोग न हो जाए।

- vii) चूँकि 100 के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वास्तविक आबंटन प्रस्तावित यूनिटों से उच्चतर हो सकता है, 10% मार्जिन की अनुज्ञा देना आवश्यक होगा अर्थात् अंतिम आबंटन प्रस्ताव के आकार के 110% तक उच्चतर हो सकेगा।

39. प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख

प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख वह तारीख मानी जायेगी जब प्रस्ताव दस्तावेज बोर्ड के पास दाखिल किया गया था।

40. न्यास विलेख

(क) प्रस्ताव तारीख में सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित न्यास विलेख की तारीख और के पक्ष उल्लिखित होंगे।

(ख) न्यास विलेख के उपबंधों और न्यासी तथा सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की निवृत्ति, हटाने और प्रतिस्थापन संबंधी विनियमों का सारांश।

41. स्कीम और विनिधान

सभी प्रस्ताव दस्तावेजों में निम्न अंतर्विष्ट होगा :

(क) सभी प्रस्ताव दस्तावेजों में प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती 5 वर्षों के भीतर सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा संचालित जनता को यूनिटों के निर्गम को अंतर्वर्तित करनेवाली अन्य प्रत्येक स्कीम का नाम और वर्णन तथा परिचालन आरंभ करने की तारीख अंतर्विष्ट होगी।

(ख) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा, प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख से अधिकतम 28 दिन पूर्व की तारीख तक स्कीम से संबंधित किये गये चालू विनिधान का संक्षिप्त रूप देते हुए एक रिपोर्ट।

(ग) प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों के भीतर सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा चालू की गयी अन्य किसी स्कीम से संबंधित यूनिटों के प्रत्येक निर्गम की बाबत लेखापरीक्षक की एक रिपोर्ट, ऐसी जानकारी देते हुए जो प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों जिनमें वे यूनिट अस्तित्व में थे, सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित यूनिटों के धारकों को आय के संवितरण (यदि कोई हो) की संख्या, राशि और प्रत्येक संवितरण तथा संवितरण के घटकों में से प्रत्येक का स्वरूप और मूल्य पर्याप्त रूप से प्रकट करती हो।

(घ) स्कीम के लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों जिनके दौरान सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी कारबार कर रही थी में से प्रत्येक की बाबत सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के लाभ और हानियाँ और उन वर्षों में से प्रत्येक की बाबत कंपनी द्वारा संदत्त लाभांशों (यदि कोई हो) की दरें और सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी की उस अंतिम तारीख जब इसके लेखे बनाये गये हों, जो प्रस्ताव दस्तावेज के निर्गम की तारीख से अधिक से अधिक 12 महीने पूर्व की हो, को आस्तियाँ और देयताओं का वर्णन करते हुए रिपोर्ट।

सातवीं अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

[विनियम 27(1)]

विज्ञापन संहिता

1. स्कीम विज्ञापन :

- क) सत्य, ऋजु और स्पष्ट होगा और उसमें ऐसा कोई कथन अंतर्विष्ट नहीं होगा जो असत्य या भ्रामक हो।
- ख) स्पष्ट, संक्षिप्त और समझनेयोग्य भाषा में उपवर्णित होगा। तकनीकी, विधिक शब्दावली या जटिल भाषा के व्यापक उपयोग और अत्यधिक ब्यौरों, जो विनिधानकर्ताओं का प्रत्याहरण करें, को शामिल करने से बचना चाहिए।
- ग) में कथन अंतर्विष्ट नहीं होंगे जो तीव्र लाभों के अधिमूल्यन का वायदा करें या गारंटी दें।
- घ) में ऐसी कोई जानकारी या भाषा अंतर्विष्ट नहीं होगी जो प्रस्ताव दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं है।
- ङ) में स्कीम के सामान्य वाणिज्यिक नाम के अलावा आकर्षक वाक्य (स्लोगन) या ब्रांड नाम सम्मिलित नहीं होगा।
- च) के लिए कोई आकर्षक वाक्य (स्लोगन), शपथ या अवास्तविक और प्रमाणरहित शीर्षक नहीं होंगे।
- छ) में जोखिम कारक मुद्रण आकार सहित सभी प्रकार से महत्त्व देते हुए अंतर्विष्ट होंगे। निर्गम विज्ञापनों में प्रमुख विशेषताओं और जोखिम कारकों का मुद्रण आकार 9 पॉइंट आकार से कम नहीं होना चाहिए। इसमें स्कीमों, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी, न्यासी के नाम और उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और निर्गम रजिस्ट्रारों के पते का उल्लेख होना चाहिए।
- ज) में संबंधित निर्गम की बाबत "जोखिम कारक" अंतर्विष्ट होंगे।

परंतु यह कि निर्गम खुलने / बंद होने के विज्ञापन जिसमें प्रमुख विशेषताएँ अंतर्विष्ट नहीं होती, में जोखिम कारकों का अंतर्विष्ट होना आवश्यक नहीं है।

2. निर्गम विज्ञापन को भ्रामक समझा जायेगा यदि उसमें निम्न अंतर्विष्ट होगा :

- i) आवश्यक स्पष्टीकारक या विशेषक कथनों के अभाव में स्कीम के कार्यनिष्पादन या क्रियाकलापों के बारे में किये गये कथन, जो कार्यनिष्पादन या क्रियाकलापों की वह जो वास्तविक रूप में है अतिशयोक्तिपूर्ण तस्वीर देते हों।
- ii) पिछले कार्यनिष्पादन का गलत चित्रण या इस रीति में इसका चित्रण जिससे कि विविक्षित हो कि पिछले अभिलाभों या आय की भविष्य में पुनरावृत्ति होगी।

3. प्रस्ताव दस्तावेज में अंतर्विष्ट किसी जानकारी को पुनः प्रस्तुत करनेवाले या पुनः प्रस्तुत करने का आशय रखनेवाले किसी विज्ञापन में ऐसी जानकारी पूर्ण रूप से पुनः प्रस्तुत होगी और सभी सुसंगत तथ्य प्रकट होंगे और उस मद से संबंधित उद्धरण चुनने तक ही सीमित नहीं होगा।
4. स्कीम के प्रस्ताव दस्तावेजों या विज्ञापनों में कोई मॉडेल, विख्यात व्यक्ति, काल्पनिक चरित्र, युगप्रवर्तक घटना या व्यंग्य-चित्र या सदृश प्रदर्शित नहीं किया जायेगा या उसका भागरूप नहीं होगा।

5. बोर्ड के पास प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के 21 दिनों के पश्चात् स्कीम की समाप्ति तक सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी कोई निगम विज्ञापन तब तक जारी नहीं करेगी जब तक प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लेख किये जाने के लिए यथा अपेक्षित जोखिम कारकों का ऐसे विज्ञापनों में उल्लेख नहीं किया गया हो।
6. कोई भी विज्ञापन यह कथन करते हुए कि अभिदान के लिए निर्गम के खुले रहने की अवधि के दौरान निर्गम पूर्णतः अभिदत्त हुआ या अत्यभिदत्त हुआ सिवाय इस आशय के कि निर्गम खुला है या बंद, जारी नहीं किया जायेगा। निर्गम बंद होने के संबंध में कोई आख्यापन नहीं किया जायेगा सिवाय बंद होने की अंतिम तारीख के। यदि स्कीम प्रस्ताव दस्तावेज में यथा कथित बंद होने की अंतिम तारीख से पहले पूर्णतः अभिदत्त हो जाता है तो निर्गम के पूरी तरह अभिदत्त हो जाने के बाद ही आख्यापन किया जायेगा और ऐसा आख्यापन उस तारीख को जिसको निर्गम बंद होता है किया जाए।
7. न्यासी का यह कि यूनिटों की कम से कम न्यूनतम संख्या अभिदत्त की गयी है और निर्गम रजिस्ट्रार से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है, समाधान हो जाने के बाद ही स्कीम बंद होने के संबंध में आख्यापन किया जायेगा।
8. निर्गम के पणन से सहयुक्त किसी को भी किसी विज्ञापन के माध्यम से किन्हीं प्रोत्साहनों का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा।
9. अनिवासी भारतीय के लिए आरक्षण की दशा में स्कीम विज्ञापन इसे विनिर्दिष्ट करेगा और भारत में वह स्थान उपदर्शित करेगा जहाँ से एकल अनिभा आवेदक आवेदन प्रपत्र उपाप्त कर सकता है।
10. विज्ञापन एक स्कीम की दूसरी स्कीम से स्पष्टतः या अस्पष्टतः तुलना नहीं करेगा, जब तक कि तुलना ऋजु न हो और तुलना से सुसंगत सभी जानकारी विज्ञापन में अंतर्वर्तित न हो।
11. यदि कोई विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम विज्ञापनों में स्कीम का पिछला कार्यनिष्पादन उपदर्शित करता है, तो प्रतिदाय / प्रतिफल और किये गये समायोजनों (कार्य और हो) की त्रों की संगणना का आधार इस कथन के साथ स्पष्टतः अवश्य उपदर्शित किया जाना चाहिए कि, ऐसी जानकारी भावी परिणामों का आवश्यकतः सूचक नहीं है और आवश्यक नहीं कि अन्य विनिधानों के साथ तुलना के लिए आधार प्रदान करे।
12. किसी स्कीम या इसकी सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के कार्यनिष्पादन पर विज्ञापन इन विनियमों के अनुसार केवल सांख्यिकी के प्रति यूनिट के आधार पर ही पिछले कार्यनिष्पादनों की तुलना करेंगे। शुद्ध आस्ति मूल्य के लिए विज्ञापनों में, यदि कोई हो, स्कीम का पिछला और साथ ही नवीनतम शुद्ध आस्ति मूल्य अवश्य उपदर्शित करेंगे। प्रतिफल परिगणना इन विनियमों में उपबंधित अनुसार की जायेगी।
13. न्यासी :
 - i) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा ऊपर उपवर्णित विज्ञापन संहिता के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
 - ii) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी से इस आशय का वचनपत्र प्राप्त करेगा कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी सम्मेलन के दौरान या किसी अन्य समय पर कोई सामग्री या जानकारी जो प्रस्ताव दस्तावेजों में अंतर्विष्ट न हो प्रकाशित नहीं करेगी।
 - iii) सुनिश्चित करेगा कि सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सभी स्कीम विज्ञापनों और प्रचार सामग्रियों की बाबत उनसे अनुमोदन अभिप्राप्त करती है।

आठवीं अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

[विनियम 51]

अधिवेशन संचालित करने की प्रक्रिया

अधिवेशन :

अधिवेशन संचालित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैं :

न्यासी या स्कीम की यूनिट पूँजी के अभिहित मूल्य का एक दहाई धारण करनेवाले यूनिट धारक नीचे उपवर्णित रीति में यूनिट धारकों का अधिवेशन बुला सकेंगे।

- i) यूनिट धारकों से सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर न्यासी, प्रत्येक यूनिट धारक को, या संयुक्त धारकों के मामले में, उस संयुक्त धारक को जिसका नाम अभिलेखों में पहला वर्णित हो, प्रस्तावित बैठक से कम से कम 7 दिन पहले प्रस्तावित अधिवेशन की डाक द्वारा सूचना भेजते हुए यूनिट धारकों का अधिवेशन बुलायेगा।
- ii) न्यासी प्रत्येक अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा।
- iii) कोई भी यूनिट धारक किसी दूसरे व्यक्ति को उसके परोक्षी के रूप में उसके बजाय उपस्थित होने और मत देने के लिए नियुक्त कर सकेगा।
- iv) इस प्रकार नियुक्त परोक्षी के पास बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- v) प्रत्येक यूनिट धारक के पास उसके (या उसके हक में पूर्ववर्ती) द्वारा पूँजी अभिदाय के प्रत्येक 1.00 यूनिटों के लिए एक मत होगा। विलेख या विनियमों में स्पष्टतः विपरीत उपबंधित होने के सिवाय, स्कीम से संबंधित सभी विनिश्चय साधारण संकल्प द्वारा होंगे। मतदान की समानता का परिणाम ऐसे संकल्प का हारना समझा जायेगा। अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा। एक असाधारण संकल्प लाया जायेगा यदि मतों का तीन चौथाई संकल्प के पक्ष में हों।
- vi) गणपूर्ति के बिना अधिवेशन में कोई कारबार का संव्यवहार नहीं किया जायेगा। गणपूर्ति की प्राप्ति होगी यदि स्कीम की यूनिट पूँजी के अभिहित मूल्य में कम से कम एक दहाई धारण करने वाले यूनिट धारक (परोक्षियों सहित) अधिवेशन में उपस्थित हैं।
- vii) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी एक कार्यवृत्त पुस्तक रखेगी जिसमें प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त और संकल्प अभिलिखित किये जायेंगे।
- viii) किसी भी अधिवेशन में अधिवेशन में मत पर संकल्प का विनिश्चय हाथ उठाने के आधार पर किया जायेगा जब तक कि अध्यक्ष द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित किसी यूनिट धारक द्वारा मतदान की माँग नहीं की जाए।
- ix) कार्यवृत्त में संकल्प की प्रविष्टि संकल्प के पक्ष में या विरोध में अभिलिखित मतों की संख्या का निश्चायक साक्ष्य होगी।
- x) यूनिट धारकों का संकल्प अविधिमान्य होगा यदि यह उन यूनिट धारकों के प्रति कपट गठित करता है जो संकल्प का विरोध करते हैं।

नवीं अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999

लेखा मानक, विनिधान और व्यय अधिकतम सीमा

[विनियम 21(13), 43(1), 44(4)(iii), 71(1)(ड)]

भाग I - व्ययों की अधिकतम सीमा

कतिपय व्ययों की अधिकतम सीमा

व्यय नीचे विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन हैं :

1. आरंभिक निर्गम व्यय

(क) इनमें निम्न सम्मिलित होंगे :

- प्रस्ताव दस्तावेज की लागत और संबंधित लागत;
- विपणन और विक्रय व्यय, एजेंट का कमीशन, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए;
- अग्रणी प्रबंधकों, यदि कोई हो, रजिस्ट्रारों और संग्रहणकर्ता बैंकों को फीस;
- आरंभिक रेटिंग और मूल्यांकन फीस।

(ख) इन व्ययों का वहन स्कीम द्वारा किया जायेगा।

(ग) ये व्यय निम्न से अधिक नहीं होंगे

- (i) 10 वर्षों तक की अवधिवाली स्कीम के लिए स्कीम के अधीन जुटायी गयी निधियों का 7.00 प्रतिशत और
- (ii) 10 वर्षों से अधिक अवधिवाली स्कीम के लिए स्कीम के अधीन जुटायी गयी निधियों का 9.00 प्रतिशत।

(घ) ये व्यय सात वर्षों से अनधिक अवधि या स्कीम की अवधि, जो भी कम हो, के दौरान बराबर अपाकृत किये जायेंगे।

2. साविप्रक को प्रबंधन और सलाहकार फीस

(क) ऐसी फीस में निम्न समाविष्ट होंगे :

- मूल फीस
- प्रोत्साहन फीस

(ख) 'मूल फीस' निम्न से अधिक नहीं होगी :

- (i) स्कीम के परिचालन के पहले पाँच वर्षों के लिए स्कीम के अधीन जुटायी गयी निधि का प्रतिवर्ष 1.00 प्रतिशत
- (ii) स्कीम के परिचालन के अगले पाँच वर्षों के लिए स्कीम के अधीन जुटायी गयी निधि का प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत
- (iii) उसके बाद स्कीम के समाप्त होने तक अनुवर्ती अवधि के लिए स्कीम के अधीन जुटायी गयी निधि का प्रतिवर्ष 1.50 प्रतिशत

प्रोत्साहन फीस

प्रोत्साहन फीस स्कीम की समाप्ति के समय प्रस्ताव दस्तावेज में यथादर्शित उपदर्शी प्रतिदाय (यूनिट पूँजी को छोड़कर) से अधिक वसूल किये गये अतिरिक्त प्रतिदाय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि स्कीम की समाप्ति पर प्रतिदाय प्रस्ताव में यथादर्शित उपदर्शी प्रतिदाय से कम है या के बराबर है तो कोई प्रोत्साहन फीस संदाय नहीं की जायेगी।

3. अन्य व्यय

स्कीम द्वारा केवल निम्न व्ययों का वहन किया जायेगा अर्थात् :

- विक्रीत या मोहित यूनिटों के अंतरण के लिए रजिस्ट्रार सेवाएँ
- न्यासियों की फीस और व्यय
- लेखापरीक्षण फीस
- पश्चात्कर्ती साख निर्धारण और मूल्यांकन फीस
- सूचीबद्धकरण फीस
- भाप्रविबो द्वारा यथाअनुमोदित अन्य प्रत्यक्ष लागत (यदि कोई हो)

4. अन्य सभी व्ययों का वहन साविप्रक द्वारा किया जायेगा।

भाग II - लेखा मान

बागान स्कीम

1. बागान स्कीमों के लिए लेखा मान

2. यूनिट पूँजी

- 2.1 स्कीम के अभिदान हेतु खुले होने की कालावधि के दौरान, विनिधानकर्ता से प्राप्त सभी धनराशियाँ, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जायें, स्कीम की यूनिटों की बिक्री हेतु मानी जायेंगी और यूनिट पूँजी के रूप में गणना की जायेगी।
- 2.2 यूनिट पूँजी स्कीम के तुलनपत्र में "निधियों के स्रोत" शीर्ष के अधीन प्रकटीकृत की जायेगी (उसी रीति में जैसे कि एक परिसीमित कंपनी के मामले में शेयर पूँजी)। यूनिट पूँजी का कोई भी अंश किसी भी परिस्थिति में राजस्व या किसी अन्य खाते में प्रभाजित नहीं किया जायेगा।

3. भूमि से संबंधित लागत

- 3.1 स्वामित्व अधिकारों के साथ अर्जित भूमि, भासलेस (आईसीएआई) द्वारा "अचल आस्तियों के लिए लेखा" पर लेखा मानक 10 ('ले मा-10') के अनुसरण में, अचल आस्ति के रूप में गणना होनी चाहिए।

स्वामित्व अधिकारों वाली भूमि के संबंध में भूमि की लागत 'फसल विकास व्ययों' के समुचित प्रभार द्वारा स्कीम अवधि पर अपाकृत होनी चाहिये।

- 3.2 पट्टे पर अर्जित भूमि निम्नलिखित के प्रतिकर हो सकती है -

- प्रीमियम (अप्रतिदेय) का संदाय ; या
- मासिक या आवधिक पट्टा किरायों का संदाय

अप्रतिदेय प्रीमियम के संदाय के प्रति अर्जित भूमि अचल आस्ति के रूप में गणना होनी चाहिये और अचल आस्ति अनुसूची में पृथक् रूप से प्रकटीकृत होनी चाहिये। पट्टा-धारित भूमि के लिए संवत्त ऐसा प्रीमियम भूमि की लागत के रूप में पूँजीकृत किया जाना चाहिये और पट्टे की अवधि या स्कीम की अवधि, जो भी कम हो, पर अपाकृत होना चाहिये।

आवधिक पट्टा किरायों के भुगतान के विरुद्ध अर्जित भूमि के संबंध में, ऐसी राशियाँ लाभ और हानि खाते को प्रभारित होगी।

वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित प्रकटीकरण अपेक्षित हैं :

- पट्टे की अवधि
- भूमि का स्वामी
- न्यासियों और सा.वि.प्र.कं. के निदेशकों के साथ स्वामी का संबंध

- यदि पट्टा अवधि स्कीम की अवधि से कम है, तो पट्टे की अवधि और पट्टे के भावी नवीकरण की शर्तें ।

3.3 भूमि विकास व्यय

इनमें निम्न पर व्यय सम्मिलित हैं :

- नई पहुँच सड़कें और बाड़
- भूमि समुच्चय रेखा में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- समतलन, उखाड़न और सोपान बनाना
- भूमि की नियमित देखभाल और अभिरक्षण

पूँजी प्रकृति के व्यय भूमि की लागत में जोड़े जाने चाहियें ।

पट्टाधारित भूमि के मामले में, ये व्यय पट्टे की अवधि या स्कीम की अवधि, जो भी कम हो, पर बट्टे खाते डाले जाने चाहियें ।

राजस्व स्वरूप के व्यय लाभ और हानि खाते को उस वर्ष में जिसमें वे उपगत हुए हैं प्रभारित किये जाने चाहियें ।

3.4 अवसंरचना और अन्य सुविधाओं में शामिल होंगे :

- सड़कें और बाड़
- सुरक्षा और अनुसंधान और विकास इमारतें
- ड्रिप सिंचाई प्रणालियाँ, जल प्रणालियाँ
- कृषि उपकरण और उत्पादन सुविधाएँ

ये भासलेसं द्वारा “अचल आस्तियों के लिए लेखा” पर ले.मा.10 के अनुसरण में अचल आस्तियों के रूप में गणना होनी चाहिये ।

- 3.5 अं ले मा 36 अपेक्षा करता है कि आस्तियों के संबंध में अपसामान्य हानियों की पहचान की जानी चाहिये । अपसामान्य वहाँ उत्पन्न होता है जब कभी भी एक आस्ति की वाहक धनराशि इसकी वसूलीयोग्य धनराशि के आधिक्य में होती है । सभी अपसामान्य हानियों के लिये प्रावधान किया जाना चाहिये ।

- 3.6 यदि ऐसी आस्तियाँ पट्टे पर ली गयी हों, तब व्यय की गयी राशि की गणना उसी आधार पर होनी चाहिये जैसे कि पैरा 3.2 में वर्णित हैं और उसमें वर्णित प्रकटीकरण अपेक्षाएँ भी लागू होंगी ।

4. अचल आस्तियाँ (भूमि और संबंधित अवसंरचना सुविधाओं के अलावा)

- 4.1 ऐसी अचल आस्तियों की गणना, भासलेसं द्वारा “अचल आस्तियों के लिए लेखा” पर ले.मा 10 के अनुसरण में गणना की जानी चाहिये - मूलतः कि एक अचल आस्ति की लागत इसके क्रय मूल्य और इसके आशयित उपयोग के लिये आस्ति को इसकी कार्य स्थिति तक लाने के लिए मानी जा सकने वाली लागत को समाविष्ट करती है ।

- 4.2 ये आस्तियाँ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्य-ह्रासित होनी चाहिये ।

- 4.3 प्राप्त पूँजी अनुदानों को भासलेसं द्वारा “सरकारी अनुदानों के लिये लेखाकरण” पर लेखामानक (ले मा)-12 के अनुसरण में गणना की जानी चाहिये - मूलतः कि अनुदान की

मान्यता शर्तों की अनुपालना के आश्वासन और प्राप्तियों की निश्चितता पर निर्भर होनी चाहिये और विनिर्दिष्ट अचल आस्तियों से संबद्ध अनुदान उनका बही मूल्य निर्धारण करने में आस्तियों के सकल मूल्य से घटाये जाने चाहियें ।

- 4.4 भालेमा (आईएस) 36 द्वारा यथा अपेक्षित के अनुसार आस्तियों के संबंध में अपसामान्य हानियों की पहचान की जानी चाहिये । अपसामान्यता वहाँ उत्पन्न होती है जब कभी एक आस्ति की वाहक राशि इसकी वसूलीयोग्य राशि के आधिक्य में होती है ।
- 4.5 यदि ऐसी आस्तियाँ पट्टे पर ली गयी हैं, तब व्यय की गयी धनराशियाँ की गणना उसी आधार पर की जायेगी जैसा कि पैरा 3.2 में वर्णित हैं और उसमें वर्णित प्रकटीकरण अपेक्षाएँ भी लागू होंगी ।

5. फसल विकास व्यय

5.1 सामान्यतः फसलों के विकास और देखभाल पर व्यय उपगत होते हैं । इसमें निम्न पर व्यय शामिल हैं :-

- मृदा खादकरण
- बालवृक्ष और फसल रोपण
- फसल की नियमित देखभाल और अनुरक्षण
- भूमि और अन्य आस्तियों के लिये संदत्त पट्टा किराया जो सीधे फसल विकास के लिये किया गया माना जा सकता हो ।
- भूमि की लागत से संबंधित स्कीम अवधि के दौरान अनुपातिक रूप से अपाकृत धनराशि
- अचल आस्तियों का मूल्यहासन और अनुरक्षण, जो सीधे फसल विकास के लिये किया गया माना जा सके ।
- अन्य व्यय जो प्रत्यक्षतः फसल विकास के लिये किये गये माने जा सकें ।

इन व्ययों की गणना “फसल विकास व्ययों” के रूप में की जानी चाहिये । ये तुलनपत्र में “अचल आस्तियाँ” और “चालू आस्तियाँ” के बीच में एक पृथक् मद के रूप में प्रकटीकृत किये जाने चाहियें ।

5.2 फसल विकास व्ययों के योग की वर्षांत पर “शुद्ध वसूलीयोग्य कीमत” (शुक्की) से तुलना की जानी चाहिये । शुक्की से सामान्यतः तात्पर्य होगा वह राशि जो सामान्य अनुक्रम में वसूल होगी यदि उस दिन खड़ी फसलों का व्ययन कर दिया जाये । शुक्की फसल को भविष्य में परिपक्वता तक लाने में उपगत की जाने वाली अनुमानित लागत और विक्रय करने में आवश्यक रूप से उपगत की जाने वाली लागत को कारबार के सामान्य अनुक्रम में अनुमानित विक्रय मूल्य से कम करने के आधार पर अवधारित किया जा सकता है । यदि शुक्की वर्षांत पर फसल विकास व्ययों के योग से कम हो, तब इन दो संख्याओं के बीच अंतर के लिए एक समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये और निम्नानुसार प्रकटीकृत किया जाना चाहिये :

फसल विकास व्यय (लागत पर)
घटाये : मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

क

ख

क - ख

- 5.3 फसल विकास व्यय और कमी के लिए उपबंध, सकल मूल्यों पर अगले वर्ष में अग्रणीत किये जायेंगे । प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक समरूप प्रक्रिया अपनायी जायेगी । यदि द्वितीय या पश्चात्तर्ती वर्ष की समाप्ति पर शुक्की संबंधित वर्ष में लागत से अधिक/या बराबर है, तो इसे केवल उस परिमाण तक जिसका विगत में उपबंध किया गया था, लाभ एवं हानि खाते के जमा में अंतरण करके उपबंध खाते की प्रतिपूति करना संभव होगा । लागत या शुक्की के निम्नतर पर मूल्यांकन का आधार सिद्धांत प्रत्येक वर्ष लागू होगा । यदि फसल ऐसे प्रक्रम में है कि शुक्की अवधारित करना संभव नहीं है, ये व्यय लागत पर मूल्यांकित किये जाने चाहियें और उस आशय का एक समुचित प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों में किया जाना चाहिये । ये व्यय या तो चरणों में या समापन-बिंदु पर, फसलों की बिक्री से उद्भूत आय के विरुद्ध समंजित किये जायेंगे ।
- 5.4 इस व्यय की अलग ही तरह की प्रकृति और दीर्घ उत्पादन चक्र पर विचार करते हुए, "फसल विकास व्यय" को "अचल आस्तियों और चालू आस्तियों" के बीच में अलग से प्रकटीकृत किया जाना चाहिये जैसा कि ऊपर पैरा 5.1 में चर्चा की गयी है ।

6. विनिधान

- 6.1 सभी विनिधान अवधारित लागत के निम्नतर और उचित मूल्य पर किये जाने चाहियें या तो वैयक्तिक विनिधान आधार पर या विनिधान के प्रवर्ग द्वारा लेकिन एक समग्र (या सार्वभौमिक) आधार पर नहीं ।
- 6.2 उत्कथित विनिधानों की बाबत, बाज़ार मूल्य सामान्यतः उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य प्रदान करता है ।
- 6.3 ऋण लिखतों में अनुत्कथित विनिधान प्रतिफल से परिपक्वता आधार पर मूल्यांकित होने चाहियें, तुलनयोग्य व्यापारित विनिधानों के लिए पूँजीकरण कारक अवधारित होते हुए और निम्न तरलता के लिये एक समुचित बट्टे के साथ ।

7. मालसूची मूल्यांकन

फसल विकास व्ययों के अलावा सूचियाँ, सूची मूल्यांकन पर ले.मा 2 द्वारा अधिकथित मूल सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकित की जानी चाहिये - सूची लागत के निम्न और शुद्ध वसूलीयोग्य कीमत पर मूल्यांकित की जानी चाहिये और मूल्यांकन के लिये लेखा नीति वित्तीय विवरणों में प्रकटीकृत की जानी चाहिये ।

8. राजस्व निर्धारण :

- 8.1 राजस्व का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा "राजस्व निर्धारण" पर जारी लेखा मानक ("ले मा") 9 के अनुसार किया जाना चाहिये, उस परिमाण तक जहाँ तक

यह लागू हो - राजस्व का निर्धारण केवल तभी होना चाहिये यदि संग्रहणीयता या मापकता की एक युक्तियुक्त निश्चितता है।

8.2 आय सामान्यतः निम्नलिखित स्रोतों से उद्भूत होगी -

- फसलों की बिक्री - आवधिक अंतरालों पर होने वाली फसलों की बिक्री से प्राप्तियों की गणना उस वर्ष के दौरान जिसमें बिक्री प्रभावी हुई है की जानी चाहिये। ऐसे बिक्री आगमों को आबंटनीय लागत फसल विकास व्यय खाते के प्रति मुजराई की जानी चाहिये और अधिशेष, यदि कोई हो, लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किया जाना चाहिये।
- अवशिष्ट एवं रद्दी की बिक्री - बिक्री प्राप्तियों की गणना बिक्री के वर्ष में आय के रूप में की जायेगी और लाभ एवं हानि खाते में जमा होंगी।
- विनिधानों से आय - अधिशेष बैंक बकाया इत्यादि के विनिधानों से उद्भूत आय की गणना बकाया राशि और प्रयोज्य दर पर विचार करते हुए, समय अनुपात आधार पर होगी।
- विनिधानों से लाभांश - लाभांशों, यदि कोई हों, का निर्धारण जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो तब किया जायेगा।
- समापन बिंदु पर खड़ी फसलों की बिक्री - समापन बिंदु पर, खड़ी फसलों की बिक्री प्राप्तियों/अंतरण मूल्य की गणना तब होगी जब कभी वे व्ययनित/अंतरित किये जायें। ऐसे संव्यवहारों पर उद्भूत बही मूल्य से अधिक लाभ की गणना बिक्री/व्ययन बिंदु पर की जायेगी; इसे फसल विकास व्ययों के विरुद्ध समंजित किया जायेगा।

9. व्यय

9.1 फसल विकास व्ययों के अलावा व्ययों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

- आरंभिक विपणन और चालू करने के व्यय
- सामान्य कारबार व्यय

9.2 प्रारम्भिक निर्गम व्यय

प्रारम्भिक निर्गम व्ययों को आठ वर्षों या स्कीम की अवधि पर, जो भी पहले हो, में बटूटे खाते में डाले जाने वाले आस्थिगत राजस्व व्ययों की तरह माना जा सकता है।

9.3 सामान्य कारबार व्ययों में शामिल होंगे :

- बेची गयी या मोचित यूनिटों के अंतरक के लिये रजिस्ट्रार सेवाएँ
- सा.वि.प्र.कं. और न्यासी फीस
- मूल्य ह्रास
- लेखापरीक्षा फीस
- पञ्चातृती रेटिंग और अंकन फीस
- सूचीबद्धकरण फीस

- अन्य लागतें, यदि कोई हों, जो स्कीम के परिचालन के लिये प्रासंगिक हैं, जो न्यासियों द्वारा अनुमोदित किये गये हों ।
- ये व्यय उस वर्ष जिसमें वे उपगत हुए हैं के व्यय माने जायेंगे और लाभ एवं हानि लेखा में बटूटे खाते डाले जायेंगे ।

10. विनिधानकर्ताओं को प्रतिलाभ

- 10.1 सामूहिक विनिधान स्कीम की बाबत विनिधानकर्ताओं को अंतरिम प्रतिलाभ केवल सामूहिक विनिधान स्कीम के वितरणयोग्य अधिशेष में से ही किये जा सकते हैं । अंतरिम प्रतिलाभ केवल नकद ही संदाय किये जा सकते हैं वस्तु रूप में नहीं ।
- 10.2 “वितरणयोग्य अधिशेष” से तात्पर्य है, निम्न के बाद सामूहिक विनिधान स्कीम के लाभ :
- मूल्यह्रास सहित उपचय आधार पर सभी व्ययों का उपबंध करना जैसा कि ऊपर पैरा 4.2 में चर्चा की गयी ।
 - फसल विकास व्ययों के मूल्य में कमी का उपबंध करना जैसा कि ऊपर पैरा 5.2 में चर्चा की गयी ।
 - लाभ और हानि लेखा में नामे शेष की पूर्णतः मुजराई करना, यदि कोई हो ।
 - शेष बकाया का 50% “विशिष्ट आरक्षिति” नामक एक पृथक् आरक्षिति को अंतरित करना
- 10.3 विनिधानकर्ताओं को वितरित अंतरिम प्रतिलाभ की राशि, वितरणयोग्य अधिशेष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
- 10.4 विशिष्ट आरक्षिति में बकाया का स्कीम की समाप्ति पर यूनिटधारकों को वितरण के अतिरिक्त किसी उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता ।
- 10.5 स्कीम की अवधि की समाप्ति पर, स्कीम का अधिशेष, यदि कोई हो, स्कीम की भूमि सहित, आस्तियों के वसूलीयोग्य मूल्य के आधार पर परिगणित किया जायेगा । नकद वितरित किया गया स्कीम का अधिशेष यूनिट पूँजी के अनुपात में होगा ।

लेखा मान : पशुधन स्कीम

1. स्वामित्व-भूमि से संबद्ध लागत

- 1.1 स्वामित्व अधिकारों से युक्त अर्जित भूमि की गणना भासलेसं द्वारा “अचल आस्तियों के लिये लेखा” पर जारी लेखा मानक 10 (ले मा -10) के अनुसार की जायेगी ।
- 1.2 ऐसी भूमि की लागत स्कीम अवधि पर अपाकृत नहीं की जानी चाहिये (ऊपर पैरा 2.3 का संदर्भ लें)

2. पशुधन विकास व्यय

- 2.1 ये अनुरक्षण और देखभाल सहित पशुधन के पालन और विकास पर उपगत सामान्यतः व्यय हैं । इसमें निम्न पर व्यय शामिल हैं :
- आधार स्टाक की लागत
 - खाद्य लागतें
 - दवाइयाँ और अन्य अनुरक्षण
 - कृत्रिम गर्भाधान की लागत
 - भूमि और किसी अन्य आस्ति के लिये संदत्त पट्टा किराया जो सीधे पशुधन विकास के लिये किया गया माना जा सके
 - अचल आस्तियों का अवक्षयण और अनुरक्षण प्रत्यक्षतः पशुधन विकास के लिये किया गया माना जा सकता है
 - पशुधन विकास के लिये प्रत्यक्षतः किये गये माने जा सकने योग्य कोई अन्य व्यय ।
- इन व्ययों की गणना “पशुधन विकास व्ययों” के रूप में की जानी चाहिये । इन्हें तुलनपत्र में “अचल आस्तियों” और “चालू आस्तियों” के बीच में वर्णित पृथक् मद के रूप में प्रकटीकृत किया जाना चाहिये (पैरा 5.1 की ओर संदर्भ आमंत्रित है) ।
- 2.2 पशुधन विकास व्ययों का मूल्यांकन और मूल्य में कमी का उपबंध उसी रीति में होगा जैसे कि फसल विकास व्ययों के संबंध में जिस पर कि पैरा 5.2 और 5.3 में चर्चा की गयी है ।

3. पशुधन व्यापार

- 3.1 उस पशुधन के बारे में जो पशुपालन/विकास क्रियाकलाप में प्रयोग किये बिना पुनर्बिक्री के लिये उपाप्त किया गया है अलग से परिमाणात्मक जानकारी अनुरक्षित की जायेगी। वर्ष के दौरान व्यापारित पशुधन के संबंध में एक वार्षिक व्यापार लेखा तैयार किया जाना चाहिये (जो पालन-पोषण/विकास के अधीन पशुधन के अनन्य होगा) ।
- 3.2 ऐसे पशुधन जो केवल व्यापार के उद्देश्य से ही रहे के अनुरक्षण इत्यादि की लागत की बाबत एक समुचित वार्षिक प्रभार बनाया जाना चाहिये, । पशुधन व्यापार लेखे को प्रभारित किये जाने वाले अनुरक्षण इत्यादि की लागत, का परिकलन पालन-पोषण/विकास और व्यापार के अधीन धारित पशुधन के परिमाणात्मक अनुपात के आधार पर किया जायेगा ।

4. उपोत्पादों का मूल्यांकन

- 4.1 वर्षान्त पर उपोत्पादों (यथा बकरी के मामले में खाद, कुक्कुट पालन के मामले में अंडे इत्यादि) की माल सूची का “लागत का निम्न या बाज़ार मूल्य” पर अग्रनयन होना चाहिये ।
- 4.2 उपोत्पाद की लागत का परिकलन उपोत्पाद पर इसे विपणनीय बनाने के लिये पृथक्करण के समय के बाद उपगत विशिष्ट लागत के आधार पर किया जायेगा ।

भाग III - वित्तीय विवरणों का रूपविधान

वित्तीय विवरणों से संबंधित मूलभूत रूपरेखा

1. स्कीमवार वित्तीय विवरण

1.1 मोटे तौर पर, वित्तीय विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :

- तुलनपत्र
- राजस्व खाता

1.2 ये स्कीमवार तैयार किये जायेंगे

2. स्कीमवार तुलनपत्र की विषय-वस्तु

2.1 तुलनपत्र का आस्ति पक्ष

तुलनपत्र की आस्तियाँ निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत की जायेंगी

- अचल आस्तियाँ
- विनिधान
- फसल विकास व्यय
- चालू आस्तियाँ
- आस्थगित राजस्व व्यय

I. अचल आस्तियाँ

निम्न में से प्रत्येक के लिये लागत, संचित मूल्यह्रास और शुद्ध ब्याक प्रकटीकृत किये जाने चाहियें :

- भूमि
- पट्टाधृत भूमि
- भूमि विकास व्यय
- अवसंरचना और अन्य सुविधाएँ
- इमारतें
- संयंत्र और मशीनें
- फर्नीचर और जुड़नार
- अनुसंधान और विकास आस्तियाँ
- अन्य

II. विनिधान

निम्न प्रकार के विनिधान पृथक्-पृथक् प्रकटीकृत किये जायेंगे :

- केन्द्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ
- अनुसूचित बैंकों के पास जमाराशियाँ

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के पास डिबेंचर, बॉण्ड और जमाराशियाँ
- अन्य विनिधान

III. फसल विकास व्यय

निम्नलिखित सूचना प्रकटीकृत की जानी चाहिये :

- आरंभिक अतिशेष
- वर्ष के दौरान उपगत व्यय
- कटौतियाँ
- इतिशेष

इसके अतिरिक्त, वर्षांत पर शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य और इतिशेष में सम्मिलित विभिन्न व्ययों का विश्लेषण प्रकटीकृत किया जाना चाहिये ।

फसल विकास व्यय खाते में मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिये उपबंधों में इतिशेष फसल विकास व्ययों के इतिशेष से एक कटौती के रूप में दिखाया जायेगा ।

IV. चालू आस्तियाँ

निम्नलिखित का पृथक्कृत प्रकटीकरण किया जाना चाहिये :

- बैंकों के पास चालू खातों में शेष
- नकदी रोकड़
- विविध देनदार, अच्छे और संदिग्ध के बीच सुभिन्नता करते हुए
- माल-सूचियाँ
- बकाया और प्रोद्भूत आय
- नकद या वस्तु रूप में वसूल किये जाने योग्य अग्रिम
- निक्षेप
- अन्य

V. आस्थगित राजस्व व्यय

निम्नलिखित का प्रकटीकरण किया जाना चाहिये :

- आरंभिक अतिशेष
- वर्ष के दौरान परिवर्धन
- वर्ष के दौरान अपाकृत रकम
- अंत शेष

VI. लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष, यदि कोई हो, प्रदर्शित किया जायेगा ।

2.2 तुलनपत्र का दायित्व पक्ष

तुलनपत्र में दायित्व निम्न प्रवर्गों में वर्गीकृत किये जायेंगे :

- यूनिट पूँजी
- आरक्षितियाँ और अधिशेष
- चालू देयताएँ और प्रावधान

I. यूनिट पूँजी

यूनिट पूँजी (यूनिटों की संख्या और प्रति यूनिट अंकित मूल्य सहित)

II. आरक्षितियों और अधिशेष

निम्नलिखित का पृथक्कृत: प्रकटीकरण किया जाना चाहिये :

- साधारण आरक्षित
- पुनर्मूल्यांकन आरक्षित
- विशेष आरक्षित
- कोई अन्य आरक्षित (इसकी प्रकृति प्रकट करते हुए)
- लाभ और हानि लेखा में अधिशेष

III. चालू देयताएँ और उपबंध

क) चालू देयताएँ

निम्नलिखित का पृथक्कृत: प्रकटीकरण किया जाना चाहिये :

- विविध देनदार
- सांविधिक देयताएँ
- बहियों के अनुसार अध्यादान बैंक खाता
- अदावाकृत वितरित आय
- अन्य

ख) प्रावधान

निम्नलिखित का पृथक्कृत: प्रकटीकरण किया जाना चाहिये :

- उपदान के लिये प्रावधान
- यूनिट पूँजी पर प्रस्तावित आय वितरण
- कराधान के लिये प्रावधान
- अन्य प्रावधान

IV. आकस्मिक देयताएँ

सभी आकस्मिक देयताओं को, ऐसी प्रत्येक देयता के स्वरूप और राशि अलग से दिखाते हुए, प्रकटीकृत किया जाना चाहिये ।

3. स्कीमवार राजस्व खाते की विषय-वस्तु

3.1 आय

निम्नलिखित का पृथक्कृत: प्रकटीकरण किया जाना चाहिये :

- फसलों से बिक्री प्राप्तियों पर अधिशेष
- लाभौंश
- ब्याज
- बिक्री/अचल आस्तियों और विनिधानों पर लाभ
- अवशिष्ट एवं रद्दी की बिक्री
- अन्य आय (प्रकृति उपदर्शित करते हुए)

3.2 व्यय और हानियाँ :

निम्नलिखित का पृथक्कृत: प्रकटीकरण किया जाना चाहिये :

- फसल विकास व्यय, इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय की प्रत्येक प्रमुख मद का भी प्रकटीकरण करते हुए
- शंकास्पद देनदारों और अन्य आस्तियों के लिये प्रावधान
- अचल आस्तियों और विनिधानों की बिक्री से हानि
- प्रबंध फीस
- न्यासिता फीस
- रजिस्ट्रीकरण और स्थानीय प्रभार
- लेखापरीक्षा फीस
- मरम्मत और अनुरक्षण
- बट्टे खाते डाले गये आस्थगित राजस्व व्यय
- अचल आस्तियों का मूल्यह्रास
- रजिस्ट्रीकरण फीस
- अन्य प्रचालन व्यय

3.3 फसल विकास व्ययों की राशि में वृद्धि/कमी

4. लेखा नीतियाँ

निम्नलिखित की बाबत लेखा नीतियों को एक स्थान पर पृथक्कृत: प्रकटीकृत किया जाना और इन्हें वित्तीय विवरणों का एक भाग होना चाहिये

क) अचल आस्तियाँ

1. भूमि
2. अन्य

ख) मूल्यह्रास

1. भूमि
2. अन्य

ग) विनिधान

- घ) फसल विकास व्यय (इस शीर्ष के अधीन प्रमुख मदें प्रकटीकृत की जानी चाहियें ।
- ङ) माल सूचियाँ
- च) राजस्व अभिज्ञान
- छ) सेवानिवृत्ति लाभ
- ज) विदेशी मुद्रा संव्यवहार
- झ) आस्थगित राजस्व व्यय

5. अनुमोदन और प्राधिकरण

वित्तीय विवरणों को स्कीमवार निधि प्रबंधकों और न्यासियों के बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और लेखापरीक्षकों द्वारा संप्रकाशित किया जायेगा । वे सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के निदेशक बोर्ड की बैठक में और न्यासियों की बैठक में भी या एक न्यासी कंपनी की दशा में, न्यासी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने चाहियें ।

6. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

- 6.1 सामूहिक विनिधान स्कीम का परिचालन करने वाली सभी निधियों से अपेक्षित होगा कि उनके न्यास विलेखों में उस आशय के उपबंध के निबंधनों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा कराये । लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का एक भागरूप होगी । इसे तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और राजस्व खाते में संलग्न होना चाहिये । लेखापरीक्षक न्यासी बोर्ड को रिपोर्ट करेगा न कि यूनिटधारकों को ।
- 6.2 लेखापरीक्षक कथन करेगा कि क्या :
- क) उसने सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिये हैं जो उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिये आवश्यक थे ।
 - ख) तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा और राजस्व खाता, स्कीम की लेखा बद्धियों से मेल खाते हैं ।
- 6.3 लेखापरीक्षक अपनी राय देगा कि क्या :
- क) तुलनपत्र, तुलनपत्र की तिथि को, स्कीम के कार्यकलाप की स्थिति का स्कीमवार सही और ऋजु चित्र देता है, और
 - ख) लाभ और हानि लेखा, तुलनपत्र की तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिये स्कीम के अधिशेष/कमी का सही और ऋजु चित्र देता है,
 - ग) राजस्व खाता, तुलनपत्र की तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिये स्कीम के स्कीमवार अधिशेष/कमी का सही और ऋजु चित्र देता है ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 15th October, 1999

**Securities and Exchange Board of India
(Collective Investment Schemes) Regulations, 1999**

S.O. 1035(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 11 and section 19 of the Securities and Exchange Board of India, Act 1992, (15 of 1992) the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement	1.(1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999.
	(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
Definitions	<p>2.(1) In these regulations, unless the context otherwise requires:</p> <p>(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);</p> <p>(b) "advertisement" includes:</p> <p>(i) notices, brochures, pamphlets, circulars, showcards, catalogues, hoardings, placards, posters, insertions in newspapers, pictures, films and cover pages of offer documents;</p> <p>(ii) any other matter to which publicity is given through print medium, radio, television programmes or electronic media.</p>

(c) "appraising agency" means an agency empanelled with the Board for the purpose of conducting technical or financial appraisal of the scheme;

(d) "associate" in relation to a collective investment management company or trustee, includes a person:

(i) who, directly or indirectly, by himself, or in combination with other persons, exercises control over the Collective Investment Management Company or the trustee, as the case may be, or

(ii) in respect of whom the Collective Investment Management Company or the trustee, as the case may be directly or indirectly, by itself, or in combination with other persons, exercises control, or

(iii) whose director, officer or employee is a director, officer or employee of the Collective Investment Management Company or the trustee, as the case may be;

(e) "auditor" means a person qualified to audit the accounts of companies under the Companies Act, 1956;

(f) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under the provisions of section 3 of the Act;

(g) "certificate" means a certificate of registration granted under regulation 10 of these regulations;

(h) "Collective Investment Management Company" means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and registered with the Board under these regulations, whose object is to organise, operate and manage a collective investment scheme;

(i) "collective investment scheme" has the meaning assigned to it by sub-regulation (2) of this regulation;

(j) "closed-ended scheme" means any scheme launched by a Collective Investment Management Company, in which the period of maturity of the scheme is specified and there is no provision for re-purchase before the expiry of the maturity of the scheme;

(k) "control" or "controlling interest" means control exercised or controlling interest held:

(i) in case of a company, by any person or combination of persons who directly or indirectly own, control or hold shares carrying not less than 10% of the voting rights of such company; or

(ii) as between two companies, if the same person or combination of persons, directly or indirectly, own, control or hold shares carrying not less than 10% of the voting rights of each of the two companies; or

(iii) majority of the directors of any company who are in a position to exercise control over the Collective Investment Management Company.

(l) "credit rating agency" means a body corporate registered under Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999;

(m) "depository" means a body corporate as defined in the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);

(n) "economic offence" means an offence to which the Economic Offences (Limitation of Prosecutions) Act, 1974 (12 of 1974) applies for the time-being;

(o) "form" means any of the forms specified as such in the First Schedule;

(p) "fraud", has the same meaning as is assigned to it in section 17 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872);

(q) "inspecting officer" means any person appointed as such by the Board under Chapter VII of these regulations;

(r) "key-personnel" in relation to a company, means the persons who exercise effective control over its affairs;

(s) "net worth" means the aggregate value of the paid up equity capital and free reserves (excluding funds created out of revaluation), reduced by the aggregate value of accumulated losses and deferred expenditure not written off, including miscellaneous expenses not written off;

(t) "offer document" means any document by which applications for subscribing to units of the scheme are invited from the public;

(u) "regulation" means a regulation forming part of these regulations;

(v) "relative" means a person who is a relative, as defined in section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(w) "registrars to an issue and share transfer agent" means a person registered as Registrars to an Issue and Share Transfer Agents under the Securities and Exchange Board of India (Registrar to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;

(x) "schedule" means any of the schedule appended to these regulations;

(y) "scheme" means a collective investment scheme;

(z) "scheme property" includes:

(i) subscription of moneys or money's worth (including bank deposits) to the scheme;

(ii) property acquired, directly or indirectly, with, or with the proceeds of, subscription of money referred to in item (i) of this Clause or

(iii) income arising, directly or indirectly, from subscription money or property referred to in item (i) or (ii),

(aa) "securities laws" means:

(i) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(ii) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956); and

(iii) the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), as amended from time to time;

(bb) "stock broker" means a stock broker as defined in Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Rules, 1992;

(cc) "trustee" means a person who holds the property of the collective investment scheme in trust for the benefit of the unit holders, in accordance with these regulations;

(dd) "unit" includes any instrument issued under a scheme, by whatever name called, denoting the value of the subscription of a unit holder; and

(ee) "unit holder" means a person holding a unit in a scheme.

(2) In these regulations, unless the context otherwise requires, "collective investment scheme" means any scheme or arrangement with respect to property of any description -

- (a) the purpose of which is to enable the investors to participate in the scheme or arrangements by way of subscriptions and to receive profits or income or produce arising from the management of such property or the investments made thereof; and
- (b) in which the subscriptions of the investors by whatever name called, are pooled, and are utilised for the purposes of the schemes or the arrangements; and
- (c) in which the property or such subscriptions are managed on behalf of the investors, who do not have day to day control over the management or operation of the scheme,

whether or not such properties or subscriptions and the investments made thereof are evidenced by identifiable properties or otherwise;

Provided that following shall not be deemed to be a collective investment scheme:

- (a) acceptance of deposits by companies under section 58A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or by Non-Banking Financial Companies as defined in section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (b) acceptance of funds by Chit Funds in terms of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982);
- (c) acceptance of funds by companies declared as Nidhi companies under section 620A of the Companies Act, 1956, (1 of 1956), as per directions issued under, section 637A of the said Act;
- (d) contracts of insurance under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (e) any scheme of the employer as per Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, (19 of 1952); or any other recognised Provident Fund under the Income Tax Act, 1961;

- (f) arrangements of co-operative societies under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) including Co-operative Societies registered under any Provincial Act or State Act for the time being in force;
- (g) any scheme under Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996; or
- (h) any other scheme or arrangement specifically exempted by the Board, from the operation of these regulations.

(3) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF COLLECTIVE INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

No person other than Collective Investment Management Company to launch scheme

3. No person other than a Collective Investment Management Company which has obtained a certificate under these regulations shall carry on or sponsor or launch a collective investment scheme.

Application for grant of certificate

4. Any person proposing to carry any activity as a Collective Investment Management Company on or after the commencement of these regulations shall make an application to the Board for the grant of registration in Form A.

Application by existing Collective Investment Schemes

5.(1) Any person who immediately prior to the commencement of these regulations was operating a scheme, shall subject to the provisions of Chapter IX of these regulations make an application to the Board for the grant of a certificate within a period of two months from such date.

(2) An application under sub-regulation (1) shall contain such particulars as are specified in Form A and shall be treated as an application made in pursuance of regulation 4 and dealt with accordingly.

Application fee to accompany the application

6. Every application for registration under regulation 4 shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in the Second Schedule.

Application to conform to the requirements

7. An application, which is not complete in all respects or does not conform to the requirements of regulation 6 or regulation 9 shall be rejected by the Board.

Provided that before rejecting any such application, the applicant may be given an opportunity to remove within one month such objections as may be indicated by the Board.

Provided further that the Board may on sufficient reasons being shown extend the time in order to enable the

applicant to remove such objections.

Furnishing information

8.(1) The Board may direct the applicant to furnish such further information or clarification as may be required by it, for the purpose of processing the application.

(2) The Board, if it so desires, may ask the applicant or its authorised representative to appear before the Board for personal representation in connection with the grant of a certificate.

Conditions for eligibility

9. The Board shall not consider an application for the grant of a certificate unless the applicant satisfies the following conditions, namely:-

- (a) the applicant is set up and registered as a company under the Companies Act, 1956;
- (b) the applicant has, in its Memorandum of Association specified the managing of collective investment scheme as one of its main objects;
- (c) the applicant has a net worth of not less than rupees five crores;
Provided that at the time of making the application the applicant shall have a minimum net worth of rupees three crores which shall be increased to rupees five crores within three years from the date of grant of registration
- (d) the applicant is a fit and proper person for the grant of such certificate;
- (e) the applicant has adequate infrastructure to enable it to operate collective investment scheme in accordance with the provision of these regulations;
- (f) the directors or key personnel of the applicant shall consist of persons of honesty and integrity having adequate professional experience in related field and have not been convicted for an offence involving moral turpitude or for any economic offence or for the violation of any securities laws;
- (g) at least fifty per cent of the directors of such Collective Investment Management Company shall consist of persons who are independent and are not directly or indirectly associated with the persons who have control over the Collective Investment Management Company;
- (h) no person, directly or indirectly connected with the applicant has in the past been refused registration by the

Board under the Act.

Explanation: For the purposes of this clause, the Board shall take into account whether the previous application for a certificate of any person, directly or indirectly, connected with the applicant has been rejected by the Board or any disciplinary action has been taken against such person under the Act or any of the rules or any of the regulations made under the Act.

- (i) at least one of the directors, on the Board of the Collective Investment Management Company, who is not subject to retirement, is a representative of the trustee;
- (j) the Collective Investment Management Company is not a trustee of any collective investment scheme.
- (k) in case the applicant is an existing collective investment scheme, it complies with the provisions of Chapter IX of these regulations.

Grant of certificate

10. (1) The Board may, on receipt of an application and on being satisfied that the applicant complies with the requirements specified in regulation 9, call upon the applicant to pay registration fee as specified in the Second Schedule.

(2) On receipt of registration fee, the Board shall grant a certificate in Form B, on such terms and conditions as are in the interest of investors and as may be specified by the Board.

Terms and conditions to be complied with

11. The certificate granted under regulation 10 shall be subject to the following conditions, namely :-
- (a) any director of the Collective Investment Management Company shall not be a director in any other Collective Investment Management Company unless such person is an independent director referred to in clause (g) of regulation 9 and approval of the board of Collective Investment Management Companies of which such person is an independent director, has been obtained;
 - (b) the Collective Investment Management Company shall forthwith inform the Board of any material change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the certificate granted by it;
 - (c) appointment of a director of a Collective Investment Management Company shall be made with the prior approval of the trustee;

(d) the Collective Investment Management Company shall comply with provisions of the Act and these regulations;

(e) no change in the controlling interest of the Collective Investment Management Company shall be made without obtaining prior approval of the Board, the trustee and the unit holders holding at-least one-half of the nominal value of the unit capital of the scheme.

(f) The Collective Investment Management Company shall take adequate steps to redress the grievances of the investors within one month from the date of receipt of the complaint from the aggrieved investor.

Procedure where
registration is not granted

12.(1) Where an application made under regulation 4 for grant of registration does not satisfy the conditions specified in regulation 9, the Board may reject the application after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard and inform the applicant of the same.

(2) The decision shall be communicated to the applicant by the Board within 30 days of such decision stating therein the grounds on which the application has been rejected.

CHAPTER III

BUSINESS ACTIVITIES AND OBLIGATIONS OF COLLECTIVE
INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

- Restrictions on business activities 13. The Collective Investment Management Company shall not:
- (a) undertake any activity other than that of managing the scheme;
 - (b) act as a trustee of any scheme;
 - (c) launch any scheme for the purpose of investing in securities;
 - (d) invest in any schemes floated by it.

Provided that a Collective Investment Management Company may invest in its own scheme,

- (i) if it makes a disclosure of its intention to invest in the offer document of the scheme, and
- (ii) does not charge any fees on its investment in that scheme.

- Obligations of Collective Investment Management Company 14. Every Collective Investment Management Company shall:
- (a) be responsible for managing the funds or properties of the scheme on behalf of the unit holders;
 - (b) take all reasonable steps and exercise due diligence to ensure that the scheme is managed in accordance with the provisions of these regulations, offer document and the trust deed;
 - (c) exercise due diligence and care in managing assets and funds of the scheme;
 - (d) be responsible for the acts of commissions and omissions by its employees or the persons whose services have been availed by it;
 - (e) remain liable to the unit holders for its acts of commission or omissions, notwithstanding anything contained in any contract or agreement;

(f) be incompetent to enter into any transaction with or through its associates, or their relatives relating to the scheme:

Provided that in case the Collective Investment Management Company enters into any transactions relating to the scheme with any of its associates, a report to that effect shall immediately be sent to the trustee and to the Board.

(g) appoint registrar and share transfer agents;

(h) abide by the Code of Conduct as specified in the Third Schedule;

(i) give receipts for all monies received by it and give a report to the Board every month, particularly of receipts and payments;

(j) hold a meeting of the Board of Directors to consider the affairs of scheme atleast twice in every three months;

(k) ensure that its officers or employees do not make improper use of their position or information to gain, directly or indirectly, an advantage for themselves or for any other person or to cause detriment to the scheme;

(l) obtain adequate insurance against the property of the scheme;

(m) comply with such guidelines, directives, circulars and instructions as may be issued by the Board from time to time, on the subject of collective investment schemes.

**Submission of information
and documents**

15.(1) The Collective Investment Management Company shall prepare quarterly reports (i.e. as at the end of March, June, September and December) on its activities and the position regarding compliance with these regulations and submit the same to the trustees within one month of the expiry of each quarter.

(2) The Collective Investment Management Company shall file with the trustee and the Board -

(a) particulars of all its directors alongwith their interest in other companies within fifteen days of their appointment; and

(b) any change in the interests of directors,
within fifteen days of such change.

(3) The Collective Investment Management Company shall furnish a copy of the Balance Sheet, Profit and Loss Account and a copy of the summary of the yearly appraisal report to the unit holders within two months from the closure of financial year.

(4) the Collective Investment Management Company shall furnish to the Board and the trustee such information and documents to the Board and the trustee as may be required by them concerning the affairs of the scheme.

CHAPTER IV

TRUSTEES AND THEIR OBLIGATIONS

Trust Deed to be registered under the Registration Act 16.(1) A scheme shall be constituted in the form of a trust and the instrument of trust shall be in the form of a deed duly registered under the provisions of the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) executed by the Collective Investment Management Company in favour of the trustees named in such an instrument.

Appointment of trustees (2) A Collective Investment Management Company shall appoint a trustee who shall hold the assets of the scheme for the benefit of unit holders.

Contents of trust deed 17. (1) The trust deed shall contain such clauses as are specified in the Fourth Schedule and such other clauses as are necessary for safeguarding the interests of the unit holders.
(2) No trust deed shall contain a clause which has the effect of-
(i) limiting or extinguishing the obligations and liabilities of the Collective Investment Management Company in relation to any scheme or the unit holders; or
(ii) indemnifying the trustee or the Collective Investment Management Company for loss or damage caused to the unit holders by their acts of negligence or acts of commissions or omissions.

Eligibility for appointment as trustee 18.(1) Only persons registered with the Board as Debenture Trustee under Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993 shall be eligible to be appointed as trustees of collective investment scheme.

Provided that no person shall be eligible to be appointed as trustee, if he is directly or indirectly associated with the persons who have control over the collective investment management company.

(2) The Collective Investment Management Company shall furnish to the Board particulars as specified in Form C in respect of trustees appointed under sub-regulation (1).

Appointment of trustee not found guilty 19. No person shall be appointed as trustee of a scheme if -
(a) He has been found guilty of an offence under the

securities laws or

- (b) The Board or any authority to which the Board has delegated its power has passed against such person, an order under the Act for violation of any provision of the Act or of regulations made hereunder.

Agreement with collective investment management company

20.(1) The trustee and the Collective Investment Management Company shall enter into an agreement for managing the scheme property.

(2) The agreement for managing the scheme property shall contain such clauses as are specified in the Fifth Schedule and such other clauses as are necessary for the purpose of fulfilling the objectives of the scheme.

Rights and obligations of the trustee

21. (1) The trustee shall have a right:-

(a) to obtain from the Collective Investment Management Company such information as is considered necessary by the trustee.

(b) to inspect the books of accounts and other records relating to the scheme.

(2) The trustee shall ensure that the Collective Investment Management Company has:-

(a) the necessary office infrastructure;

(b) appointed all key personnel including managers for the schemes and submitted their bio-data which shall contain the educational qualifications and past experience in the areas relevant for fulfilling the objectives of the schemes;

(c) appointed auditors to audit the accounts of the scheme from the list of auditors approved by the Board;

(d) appointed a compliance officer to comply with the provisions of the Act and these regulations and to redress investor grievances;

(e) appointed registrars to an issue and share transfer agent;

(f) prepared a compliance manual and designed internal control mechanisms including internal audit systems;

(g) taken adequate insurance for the assets of the scheme;

(h) not given any undue or unfair advantage to any associates of the company or dealt with any of the associates in any manner detrimental to the interest of the unit holders;

(i) operated the scheme in accordance with the provisions of the trust deed, these regulations and the offer document of the scheme(s);

(j) undertaken the activity of managing schemes only;

- (k) taken adequate steps to ensure that the interest of investors of one scheme are not compromised with the object of promoting the interest of investors of any other scheme;
- (l) minimum networth on a continuous basis and shall inform the Board immediately of any shortfall;
- (m) been diligent in empanelling the marketing agents and in monitoring their activities.

(3) Where the trustee has reason to believe that the conduct of business of the scheme is not in accordance with these regulations, trust deed and the offer document of the scheme, the trustee shall forthwith take such remedial steps as are necessary and shall immediately inform the Board of the action taken.

(4) The trustee shall be accountable for, and be the custodian of, the funds and property of the respective schemes and shall hold the same in trust for the benefit of the unit holders in accordance with these regulations and the provisions of trust deed.

(5) The trustee shall be responsible for the calculation of any income due to be paid to the scheme and also for any income received in the scheme to the unit holders.

(6) The trustee shall convene a meeting of the unit holders -

(a) whenever required to do so by the Board in the interest of the unit-holders; or

(b) whenever required to do so on the requisition made by unit holders holding at least one-tenth of nominal value of the unit capital of any scheme; or

(c) when any change in the fundamental attributes of any scheme which affects the interest of the unit holders is proposed to be carried out.

Provided that no such change shall be carried out unless the consent of unit holders holding at least three-fourths of nominal value of the unit capital of the scheme is obtained.

Explanation:- For the purposes of this clause "fundamental attributes" means the investment objective and terms of a scheme.

(7) The trustee shall review:

(a) on a quarterly basis (i.e. by the end of March, June, September and December) every year all activities carried out by the Collective Investment Management Company.

(b) periodically all service contracts relating to registrars to an issue and share transfer agents and satisfy itself that such

contracts are fair and reasonable in the interest of the unit holders.

(c) investor complaints received and the redressal of the same by the Collective Investment Management Company.

(8) (i) The trustee shall ensure that:-

- (a) net worth of Collective Investment Management Company is not deployed in a manner which is detrimental to interest of unitholders.
- (b) Property of each scheme is clearly identifiable as scheme property and held separately from property of the Collective Investment Management Company and property of any other scheme.
- (c) Clearances or no objection certificate is obtained, in respect of transactions relating to property of the scheme from such authority as is competent to grant such clearance or no objection certificate.

(ii) The trustee shall abide by the Code of Conduct as specified in the Third Schedule.

(9) The trustee shall furnish to the Board on a quarterly basis (i.e. by end of March, June, September and December), every year -

- (a) a report on the activities of the scheme;
- (b) a certificate stating that the trustee has satisfied himself that affairs of the Collective Investment Management Company and of the various schemes are conducted in accordance with these regulations and investment objective of each scheme.

(10) The trustee shall cause:-

- (a) the profit and loss accounts and balance sheet of the schemes to be audited at the end of each financial year by an auditor empanelled with the Board.
- (b) each scheme to be appraised at the end of each financial year by an appraising agency.
- (c) Scheme rated by a credit rating agency.

(11) A meeting of the trustees to discuss the affairs of the scheme shall be held at least twice in every three months in a financial year.

(12) The trustee shall report to the Board any breach of these

regulations and has had, or is likely to have, a materially adverse effect on the interests of unit holders as soon as they become aware of the breach.

(13) The trustee shall ensure that -

- (a) the fees and expenses of the scheme are within the limits as specified in Part-I of the Ninth Schedule;
- (b) accounts of the schemes are drawn up in accordance with the accounting norms as specified in Part-II of the Ninth Schedule.
- (c) accounts of the scheme comply with the format of the balance sheet and the profit and loss account as specified in Part-III of the Ninth Schedule.

Termination of trusteeship

22.(1) The trusteeship of a trustee shall come to an end -

- (a) If the trustee ceases to be trustee under the Securities and Exchange Board of India (Debentures Trustees) Regulations, 1993; or
- (b) if the trustee is in the course of being wound up; or
- (c) if unit holders holding at least three-fourths of the nominal value of the unit capital of the scheme pass a resolution for removing the trustee and the Board approves such resolution; or
- (d) if in the interest of the unit holders, the Board, for reasons to be recorded in writing decides to remove the trustee for any violation of the Act or these regulations committed by them; or

Provided that the trustee shall be afforded reasonable opportunity of hearing before action is taken under this clause;

- (e) if the trustee serves on the Collective Investment Management Company a notice of not less than three months expressing its intention not to continue as trustee.

(2) On termination of the trusteeship under sub-regulation (1), another trustee, eligible to be appointed under regulation 18, shall be appointed by the Collective Investment Management Company.

(3) The appointment of the new trustee under sub-regulation (2), shall be completed within three months from the date the previous trusteeship came to an end.

(4) The Board may notwithstanding anything contained in

regulation 18 appoint any person as a trustee if the Collective Investment Management Company fails to appoint a trustee under sub-regulations (2) and (3).

(5) The trustee appointed under sub-regulation (3) and (4) shall stand substituted as a trustee in all the documents to which the trustee so removed was a party.

(6) The person appointed by the Board shall apply to the Court for an order directing the Collective Investment Management Company to wind up the scheme.

(7) A trust deed in the form as specified under regulation 16 shall be executed by the Collective Investment Management Company in favour of the trustee so appointed and from the date of such appointment, trustees shall be subject to all the rights and duties as specified in the regulations.

(8) The trustee so removed shall from such date be discharged from complying with the obligations under the trust deed but shall remain liable for any action taken by them before such removal.

Termination of the Agreement with the Collective Investment Management Company

23.(1) The agreement referred to in regulation 20 entered into by the trustee with the Collective Investment Management Company may be terminated -

(a) if the Collective Investment Management Company is in the course of being wound up as per the provisions of the Companies Act, 1956 or;

(b) if unit holders holding at least three-fourths of the nominal value of the unit capital of the scheme pass a resolution for terminating the agreement with the Collective Investment Management Company and the prior approval of the Board has been obtained, or

(c) if in the interest of the unit holders the Board or the trustee, after obtaining prior approval of the Board, and after giving an opportunity of being heard to the Collective Investment Management Company, decide to terminate the agreement with the Collective Investment Management Company.

(2) Upon termination of agreement under sub-regulation (1), another Collective Investment Management Company, registered with the Board, shall be appointed by the trustee within three months from the date of such termination.

- (3) The Collective Investment Management Company so removed shall continue to act as such at the discretion of trustee or the trustee itself may act as Collective Investment Management Company till such time as new Collective Investment Management Company is appointed.
- (4) The Collective Investment Management Company appointed under sub-regulation (2) shall stand substituted as a party in all the documents to which the Collective Investment Management Company so removed was a party.
- (5) The Collective Investment Management Company so removed shall continue to be liable for all acts of omission and commissions notwithstanding such termination.
- (6) If, none of the Collective Investment Management Company, registered under these regulations, consent to be appointed as Collective Investment Management Company within a further period of three months, then the trustee may wind up the scheme.
- (7) An agreement for managing scheme property shall be executed in favour of the new Collective Investment Management Company subject to all the rights and duties as specified in the regulations.

CHAPTER V**SCHEMES OF COLLECTIVE INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY**

Procedure for launching of schemes	24.(1) No scheme shall be launched by the Collective Investment Management Company unless such scheme is approved by the Trustee.
Rating	(2) No scheme shall be launched by the Collective Investment Management Company without obtaining rating from a credit rating agency.
Appraisal	(3) No scheme shall be launched by the Collective Investment Management Company without getting the scheme appraised by an appraising agency.
Close-ended scheme and Scheme duration	(4) Collective Investment Management Company shall:- (a) Launch only close ended schemes; (b) the duration of the schemes shall not be of less than three calendar years.
Insurance	(5) Collective Investment Management Company shall obtain adequate insurance policy for protection of the scheme property.
No Guaranteed returns	25. No scheme shall provide guaranteed or assured returns. Provided that indicative return may be indicated in the offer document only, if the same is assessed by the appraising agency and expressed in monetary terms.
Disclosures in the offer document	26.(1) The Collective Investment Management Company shall before launching any scheme file a copy of the offer document of the scheme as referred to in sub-regulation (1) of regulation 24 with the Board and pay filing fees as specified in the Second Schedule. (2) The offer document shall contain such information as specified in the Sixth Schedule. (3) The offer document shall also contain true and fair view of the scheme and adequate disclosures to enable the investors to make informed decision.

	<p>(4) The Board may in the interest of investors require the Collective Investment Management Company to carry out such modifications in the offer document as it deems fit.</p> <p>(5) In case no modifications are suggested by the Board in the offer document within 21 days from the date of filing, the Collective Investment Management Company may issue the offer document to public.</p>
Advertisement material	<p>27. (1) Advertisements in respect of every scheme shall be in conformity with the Advertisement Code as specified in the Seventh Schedule.</p> <p>(2) The advertisement for each scheme shall disclose in addition to the investment objectives, the method and periodicity of valuation of scheme property.</p>
Appraising Agency	<p>28. The appraising agency whose appraisal report forms part of the offer document and has given a written consent for the inclusion of the appraisal report in the offer document shall be liable for any statement in the appraisal report which is misleading, incorrect or false.</p>
Misleading Statements	<p>29.(1) The offer document and advertisement materials shall not be misleading or contain any statement or opinion which are incorrect or false.</p> <p>(2) Where an offer document or advertisement includes any statement or opinion which are incorrect or false or misleading, every person -</p> <p>(i) who is a director of the Collective Investment Management Company at the time of the issue of the offer document;</p> <p>(ii) who has issued the offer document and shall be punishable under the Act unless he proves either that the statement or opinion was immaterial or that he had reasonable ground to believe at the time of the issue of the offer document or advertisement that the statement was true.</p>
Offer Period	<p>30. No scheme shall be open for subscription for more than 90 days.</p>
Allotment of Units and refunds of moneys	<p>31.(1) The Collective Investment Management Company shall specify in the offer document, -</p> <p>(a) the minimum and the maximum subscription amount it</p>

seeks to raise under the scheme; and

(b) in case of oversubscription the process of allotment of the amount oversubscribed.

(2) The Collective Investment Management Company shall refund the application money to the applicants,-

(i) if the scheme fails to receive the minimum subscription amount referred to in clause (a) of sub-regulation (1).

(3) Any amount refundable under sub-regulation (2) shall be refunded within a period of six weeks from the date of closure of subscription list, by Registered A.D and by cheque or demand draft marked "A/C. Payee" to the applicants.

(4) In the event of failure to refund the amounts within the period specified in sub-regulation (3), the Collective Investment Management Company shall pay interest to the applicants at a rate of fifteen percent per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the subscription list.

Unit certificates

32. The Collective Investment Management Company shall issue to the applicant whose application has been accepted, unit certificates as soon as possible but not later than six weeks from the date of closure of the subscription list.

Provided that if the units are issued through a depository, a receipt in lieu of unit certificate will be issued as per provisions of Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 and bye-laws of the depository.

Transfer of units

33.(1) A unit certificate issued under the scheme shall be freely transferable.

(2) The Collective Investment Management Company shall, on production of instrument of transfer together with relevant unit certificates, register the transfer and return the unit certificate to the transferee within thirty days from the date of such production.

Provided that if the units are held in a depository such units shall be transferable in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 and the

bye-laws of the depository.

Money to be kept in separate account and utilisation of money	<p>34.(1) The subscription amount received shall be kept in a separate bank account in the name of the scheme and shall be utilised for-</p> <p>(a) adjustment against allotment of units only after the trustee has received a statement from the registrars to the issue and share transfer agent regarding minimum subscription amount, as stated in the offer document, having been received from the public, or</p> <p>(b) for refund of money in case minimum subscription amount, as stated in the offer document, has not been received or in case of over-subscription.</p> <p>(2) The minimum subscription amount as specified in the offer document shall not be less than the minimum amount, as specified by the appraising agency, needed for completion of the project for which the scheme is being launched.</p> <p>(3) The moneys credited to the account of the scheme shall be utilised for the purposes of the scheme and as specified in the offer document.</p> <p>(4) Any unutilised amount lying in the account of the scheme shall be invested in the manner as disclosed in the offer document.</p>
Investments and segregation of funds	<p>35. The Collective Investment Management Company shall:</p> <p>(a) not invest the funds of the scheme for purposes other than the objective of the scheme as disclosed in the offer document.</p> <p>(b) segregate the scheme assets of different schemes.</p> <p>(c) not invest corpus of a scheme in other schemes.</p> <p>(d) not transfer funds from one scheme to another scheme.</p> <p>Provided that inter scheme transfer of scheme property may be permitted at the time of termination of the scheme with prior approval of the trustee and the Board.</p>
Listing of schemes	<p>36. The units of every scheme shall be listed immediately after the date of allotment of units and not later than six weeks from the date of closure of the scheme on each of the stock exchanges as mentioned in the offer document.</p>
Winding up of scheme	<p>37. (1) A scheme shall be wound up on the expiry of duration specified in the scheme or on the accomplishment of the purpose of the scheme.</p>

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a scheme may also be wound up -

(a) on the happening of any event which, in the opinion of the trustee, requires the scheme to be wound up and the prior approval of the Board is obtained; or

(b) if unit holders of a scheme holding at least three-fourth of the nominal value of the unit capital of the scheme pass a resolution that the scheme be wound up and the approval of the Board is obtained; or

(c) if in the opinion of the Board, the continuance of the scheme is prejudicial to the interests of the unit-holders; or

(d) if in the opinion of the Collective Investment Management Company, the purpose of the scheme can not be accomplished and it obtains the approval of the trustees and also of the unit holders of the scheme holding atleast $\frac{3}{4}$ of the nominal value of the unit capital of the scheme with a resolution that the scheme be wound up and the approval of the Board is obtained.

(3) Where a scheme is to be wound up under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the trustee shall give notice disclosing the circumstances leading to the winding up of the scheme in a daily newspaper having nation wide circulation and in the newspaper published in the language of the region where the Collective Investment Management Company is registered.

(4)(a) The trustee shall dispose of the assets of the scheme concerned in the best interest of the unit holders of that scheme.

(b) The proceeds of sale realised under clause(a), shall be first utilised towards the discharge of such liabilities as are due and payable under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the unit holders in proportion to their unit holding.

(5) On the completion of the winding up, the trustee shall forward to the Board and the unit holders

(a) a report on the steps taken for realisation of assets of the scheme, expenses for winding up and net assets available for distribution to the unit holders and

(b) a certificate from the auditors of the scheme to the effect that all the assets of the scheme are realised and the

details of the distribution of the proceeds.

(6) The unclaimed money if any at the time of winding up shall be kept separately in a bank account by the trustee for a period of three years for the purpose of meeting investors' claims and thereafter shall be transferred to investor protection fund, as may be specified by the Board.

Effect of commencement of winding up proceedings	38. On and from the date of the publication of notice under sub-regulation (3) of regulation 37, the trustee or the Collective Investment Management Company as the case may be, shall cease to carry on any business activities in respect of the scheme so wound up.
Cessation of the scheme	39. If, after the receipt of the report under sub-regulation (5) of regulation 37, the Board is satisfied that all the measures for winding up of the scheme have been complied with, the scheme shall cease to exist.

CHAPTER VI

GENERAL OBLIGATIONS

- | | |
|--|---|
| To maintain proper books of accounts and records, etc. | <p>40.(1) Every Collective Investment Management Company shall -</p> <p>(a) keep and maintain proper books of accounts, records and documents, for each scheme so as to explain its transactions and to disclose at any point of time the financial position of each scheme and in particular give a true and fair view of the state of affairs of the scheme and</p> <p>(b) intimate to the Board and the trustees the place where such books of accounts, records and documents including computer records are maintained.</p> <p>(2) Every Collective Investment Management Company shall continue to maintain and preserve, for a period of five years after the close of each scheme, its books of accounts, records, computer data and documents.</p> |
| Financial year | <p>41. The financial year for all the schemes shall end as of March 31 of each year.</p> |
| Despatch of warrants and proceeds | <p>42. The Collective Investment Management Company shall,</p> <p>(a) despatch to the unit holders the warrants within 42 days of the declaration of the interim returns.</p> <p>(b) Despatch the redemption proceeds within 30 days of the closure or the winding up of the scheme.</p> |
| Statement of Accounts and Annual Report | <p>43.(1) The Collective Investment Management Company shall:</p> <p>(a) not exceed the ceilings on expenses or fees in respect of the scheme as specified in Part-I of the Ninth Schedule.</p> <p>(b) prepare the accounts of the scheme in accordance with accounting norms as specified in Part-II of the Ninth Schedule;</p> <p>(c) comply with format of balance sheet and profit and loss accounts as specified in Part-III of the Ninth Schedule;</p> <p>(2) An annual report and annual statement of accounts of each scheme shall be prepared in respect of each financial year.</p> |

(3) Every Collective Investment Management Company shall within two months from the date of closure of each financial year forward to the Board a copy of the Annual Report.

Auditor's Report

44.(1) Every scheme shall have the annual statement of accounts audited by an auditor who is empanelled with the Board and who is not in any way associated with the auditor of the Collective Investment Management Company.

(2) The auditor shall be appointed by the trustee.

(3) The auditor shall forward his report to the trustee and such report shall form part of the Annual Report of the scheme.

(4) The auditor's report shall comprise the following:-

(a) a certificate to the effect that:-

(i) he has obtained all information and explanations which, to the best of his knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit;

(ii) the balance sheet and the revenue account give a fair and true view of the scheme, state of affairs and surplus or deficit in the scheme for the accounting period to which the Balance Sheet or, as the case may be the Revenue Account relates;

(iii) the statement of account has been prepared in accordance with accounting policies and standards as specified in the Part II of the Ninth Schedule.

(iv) any other matter which in the opinion of the auditor is vital and has a bearing on the schemes.

Functions of auditors of scheme

45.(1) The auditor of the scheme shall, as soon as possible, notify the Board and the trustee in writing if he has reasonable grounds to suspect that a contravention of the regulations has occurred or if the schemes are not conducted on sound commercial principles.

(2) The auditor of the scheme:

(a) shall have a right of access at all reasonable times to the books of the scheme; and

(b) may require any employee of the Collective Investment Management Company to give the auditor information and explanations for the purposes of the audit.

- | | |
|--|---|
| Removal or Resignation of auditors | <p>46.(1) The trustee, after prior approval of the trustee and for reasons to be recorded in writing remove the auditor of the scheme for misconduct or inefficiency after giving the auditor a reasonable opportunity of hearing.</p> <p>Provided that another auditor for the scheme is appointed by trustee immediately from auditors empanelled with the Board.</p> <p>(2) The auditor of the scheme may resign by giving a three months written notice to the Collective Investment Management Company and to the trustee.</p> |
| Publication of Annual Report and summary thereof | <p>47.(1) The scheme wise annual report or an abridged form thereof shall be published in a national daily as soon as possible but not later than two calendar months from the date of finalisation of accounts.</p> <p>(2) The annual report shall contain details as specified in the Ninth Schedule and such other details as are necessary for the purpose of providing a true and fair view of the operations of the collective investment scheme.</p> <p>(3) The report if published in abridged form shall carry a note that full annual report shall be available for inspection at the Head Office and all branch offices of the Collective Investment Management Company.</p> |
| Periodic and continual disclosures | <p>48.(1) The Collective Investment Management Company and the trustee, shall make such disclosures or submit such documents as they may be called upon by the Board to make or submit.</p> <p>(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1), the Collective Investment Management Company on behalf of the scheme shall furnish the following periodic reports to the Board, namely:</p> <p>(a) copies of the duly audited annual statements of accounts including the balance sheet and the profit and loss account in respect of each scheme, once a year;</p> <p>(b) a copy of quarterly unaudited accounts;</p> <p>(c) a quarterly statement of changes in net assets for each of the schemes.</p> |
| Quarterly disclosures | <p>49. A Collective Investment Management Company, on behalf of the scheme shall before the expiry of one month</p> |

from the close of each quarter that is 31st March, 30th June, 30th September and 31st December publish its unaudited financial results in one daily newspaper having nation wide circulation and in a newspaper published in the language of the region where the Head Office of the Collective Investment Management Company is situated.

Provided that the quarterly unaudited report referred in this sub-regulation shall contain details as specified in the regulations and such other details as are necessary for the purpose of providing a true and fair view of the operations of the scheme.

Disclosures to the investors	50. The trustee shall ensure that the Collective Investment Management Company shall make such disclosures to the unit holders as are essential in order to keep them informed about any matter which may have an adverse bearing on their investments.
------------------------------	---

Calling of meeting of unit holders, transfer and transmission of units.	51. The calling of meeting of unit holders as well as transfer and transmission of units of scheme shall be as per the provisions of the Eighth Schedule.
---	---

CHAPTER VII**INSPECTION AND AUDIT**

Board's right to inspect and investigate

52.(1) The Board may appoint one or more persons as inspecting officer to undertake the inspection of the books of accounts, records, documents and infrastructure, systems and procedures or to investigate the affairs of the trustee and Collective Investment Management Company for any of the following purposes, namely:

- (a) to ensure that the books of accounts are being maintained by the Collective Investment Management Company in the manner specified in these regulations;
- (b) to ascertain whether the provisions of the Act and these regulations are being complied with by the trustee and Collective Investment Management Company;
- (c) to ascertain whether the systems, procedures and safeguards followed by the Collective Investment Management Company are adequate;
- (e) to investigate into the complaints received from the investors or any other person on any matter having a bearing on the activities of the trustee and Collective Investment Management Company;

Notice before inspection and investigation

53. (1) Before ordering an inspection under regulation 52 the Board shall give not less than ten days notice to the Collective Investment Management Company or trustee as the case may be.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Board is satisfied that in the interest of the investors no such notice is required to be given, it may, by an order in writing direct that such inspection or investigation be taken up immediately without any notice.

(3) During the course of inspection or investigation, the trustee or Collective Investment Management Company against whom the inspection or investigation is being carried out shall be bound to discharge his obligations as provided in regulation 54.

Obligations during inspection and investigation

54. (1) It shall be the duty of the trustee or Collective Investment Management Company whose affairs are being

inspected or investigated, and of every director, officer and employee thereof, to produce such books, accounts, records, and other documents in its custody or control and furnish him such statements and information relating to the activities as trustee or Collective Investment Management Company, as the inspecting officer may require, within such reasonable period as the inspecting officer may specify.

(2) The trustee or Collective Investment Management Company shall allow the inspecting officer to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also provide necessary infrastructure for examining any books, records, documents, and computer data in the possession of the trustee and Collective Investment Management Company or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the inspecting officer are relevant for the purpose of the inspection.

Submission of report to the Board

55. The inspecting officer shall, on completion of the inspection or investigation, submit a report to the Board:

Provided that if directed to do so by the Board, he shall submit interim reports also.

Communications of findings, etc.

56.(1) The Board shall, after consideration of the report referred to in regulation 55, communicate the findings to the trustee or Collective Investment Management Company as the case may be, and give him an opportunity of being heard within fourteen days from the date of receipt of such communication.

(2) Without prejudice to its right to initiate necessary action under the Act and these regulations, the Board upon receipt of the reply, if any, from the trustee or Collective Investment Management Company may call upon it to take such remedial measures as the Board may direct in this behalf and may also initiate action under Chapter VIII of these regulations.

Appointment of Auditor and recovery of expenses

57. (1) Without prejudice to the provisions of regulation 52, the Board shall have the power to appoint an auditor to inspect or investigate, as the case may be, into the books of accounts or the affairs of the trustee or Collective Investment Management Company in respect of schemes:

Provided that the Auditor so appointed shall have the

same powers of the inspecting officer as stated in regulation 52 and the obligation of the Collective Investment Management Company or trustee and their respective employees in regulation 54, shall be applicable to the inspection under this regulation.

Payment of inspection fees
to the Board

(2) The Board shall be entitled to recover such expenses including fees paid to the auditors as may be incurred by it for the purposes of inspecting the books of accounts, records and documents of the trustee or Collective Investment Management Company.

CHAPTER VIII

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

- Competent Authority** 58. In this Chapter, unless the context otherwise requires a competent authority means an officer of the Board not below the rank of Division Chief, whom the Board specifies as the competent authority for the purpose of Chapter VIII.
- Suspension of Certificate** 59. The competent authority may suspend a certificate of registration granted to a Collective Investment Management Company if such company :-
- (a) contravenes any provision of the Act or these regulations;
 - (b) for the purposes of these regulations furnishes any information which is false or misleading or suppresses any material information;
 - (c) does not co-operate in any inspection, investigation or inquiry conducted by the Board under the Act or these regulations;
 - (d) fails to comply with any directions issued by the Board under the Act or the regulations;
 - (e) fails to resolve the complaints of the investors or fails to furnish to the Board a satisfactory reply in this behalf when called upon to do so by the Board;
 - (f) commits a breach of any provision of the Code of Conduct specified in the Third Schedule;
 - (g) fails to pay the fees specified in the Second Schedule;
 - (h) commits a breach of the conditions of registration; or
 - (i) fails to make an application for listing or fails to list units of a scheme in a recognised stock exchange.
- Cancellation of certificate** 60. The competent authority may cancel the certificate of registration granted to a Collective Investment Management Company, if -
- (a) the company has been guilty of fraud or has been convicted of an economic offence;
 - (b) the company has been guilty of repeated defaults of the nature specified in regulation 59;
 - (c) the financial position of the company has deteriorated to such an extent that the competent authority is of the opinion that its continuance is not in the interest of the unit holders.

- (d) the agreement for managing the scheme property has been terminated.
- (e) The company is declared insolvent or wound up.

Manner of making order of cancellation or suspension

61. No order of suspension or cancellation of certificate shall be made by the competent authority against the Collective Investment Management Company except after holding an enquiry in accordance with the procedure specified in regulation 62.

Provided that the holding of an enquiry shall not be necessary in the following cases:

- (a) where the company is declared insolvent or is wound up;
- (b) where the company fails to pay fees to the Board;
- (c) where the agreement for managing the scheme property is terminated;
- (d) where the company surrenders its certificate of registration to the Board;
- (e) where the company fails to maintain the net worth;
- (f) where the number of independent directors falls below fifty percent of the total number of directors.

Provided further that an opportunity of hearing shall be given to Collective Investment Management Company before any action is taken under the first proviso to this regulation.

Show cause notice and order

62.(1) Where action under regulation 59 or 60 is proposed, the competent authority shall issue to the Collective Investment Management Company, at its registered office or its principal place of business, a notice setting out the grounds on which the action is proposed to be taken against it and calling it to show cause against such action within a period of fourteen days from the date of receipt of the notice.

(2) The competent authority shall give a reasonable opportunity of hearing to the Collective Investment Management Company to enable it to make submissions in support of his reply to its notice issued under sub-regulation (1).

(3) Before the competent authority, the Collective Investment Management Company may either appear in person or through any person duly authorised on his

behalf;

Provided that no advocate shall be permitted to represent the Collective Investment Management Company at the personal hearing.

Provided further that where an advocate has been appointed by the Board as a presenting officer under sub-regulation (5) of this regulation, the company shall have the right to present its case through an advocate.

(5) If it is considered necessary, the competent authority may request the Board to appoint a presenting officer to present its case.

(6) The Competent Authority, after considering the reply of the Collective Investment Management Company, the evidence on record, and the submissions at the time of the personal hearing, if any, pass such order as it deems fit, including an order for the suspension or cancellation of the certificate.

(7) Every order made under sub-regulation (6) shall be self-contained and shall give reasons for the conclusions stated therein, including the justification for the penalty if any, imposed by that order.

Effect of suspension or cancellation of certificate of registration

63. (1) On and from the date of the suspension of the certificate, the Collective Investment Management Company shall cease to carry on any activity during the period of suspension, and shall be subject to the directions of the Board with regard to any records, documents, or assets that may be in its custody or control, relating to its activities.

(2) On and from the date of cancellation of the certificate, the Collective Investment Management Company shall, cease to carry on any activity.

Publication of order of suspension or cancellation

64. The order of suspension or cancellation passed under sub-regulation (6) of regulation 62, shall be published by the Board in two newspapers of which at least one shall have nation wide circulation.

Directions by the Board

65. The Board may, in the interests of the securities market and the investors and without prejudice to its right to initiate action under this Chapter, including initiation of criminal

prosecution under section 24 of the Act, give such directions as it deems fit in order to ensure effective observance of these regulations, including directions,:

- (a) requiring the person concerned not to collect any money from investors or to launch any scheme;
- (b) prohibiting the person concerned from disposing of any of the properties of the scheme acquired in violation of these regulations;
- (c) requiring the person concerned to dispose of the assets of the scheme in a manner as may be specified in the directions;
- (d) requiring the person concerned to refund any money or the assets to the concerned investors along with the requisite interest or otherwise, collected under the scheme.
- (e) prohibiting the person concerned from operating in the capital market or from accessing the capital market for a specified period.

Action
intermediaries

against

66. The Board may initiate action for suspension or cancellation of registration of an intermediary holding a certificate of registration under section 12 of the Act who fails to exercise due diligence in the performance of its functions or fails to comply with its obligations under these regulations:

Provided that no such certificate of registration shall be suspended or cancelled unless the procedure specified in the regulations applicable to such intermediary is complied with.

Appeal to the Central
Government

67. Any person aggrieved by an order of the competent authority or the Board under these regulations:

- (a) suspending the certificate of registration; or
- (b) cancelling such certificate; or
- (c) issuing directions under regulation 65,

may prefer an appeal to the Central Government against such order, in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Appeals to Central Government) Rules, 1993.

CHAPTER IX**EXISTING COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES**

Existing schemes to obtain provisional registration 68.(1) Any person who has been operating a collective investment scheme at the time of commencement of these regulations shall be deemed to be an existing collective investment scheme and shall also comply with the provisions of this Chapter.

Explanation: The expression 'operating a collective investment scheme' shall include carrying out the obligations undertaken in the various documents entered into with the investors who have subscribed to the scheme.

(2) An existing collective investment scheme shall make an application to the Board in the manner specified in regulation. 5.

(3) The application made under sub-regulation (2) shall be dealt with in any of the following manner:

- (a) by grant of provisional registration by the Board under sub-regulation (1) of regulation 71;
- (b) by grant of a certificate of registration by the Board under regulation 10;
- (c) by rejection of the application for registration by the Board under regulation 12.

No scheme to be launched until grant of registration 69. No existing collective investment scheme shall launch any new scheme or raise money from the investors even under the existing scheme, unless a certificate of registration is granted to it by the Board under regulation 10.

Consideration of application for grant of provisional registration 70.(1) The applicant for the purpose of being considered eligible for the grant of provisional registration shall satisfy the Board that

- (a) the schemes of the applicant are in the nature of collective investment schemes;
- (b) the affairs of the applicant are not being conducted in a manner detrimental to the interest of existing investors;
- (c) the applicant has atleast 50% independent directors at the time of making the application;

Explanation:- "Independent directors" shall mean directors who are not associates of the persons operating the existing collective investment scheme.

(d) any person, directly or indirectly connected with it has not been granted registration by the Board under the Act;

2) The Board for the purposes of grant of provisional registration may, inter alia, inspect the schemes, books of accounts, records and documents of the applicant

3) The Board shall recover from the applicant such expenses including fees paid to the auditor, appraising agency as may be incurred by it for the purposes of inspecting the schemes, books of accounts, records and documents of the applicant.

4) The Board on being satisfied that the requirements specified in sub-regulation (1) are not fulfilled may reject the application and the applicant thereupon shall wind up its existing scheme (s) in the manner specified in regulation 73.

Grant of provisional registration

71.(1) The Board after being satisfied that the conditions specified in regulation 70 are fulfilled may grant provisional registration to the applicant subject to the following conditions, namely:-

(a) the applicant shall get the existing schemes rated by a credit rating agency within one year from the date of grant of provisional registration;

(b) the applicant shall get the existing schemes audited by an auditor within a period of one year from the date of grant of provisional registration;

(c) the applicant shall get existing schemes appraised by an appraising agency within a period of one year from the date of grant of provisional registration;

(d) the applicant shall create a trust and appoint trustees in the manner specified in Chapter IV of these regulations within a period of one year from the date of grant of provisional registration;

(e) the applicant shall comply with accounting and valuation norms in respect of schemes floated before the commencement of these regulations as specified in Part-II of the Ninth Schedule within a period of one year from the date of provisional registration;

(f) the applicant shall meet the minimum net worth of

Rupees one crore within one year from the date of grant of provisional registration which shall be increased by Rupees one crore each within two years, three years, four years and five years from the date of grant of provisional registration.

(g) the applicant shall not dispose of the scheme property except for meeting obligations arising under the offer document of the scheme.

(h) the applicant shall comply with the conditions specified in regulation 11;

(i) such other conditions which the Board may impose.

(2) The applicant shall give a written undertaking to the Board to comply with the conditions specified in sub-regulation (1).

(3) The applicant who has been considered eligible for the grant of provisional registration by the Board shall pay provisional registration fee as per the Second Schedule.

(4) An applicant who after grant of provisional registration fails to comply with the conditions as specified in sub-regulation (1) and regulation 9 shall not be considered eligible for the grant of certificate of registration under regulation 10 and shall wind up the scheme in the manner specified in regulation 73.

Registration to existing scheme

72.(1) An existing Collective Investment Scheme which satisfies the Board that the requirements specified in regulation 9 and the conditions specified under regulation 71 have been fulfilled, shall be granted a certificate of registration under regulation 10 upon payment of registration fees as specified in paragraph 2 of the Second Schedule and on such terms and conditions as may be specified by the Board.

(2) An existing collective investment scheme which has been granted certificate of registration under sub-regulation (1) may be allowed to float new schemes on such terms and conditions as may be specified by the Board.

Manner of repayment and winding up

73. (1) An existing collective investment scheme which;
(a) has failed to make an application for registration to the Board; or
(b) has not been granted provisional registration by the Board; or

- (c) having obtained provisional registration fails to comply with the provisions of regulation 71;

shall wind up the existing scheme.

- (2) The existing collective investment scheme to be wound up under sub-regulation (1) shall send an information memorandum to the investors who have subscribed to the schemes, within two months from the date of receipt of intimation from the Board, detailing the state of affairs of the scheme, the amount repayable to each investor and the manner in which such amount is determined.
- (3) The information memorandum referred to in sub-regulation (2) shall be dated and signed by all the directors of the scheme.
- (4) The Board may specify such other disclosures to be made in the information memorandum, as it deems fit.
- (5) The information memorandum shall be sent to the investors within one week from the date of the information memorandum.
- (6) The information memorandum shall explicitly state that investors desirous of continuing with the scheme shall have to give a positive consent within one month from the date of the information memorandum to continue with the scheme.
- (7) The investors who give positive consent under sub-regulation (6), shall continue with the scheme at their risk and responsibility.
- Provided that if the positive consent to continue with the scheme, is received from only twenty five percent or less of the total number of existing investors, the scheme shall be wound up.
- (8) The payment to the investors, shall be made within three months of the date of the information memorandum.
- (9) On completion of the winding up, the existing collective investment scheme shall file with the Board such reports, as may be specified by the Board.

Existing scheme not
desirous of obtaining
registration to repay

74. An existing collective investment scheme which is not desirous of obtaining provisional registration from the Board shall formulate a scheme of repayment and make such repayment to the existing investors in the manner specified in regulation 73.

CHAPTER X

MISCELLANEOUS

Power of the Board to
issue clarifications

75. In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board shall have the power to issue clarifications and guidelines in the form of notes or circulars which shall be binding on the trustee or Collective Investment Management Company or any other intermediary in the capital market.

[F. No. SEBI/19418/99]

D.R. MEHTA, Chairman

FIRST SCHEDULE - FORMS

FORM A

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999
[Regulations 4, 5(2)]

APPLICATION FOR THE GRANT OF REGISTRATION AS COLLECTIVE
INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

1. NAME OF THE APPLICANT:

2. CONTACT PERSON:

3. NAME OF THE COMPLIANCE OFFICER:

TELEPHONE NO.:

FAX NO.:

4. ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE
OF THE APPLICANT:

PIN CODE:

TELEPHONE NO. :

FAX NO.:

5. ADDRESS OF THE APPLICANT FOR
CORRESPONDENCE:

PIN CODE:

TELEPHONE NO. :

FAX NO.:

6. ADDRESS OF BRANCH OFFICES (IN INDIA & ABROAD) OF THE APPLICANT, IF ANY:

(A)

(B)

(C)

7. WHETHER ANY OTHER APPLICATION UNDER SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ACT, 1992 HAS BEEN MADE FOR GRANT OF CERTIFICATE, IF SO, DETAILS THEREOF:

8. DATE AND PLACE OF INCORPORATION OF THE COLLECTIVE INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY:

(Enclose a copy of certificate of incorporation)

9. OBJECTS OF THE COLLECTIVE INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY:

(Enclose copy of the Memorandum and Articles of Association)

10. MAIN OBJECTS:

11. ANCILLARY OBJECTS:

(the Memorandum and Articles of Association should have necessary clause in respect of collective investment scheme and amendments, if any, shall have to be incorporated in the existing Memorandum and Articles of Association)

12. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN:

(give list of major share holders holding 5% or more voting rights and percentage of their share holdings, as of the latest date)

13. NET WORTH OF THE COMPANY:

(as of the latest date)

14. PRESENT LINE(S) OF BUSINESS ACTIVITIES:

(History, major achievements and present activity)

15. FINANCIAL INFORMATION:

(Enclose Balance Sheet and Profit and Loss account for the immediately preceding 3 years)

16. ACCOUNTING POLICIES:

(Furnish description of significant accounting policies)

17. NAMES AND ACTIVITIES OF ASSOCIATE COMPANIES/CONCERNS CARRYING ON ACTIVITIES RELATED TO THE SECURITIES MARKET AND GRANTED REGISTRATION BY SEBI:**18. MANAGEMENT OF THE COLLECTIVE INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY:****19. BOARD OF DIRECTORS:**

(Indicate name, qualifications, background, experience, whether directorship is on whole time/ part time basis, other directorships, of the Directors. Whether any of the Directors is in full employment elsewhere; give details thereof. If any of the Directors is a member of a professional body i.e. the ICAI or ICSI, to furnish permission of the professional body for acting as director of the applicant)

20. KEY MANAGEMENT PERSONNEL:

(Furnish the names, qualifications, experience of the key management personnel indicating their experience. Also, submit proof of acceptance of appointment letter, latest salary slips)

21. OTHER EMPLOYEES:

(Furnish the names, qualifications, experience of the other employees)

22. DETAILS OF INFRASTRUCTURAL FACILITIES:

23. OFFICE SPACE:

(Mention extent of area available at the place where the main activity would be carried out; detail of office space available at all the locations; certified copies of relevant sale deed/ lease deed/ rental agreement etc. in respect of each of the premises to be enclosed.)

24. OFFICE EQUIPMENT:

(mention the details of electronic office equipment, computers, fax, telephones etc; submit proof of purchase of the above equipments.)

25. INVOLVEMENT IN CASES:

(a) Court cases/ litigations in which the applicant may have been involved in the last 3 years.

(b) Involvement in any offence relating to moral turpitude/ economic offences of the directors, employees of the applicant in the last 3 years.

26. AUDITORS**27. OTHER INFORMATION:**

Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

Names and addresses of the auditors of the applicant:

28. DOCUMENTS:

Submit copies of:

(a) Draft Trust Deed; and

(b) Draft Investment Management Agreement

INSTRUCTION FOR FILLING UP THE FORM :-

(a) Applicants must submit a completed application form together with appropriate supporting documents to the Board.

(b) It is important that this application form should be filled in accordance with the regulations.

(c) An application which is not complete is liable to be rejected.

(d) Answers must be typed and legible.

(e) Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the application form.

(f) The application must be signed by the competent person having authority to do so and all signatures must be in original.

FORM B

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999

[Regulation 10]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, (15 of 1992) read with the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Scheme) Regulations, 1999 made thereunder the Board hereby grants a certificate of registration to _____ as an Collective Investment Management Company.

Registration Code for the Collective Investment Management Company is CIMC/CIS/ /

Date

By order

Sd/-

For and on behalf

Securities and Exchange Board of India

FORM C

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999****[Regulation 18(2)]****TRUSTEESHIP OF THE COLLECTION INVESTMENT SCHEME**

1] Furnish the following particulars:

- [a] Name of the Institution
- [b] Address/telephone/telex/fax nos.
- [c] Name of the contact person
- [d] SEBI Registration No.:
- [e] Management of the trustee
 - Board of Directors
 - Key Personnel
 - Other Employees
- [f] Details of Infrastructure facilities
 - Office Space
 - Office Equipment
- [g] Court cases / litigations in which the trustee may have been involved in the last three years and whether the case is pending or has been adjudicated.
- [h] Any penalty imposed by SEBI or by other regulatory bodies during the last three years.
- [i] Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the trustee.

2] **INSTRUCTION FOR FILLING UP THE FORM**

(See Form A)

SECOND SCHEDULE**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999****[Regulations 6, 10, 26(1), 59(g), 71(3), 72(1)]****FEEES**

- | | |
|---|------------------------------|
| 1.(a) Application fees payable by the applicant: | Rupees Twenty- Five Thousand |
| (b) Provisional registration fees payable by existing collective investment scheme:
[see para 2 below] | Rupees Five Lacs |
| (c) Registration fees payable by the applicant for grant of registration as collective investment management company: | Rupees Ten Lacs |
| (d) Filing fees for offer document: | Rupees Twenty- Five thousand |

2. The applicant who has paid provisional registration fee of Rs.5 lacs under sub-paragraph (b) of paragraph 1, shall pay remaining registration fee of Rs.5 lacs at the time of grant of registration.

3. The fees referred to in paragraphs 1 and 2 above, shall be paid by means of a bank draft in favour of "Securities and Exchange Board of India" at Mumbai or at the regional offices where the application for registration or draft offer document is submitted.

THIRD SCHEDULE**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999****[Regulations 14(h), 21(8), 59(f)]****CODE OF CONDUCT****1. Interests of all classes of unit holders to be protected**

The organisation, operation and management of the Collective Investment Scheme and the creation of assets therein shall be conducted -

- (a) in the interest of all classes of unit holders of the scheme and
- (b) not merely in the interests of the directors of the company or associated persons or any special class of unit holders.

2. Dissemination of information

- (a) the trustee and the Collective Investment Management Company shall ensure the timely dissemination to all unit holders, of adequate accurate and explicit information about the investment policies, investment objectives, financial position and general affairs of the scheme;
- (b) all such information shall be fairly presented in simple language.

3. Conflict of interest

The trustee and the Collective Investment Management Company shall in managing the affairs of the schemes avoid conflicts of interest and treat the interests of all unit holders paramount in all matters.

4. Segregation

The trustee and the Collective Investment Management Company shall ensure scheme wise segregation of funds and assets as created.

5. Integrity, investments as per objects, etc.

The trustee and the Collective Investment Management Agency shall

- (a) carry on the business and make investments in accordance with the investment objectives stated in the offer documents and take investment decisions solely in the interests of unit holders;
- (b) not use any unethical means for marketing their schemes or for inducing investors to bring the same;
- (c) carry on all their activities in the interests of unit holders and with strict regard to integrity and honesty.

FOURTH SCHEDULE**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999****[Regulation 17(1)]****CONTENTS OF THE TRUST DEED****1. Principal Clauses**

The Trust Deed shall contain the following clauses, namely:-

[a] the responsibilities, obligations and rights of the trustee for the protection of the assets of the scheme.

[b] provisions to ensure that management of scheme property shall be in accordance with that specified in the offer document and these regulations.

[c] the responsibilities, obligations and rights of the Collective Investment Management Company.

[d] the policies for issue, pricing of units and expenses of the scheme, including payment of fees and distribution of income and gains and accounting.

[e] the policies for disclosures of the investors of various schemes objectives and investment objectives in offer documents and advertisements and annual and half-yearly reporting requirements.

[f] provisions to ensure that the auditor for the scheme shall be different from the Auditor of the Collective Investment Management Company. Further, it shall contain conditions of appointment, retirement, removal and replacement of auditor of the scheme.

[g] broad policies regarding allocation of expenditure to capital or income.

[h] provisions to explicitly forbid the acquisition of any asset out of the trust property which involves the assumption of any liability which is unlimited or shall not result in encumbrance of the trust property in any way.

[i] trusteeship fee, if any, payable to the trustee.

[j] provisions to the effect that no amendment to the Trust Deed shall be carried out without the prior approval of the Board and unit holders.

[k] provisions to ensure that removal of the trustee in all cases shall require the prior approval of the Board and the provisions regarding appointment of new trustee and their removal be specified.

[l] procedure for seeking approval of the unit holders.

[m] provisions for redressal of grievances of the investors and time within which such complaints shall be redressed.

[n] the circumstances under which the assets may be disposed of with the approval of the trustee.

[o] provisions regarding transfer of units, meeting of unit holders and maintenance of upto date register of unit holders.

[p] the time within which the unit certificates shall be issued after allotment and the time within which transfer of units shall be completed.

[q] provisions to ensure that any document required to be lodged with the Board shall be signed by atleast two Directors of the Collective Investment Management Company with atleast one of them being an independent director.

[r] provisions to ensure the public availability of the trust deed for inspection of unitholders and investors.

[s] provisions to ensure that unit holders shall have beneficial interest in the trust property to the extent of individual holding in respective schemes only.

2. Trustee's duties regarding information properly, etc.

The Trust Deed shall lay down that the trustee shall:

[a] obtain necessary information and a quarterly report from the Collective Investment Management Company.

[b] make spot checks on the Collective Investment Management Company regarding pricing of units and payment into and out of the scheme and proper accounting of the income of the scheme and charging of expenses and distribution as permitted.

[c] maintain an arms' length relationship with other companies, or institutions or financial intermediaries or any body corporate with which it may be associated.

[d] take into their custody, or under their control all the property of the schemes and hold it in trust for the unit holders.

[e] act in the interest of the unit holders.

[f] provide or cause to be provide information to unit holders and Board as may be specified by the Board.

[g] enter into an agreement for managing the scheme property with the Collective Investment Management Company for this purpose, and shall enclose the same with the Trust Deed.

[h] supervise the collection of any income due to be paid to the scheme and for claiming any repayment of tax and holding any income received in trust for the holders in accordance with the Trust Deed, Offer document and regulations.

[i] take reasonable care to ensure that the funds under the schemes floated by and managed by the Collective Investment Management Company are in accordance with the Trust Deed, Offer document and regulations.

[j] have to remove the Collective Investment Management Company under the specific events only with the approval of Board in accordance with the regulations.

[k] be responsible for the supervision of its activities of the Collective Investment Management Company in relation to the scheme and shall also act as a Custodian of the assets of the scheme.

3. Obligations of the Company

The Trust Deed shall lay down that Collective Investment Management Company shall:

[a] float schemes for the scheme after approval by the trustee, and manage the funds mobilised under various schemes, in accordance with the provisions of the Trust Deed, Offer document and regulations.

[b] not invest the corpus of the scheme in other scheme.

[c] not without the approval of the trustee publish or cause to be published any advertisement containing any invitation to buy units, or any statement with respect to the sale price of the units or the return expected from the scheme.

[d] use its best endeavours to carry on and conduct its business in a proper and efficient manner and to ensure that the scheme to which the deed relates is carried on and conducted in a proper and efficient manner.

[e] make available to the trustee or to the auditors for inspection all the books of the scheme.

[f] furnish to the trustee or to the auditors such oral or written information as the trustee or the auditor requires with respect to all matter relating to the scheme or otherwise relating to the affairs of the scheme.

[g] not exercise the right to vote in respect of any units relating to the scheme held by the Collective Investment Management Company.

FIFTH SCHEDULE

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999

[Regulation 20(2)]

CONTENTS OF THE AGREEMENT FOR MANAGING SCHEME PROPERTY

The Investment Management Agreement shall contain the following clauses namely:-

1. Obligations of the Collective Investment Management Company:

The Collective Investment Management Company

(a) shall be responsible for floating schemes after obtaining approval from the trustee and managing the funds mobilised under various schemes, in accordance with the provisions of the Trust Deed, Offer document and regulations;

(b) shall invest the funds raised under various schemes in accordance with the provisions of the Trust Deed, Offer document and the regulations;

(c) shall not acquire any assets out of the scheme property which involves the assumption of any liability which is unlimited or which may result in encumbrance of the scheme property in any way;

(d) shall not give or guarantee loans or take up any activity in contravention of the regulations;

(e) shall ensure that no application form, or sales literature or other printed matter issued to prospective investors, or advertisement, or report and or announcement addressed to the general body of unit holders, or to the public, or to the press or other communications media, is issued or published without the trustee's prior approval in writing, and contains any statement or matter extraneous to the Trust Deed or Offer Document scheme particulars approved by the trustee and Board;

(f) shall submit quarterly reports on the functioning of the schemes to the trustee or at such intervals as may be required by the trustee or Board.

2. The trustee:

(a) shall have the right to obtain from the Collective Investment Management Company all information concerning the operations of the various schemes managed by the Collective Investment Management Company at such intervals and in such a manner as required by the trustee to ensure that the Collective Investment Management Company is complying with the provisions of the Trust Deed, Offer document and regulations;

(b) shall have the power to remove the Collective Investment Management Company under the specific events only with the approval of Board in accordance with the regulations.

3. Meeting the losses

No loss or damage or expenses incurred by the Collective Investment Management Company or its officers or any person delegated by the Collective Investment Management Company, shall be met out of the trust property.

SIXTH SCHEDULE**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999****[Regulation 26(2)]****CONTENTS OF THE OFFER DOCUMENT****1. Contents**

The offer document filed with the Board shall contain, in addition to the requirements specified in the regulations, following information so as to enable the investors to make a true, fair and informed decision on the investments in the scheme, namely:

1. Outer Cover Pages**1.1. Front Outer cover Page**

i) The front outer cover page of the offer document filed with the Board shall contain the following details only:-

The name of the scheme, name and address of the registered office of the Collective Investment Management Company and trustee along with their telephone number and fax number.

ii) The nature, number, price and amount of the units offered.

iii) The following clause in respect of general risk should be incorporated:

“Investment in units involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the scheme and the offer including the risks involved. The units have not been recommended or approved by Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document.”

Specific attention of investors shall be invited to the summarised and detailed statement of Risk Factors by indicating their page number(s) in the ‘General Risks’.

iv) “Collective Investment Management Company’s Absolute Responsibility clause to be incorporated as under:

“The Collective Investment Management Company, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this offer document contains all information with regard to the scheme and that the information contained in the offer document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect.”

v) The name and address of the Registrar to the issue along with the telephone number and fax number.

vi) The name and address of the auditor of the scheme.

vii) Opening, Closing and Earliest closing date (if any) for the offer.

viii) Credit Rating - Name of the Credit Rating Agency, the rating given, the tenure of the rating.

ix) Name of the Compliance Officer.

x) Name of the appraising agency - A brief appraisal report.

xi) The front cover page shall be white. No patterns or pictures shall be printed on this page.

xii) The cover page paper shall be of adequate thickness (preferably minimum 100 gcm quality).

1.2. Front Inside Cover Page

Index shall appear on the Front Inside Cover Page.

1.3. Inner cover Pages

The other risk factors shall be printed in clear readable font (preferably of minimum point 10 size) starting on the first inner cover page to be numbered page i (and, if need be, shall continue on subsequent pages ii, iii, etc. as distinct from the page number of the offer document proper which would run as 1, 2, 3, etc.) in addition to appearing in the offer document.

1.4. Back cover Pages

Back Inside Cover Page and Back Outside Cover Page shall be in white and blank. Any 'notes' required to be given prominence shall appear immediately after the Risk Factors wherever they appear.

2. Risk Factors

The Collective Investment Management Company shall classify the risk factors as those which are specific and internal to the scheme and those which are external and beyond the control of the Collective Investment Management Company. Collective Investment Management Company's perception of the internal and external risk factors shall be given immediately after each of the risk factors and not as a separate heading under management perception.

3. Disclaimer Clause

The offer document shall contain the following disclaimer clause in capital letters and bold.

It is to be distinctly understood that submission of offer document to SEBI should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. SEBI does not take any responsibility either for the financial soundness of any scheme for which the issue is proposed to be made or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the offer document. Collective Investment Management Company, _____ has certified that the disclosures made in the offer document are generally adequate and are in conformity with SEBI (Collective Investment Scheme), Regulations, 1999 in force for the time being. This requirement is to facilitate unit holders to take an informed decision for making investment in the proposed issue.

It should also be clearly understood that the Collective Investment Management Company is primarily responsible for the correctness, adequacy and disclosure of all relevant information in the offer document.

WE THE COLLECTIVE INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY CONFIRM that:

the offer document forwarded to SEBI is in conformity with the documents, materials and paper relevant to the issue; all the legal requirements connected with the said issue, as also the guidelines, instructions, etc. issued by SEBI, the Government and any other competent authority in this behalf have been duly complied with; and the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision as to the investment in the proposed scheme.

We confirm that beside ourselves, all the intermediaries named in the prospectus are registered with SEBI and till date such registration is valid.

4. Undertaking from the Collective Investment Management Company

The following undertaking by the Collective Investment Management Company shall be incorporated in the offer document:

- i) that the complaints received in respect of the issue of units of the scheme would be attended to expeditiously and satisfactorily.
- ii) that the funds required for despatch of refund orders/allotment letters/ certificates by registered post shall be made available to the Registrar to the Issue by the Collective Investment Management Company.
- iii) that the certificates of the units/refund orders to the non-resident Indians shall be despatched in time.
- iv) that no units shall be issued to the public later than six months after the date of the offer document i.e. the date when the offer document is filed with the Board.

5. Fictitious Applications

Any person who makes in a fictitious name an application for acquiring or subscribing for any units of a scheme, or otherwise induces the scheme to allot, or register any transfer of units therein to him, or to any other person in a fictitious name, shall be punishable under the provisions of the SEBI Act, 1992.

6. Minimum Subscription Clause

The Collective Investment Management Company shall state that the minimum subscription of units necessary for the purpose of launching the scheme.

The minimum subscription clause is to be incorporated in the offer document as under:

"If the scheme does not receive the above stated minimum subscription of units from the public on the date of closure of the issue, then the entire subscription amount received shall be refunded forthwith".

7. Maximum Subscription Clause

The Collective Investment Management Company shall state the maximum number of units that shall be offered through the offer document.

Minimum and Maximum - by Appraising Agency compared.

8. Terms of the present issue

8.1. Terms of payments

8.2. Rights of the investors

8.3. How to apply - availability of forms, offer document and mode of payment

8.4. Any special tax benefits for investing in the scheme.

9. Appraisal of the Project

Project to be appraised by appraising agency for carrying out appraisal and salient features of the appraisal report to be detailed. The scope and purpose of the appraisal along with the date of appraisal may be disclosed. The cost of the project and means of finance as per the appraisal report should also be disclosed. The weakness and threats, if any, given in the appraisal report should also be disclosed by way of risk factors.

10. Project relating to the scheme

The Collective Investment Management Company shall disclose -

i) detail particulars as are sufficient to disclose the true nature of the scheme.

ii) the nature and description of property and the conditions or circumstances under which it is will become vested with the trustee.

iii) with respect to the property purchased or acquired or proposed to be purchased or acquired in relation to the scheme, the following shall be given

- the name and address of the vendor (s)

- the amount of cash or other consideration paid or payable to the vendor or each vendor, as the case may be

- short particulars of any transaction relating to the property, in which any vendor of the property or any person who is, or was at the time of the transaction, having control or controlling interest in or director of the Collective Investment Management Company or directly or indirectly related to the Collective investment management company.

(if the property to be acquired by the trustee is to be taken on lease then the term “vendor” would construe to mean “lessor”, the expression “purchase money” would include the consideration for the lease)

iv) the amount or estimated amount of -

v) the expense of setting up the scheme; and

vi) the expense of the issue, and the names of the persons by whom any of these expenses have been paid or are payable.

11. Management of the Scheme

11.1. This section shall describe the manner in which the scheme is managed. The disclosures shall include-

i) Identification of Collective Investment Management Company and the name of the key personnel of the Collective Investment Management Company who would be responsible for managing the scheme along with his qualifications, experience and background;

ii) Name and address of the Investor Relations Officer;

iii) The name and the address of the Collective Investment Management Company and the names and addresses of the Directors on the Board of the Collective Investment Management Company with a brief description of the experience of the Collective Investment Management Company;

iv) disclosure of the date of entering the Investment Management Agreement.

v) Full information regarding the remuneration/ compensation of the trustee and the Collective Investment Management Company respectively, the manner in which that remuneration/ compensation is provided for, and the changes (if any) that will be made by way of that remuneration/ compensation upon the sale of or subscription for any units of the scheme and upon the distribution of income and capital or otherwise in connection with the scheme.

11.2. The identity of any other person who provides significant administrative or business management services and a brief description of the services provided and the compensation to be paid therefore;

11.3. The name and principal business address of the Registrars and Transfer Agents. A statement to the effect that the trustee and the Collective Investment Management Company have ensured that the Registrar has adequate capacity to discharge responsibilities with regard to processing of applications and despatching unit certificates to unit holders within the time limit prescribed in the regulations and also has sufficient capacity to handle investor complaints;

11.4. Identification and name and address of the statutory auditor for the scheme;

12. Constitution of the Collective Investment Scheme

Under this head, the following shall be discussed:

- i) A brief description of the objectives of the scheme'
- ii) Functions and responsibilities of the constituents of the Collective Investment Scheme viz. Collective Investment Management Company and trustee;
- iii) Names and addresses of the Directors of the trustee and details of their principal occupations and current directorships.
- iv) Summary of substantial provisions of the Trust Deed which may be of material interest to the unit holders'

13. Units and Offer

Describe concisely the nature and the most significant attributes of the units being offered, including:

- i) The minimum and maximum number of units on offer and refund beyond this amount shall be disclosed.
- ii) The circumstances under which refund may take place and the period within which refunds must be carried out.
- iii) A calendar indicating opening, closing, earliest closing, allotment and despatch of certificates.
- iv) The period within which allotment and despatch of certificates will be completed and relevant regulations in this regard alongwith a statement to the effect that an advertisement will be published in a newspaper soon after completion of allotment procedure.
- v) Maturity period or duration of the scheme.
- vi) The circumstances under which the scheme shall be wound up (in accordance with regulations).
- vii) Procedures to be followed for transfer and transmission of units.
- viii) The rights of the unit holders including voting, calling of meetings etc
- ix) The address where the register of unit holders is or will be kept and the days on which and the hours during which the register is or will be accessible to the public.

x) The amount, if any, paid or payable as commission for subscribing or agreeing to subscribe, or procuring or agreeing to procure subscriptions for any units of the scheme, or the rate of any such commission. Also, the names of persons having control or controlling interest in or director of the Collective Investment Management Company who are entitled to receive any such commission and the amount or rate of that commission.

xi) Any amount or benefit paid or given or intended to be paid or given, to persons having control or controlling interest in or director of the Collective Investment Management Company out of the proceeds of an issue of units, and the consideration for the payment or giving of the amount or benefit.

xii) The policy regarding the valuation of any investment made or property held in relation to the scheme.

xiii) The policy regarding distribution of income to the unit holders derived from the scheme.

14. Outstanding Litigations, Defaults, Dues, etc.

i) All pending litigations in which the Collective Investment Management Company is involved, defaults to the financial institutions/banks and non-payment of statutory dues by the Collective Investment Management Company shall be listed in the offer document, together with the amounts involved and the present status of such litigations/defaults.

ii) The above information is required to be furnished in addition to the litigations against the Collective Investment Management Company or against any other entity whose outcome could have a materially adverse effect on the position of the scheme.

iii) The pending proceedings initiated for economic offences against the directors of the Collective Investment Management Company, shall be disclosed separately indicating their present status. The Collective Investment Management Company shall furnish the details of the past cases in which penalties were imposed by the concerned authorities.

iv) Outstanding litigations, defaults, etc., pertaining to matters likely to affect operations and finances of the scheme including disputed tax liabilities etc shall be furnished in the offer document.

v) The Collective Investment Management Company shall ensure to appropriately incorporate in the offer document and as risk factor(s) information regarding pending litigations, defaults, non payment of statutory dues and proceedings initiated for economic offenses/Civil offences against the schemes.

vi) If any of the above mentioned litigations, etc., arise after the filing of the offer document, the facts shall be incorporated appropriately in the offer document (and as risk factors). In case there are no such cases a distinct negative statement is required to be made in this regard in the offer document.

vii) An enquiry/ adjudication proceedings under the SEBI Act and the regulations made thereunder, that are in progress against the scheme or any company associated in any capacity with the Collective Investment Management Company, trustee or any of the Directors or key personnel of the Collective Investment Management Company shall be disclosed.

15. Disclosure on investor grievances and redressal system

The offer documents should disclose the arrangements or any mechanism evolved by the Collective Investment Management Company for redressal of investor grievances. By way of additional information, the company should disclose the time normally taken by it for disposal of various types of investor grievances. Also describe briefly the investor's complaints history for the last three fiscal years of existing scheme and the redressal mechanism, thereof. The offer document should include data updated 30 days prior to the launch of the scheme on the number of complaints received, redressed and pending with the collective investment scheme.

16. Disclosures about stock invests

The disclosures regarding manner of obtaining Stockinvests, and disposal of applications accompanied by Stockinvest, Mode of drawing stockinvests, utilisation of stockinvests by third party, time period for utilisation of stockinvests by the purchasers should be incorporated at the appropriate places in the offer document in line with the prevailing instructions of RBI in this regard. Further, name of the bank through which the stockinvests shall be realised, shall be given in the offer document. Also the following paragraph shall appear at the appropriate places.

"Registrars to the Issue have been authorised by the trustee to sign on behalf of the trustee to realise the proceeds of the Stockinvest from the issuing bank or to affix non-allotment advice on the instrument or cancel the stockinvest of the non-allottees or partially successful allottees who have enclosed more than one stockinvest. Such cancelled Stockinvest shall be sent back by the Registrars directly to the Investors."

Stockinvests should be marked account payee and inscribed with the words -Collective Investment Scheme - A/c Scheme.

17. Despatch of Refund Orders

The following clause should be incorporated in the offer document:

"The trustee shall ensure despatch of refund orders of value over Rs.1500/- and unit certificates by Registered Post only and adequate funds for the purpose will be made available to the Registrars".

18. Interest in case of delay in despatch of allotment letters/ refund orders

The caption should appear under terms of the present issue and should contain the following:

" The trustee agrees that as far as possible allotment of units offered to the public shall be made within 30 days of the closure of the issue. The trustee further agrees that it shall pay interest @15% per annum if the allotment letters/ refund orders have not been despatched to the applicants within 30 days from the date of the closure of the issue.

19. Appointment of Compliance Officer

The name of compliance officer appointed should be mentioned in the offer document with details such as telephone number, fax number and address on which he/ she would be available. The investor's attention should also be invited to contact the compliance officer in case of any pre-issue / post - issue related problems.

20. Promise vis-à-vis performance

A separate para entitled "Promise Vs Performance - ALL earlier Schemes" shall be given indicating whether all the objects mentioned in the respective offer documents relating to the earlier schemes launched by the Collective Investment Management Company were met and whether all projections made in the said offer documents were achieved. If not, non-achievement of objects/projections shall be brought out distinctly (shortfall/delay to be quantified).

21. Utilisation of stockinvest by third parties

SI should be utilised by the purchaser(s) and the purchaser's name/ name of one of the purchasers should be invariably indicated as the first applicant in the share application form. Thus, if the signature of the purchaser on the stockinvest and the signature of the first applicant on the application form does not tally, the application should be treated as having been accompanied by a third party stockinvest.

22. Utilisation of stockinvest within 10 days

Stockinvests are to be used by the purchaser(s) within 10 days of issue and for the purpose, the last day for use of the SI for submitting application to the bank is indicated on the face of the SI with a notation "To be used before".

23. Due Diligence Certificate

i) The Collective Investment Management Company, while filing the draft offer document with the Board, shall furnish a due diligence certificate.

ii) The Collective Investment Management Company shall also:-

a) certify that all amendments suggested/observations made by Board have been given effect to in the offer document;

b) furnish a fresh certificate immediately before the opening of the issue that no corrective action on its part is needed.

c) furnish a fresh certificate after the issue has opened but before it closes for subscription.

24. The Collective Investment Management Company shall submit with the offer document the following certificates:

i) all refund orders of the previous issues were despatched within the prescribed time and in the prescribed manner;

ii) all unit certificates were despatched to the allottees within the prescribed time and in the prescribed manner; and

25. Appointment of other intermediaries

i) Collective Investment Management Company should ensure that the intermediaries being appointed are registered with the Board, wherever required. The Collective Investment Management Company shall independently assess the capability and the capacity of the various intermediaries to handle the issue.

ii) Collective Investment Management Company should ensure that Bankers to the Issue are appointed in all the mandatory collection centres.

iii) Collective Investment Management Company shall ensure that Registrars to Issue registered with the Board are appointed.

iv) Registrar to an issue who is associated with the Collective Investment Management Company as a promoter or a director shall not be allowed to act as Registrar for that issue.

26. Offer document to be made public

The draft offer document filed with the Board shall be made public for a period of 21 days from the date of filing the offer document with the Board. The Collective Investment Management Company shall make copies of offer document available to the public. Collective Investment Management Company can charge an appropriate sum to the person requesting for the copy.

27. Despatch of Issue Material

The Collective Investment Management Company shall ensure that offer document and other issue materials are dispatched to the bankers to the issue, investors association etc in advance.

28. No Complaints Certificate

After a period of 21 days from the date the draft offer document was made public, the Collective Investment Management Company shall file a statement with SEBI:

- i) giving a list of complaints received by it,
- ii) a statement by it whether it is proposed to amend the draft offer document or not, and;
- iii) highlight those amendments.

29. Mandatory Collection Centres

There should be at least 30 mandatory collection centres which should invariably include the places where stock exchanges have been established.

30. Authorised Collection agents

i) The Collective Investment Management Company's are also permitted to appoint authorised collection agents subject to necessary disclosures including the names and addresses of such agents being mentioned in the offer document. While the modalities of selection and appointment of collection agents are left to the discretion of the Collective Investment Management Company's, it should be ensured that the agents so selected are properly equipped for the purpose, both in terms of infrastructure and manpower requirements.

ii) The collection agents should be permitted to collect such applications as are accompanied by payment of application moneys paid by cheques, drafts and stockinvests. Under no circumstances they should be permitted to collect application moneys in cash.

iii) The applications so collected shall be deposited in the special unit application account with designated scheduled bank either on the same date or latest by the next working day. The application forms along with duly reconciled schedules should be forwarded to the Registrars to the Issue after realisation of cheques and after weeding out the applications in respect of cheques return cases, within a period of 2 weeks from the date of closure of the issue.

iv) The applications accompanied by stockinvests should be sent directly to the Registrars to the Issue along with the schedules within one week from the date of closure of the issue. Further, the offer documents and application forms should specifically indicate that the acknowledgement of receipt of application moneys given by the collection agents shall be valid and binding on the Collective Investment Management Company and other persons connected with the issue.

v) The investors from the places other than from the places where the mandatory collection centres and authorised collection agents are located, can forward their applications along with stockinvests to the Registrars to the Issue directly by Registered Post with Acknowledgment Due and such applications shall be dealt with by the Registrars to the Issue in the normal course.

31. a) Post issue Monitoring reports

Collective Investment Management Company shall ensure the submission of the post issue monitoring reports irrespective of the level of subscription. These reports are required to be submitted within 3 working days from the due dates.

b) 3-day post issue monitoring report

The due date for this report shall be the 3rd day from the date of closure of subscription of the issue.

c) 98-day post issue monitoring report

The due date for this report shall be the 98th day from the date of closure of subscription of the issue.

32. Bankers to an issue

The trustee shall ensure that moneys received pursuant to the issue shall be utilised only after the minimum subscription as mentioned in the offer document has been received and a statement to that effect has been given by the Registrars to the Issue.

33. Post-issue advertisements

33.1. Collective Investment Management Company shall ensure that in all issues, advertisement giving details relating to oversubscription, basis of allotment, number, value and percentage of applications received along with stockinvest, number, value and percentage of successful allottees who have applied through stockinvest, date of completion of despatch of refund orders, date of despatch of certificates is released within 10 days from the date of completion of the various activities in at least two national dailies.

33.2. Collective Investment Management Company shall ensure that advisors/brokers or any other agencies connected with the issue do not publish any advertisement stating that issue has been oversubscribed or indicating investors' response to the issue, during the period when the public issue is still open for subscription by the public.

33.3. Advertisement stating that the subscription list has been closed may be issued after the actual closure of the issue. .

34. Other responsibilities

34.1. In case of delay in refund of subscription moneys/ excess subscription, the Collective Investment Management Company shall ensure that the interest for the delayed period as mentioned in the offer document, is paid to the applicants.

34.2. The Collective Investment Management Company shall ensure that the despatch of refund orders/allotment letters /share certificates is done by way of registered post /certificate of posting as may be applicable.

35. Certificate Regarding Realisation of Stockinvests

i) The Collective Investment Management Company shall submit within two weeks from the date of allotment, a Certificate to the trustee certifying that the stockinvests on the basis of which allotment was finalised, have been realised.

ii) Subscription list for the scheme shall be kept open for not more than 90 working days and this fact should be disclosed in the offer document

36. Retention of Over subscription

The quantum of issue shall not exceed the amount specified in the offer document. However, an oversubscription to the extent of 10% of the amount mentioned is permissible for the purpose of rounding off to the nearer multiple of 100 while finalising the allotment

37. Updation of Offer Document

i) The Collective Investment Management Company should ensure that the particulars (audited statement) contained therein should not be more than 6 months old from issue opening date.

ii) Restrictions, if any, on transfer and transmission of units.

iii) Tax treatment of Investments in schemes.

A detailed write-up on the various tax benefits that are available and the taxes that are charged to the unit holders in the schemes.

38. Basis of Allotment

In each and every issue of units to the public that has been oversubscribed, the Collective Investment Management Company and the Registrar to an Issue, shall ensure that allotments are made in the following manner :

a) Proportionate allotment procedure:

The allotment shall be subject to allotment in marketable lots, on a proportionate basis as explained below:

(i) Applicants will be categorised according to the number of units applied for.

(ii) The total number of units to be allotted to each category as a whole shall be arrived at on a proportionate basis i.e. the total number of units applied for in that category (number of applicants in the category x number of units applied for) multiplied by the inverse of the oversubscription ratio as illustrated below:

Total number of applicants in category of 100s -	1,500
Total number of units applied for -	1,50,000
Number of times oversubscribed -	3
Proportionate allotment to category -	$1,50,000 \times 1/3$
	= 50,000

Number of the units to be allotted to the successful allottees will be arrived at on a proportionate basis i.e. total number of units applied for by each applicant in that category multiplied by the inverse of the oversubscription ratio.

Number of units applied for by - 100
 each applicant
 Number of times oversubscribed - 3
 Proportionate allotment to each
 successful applicant - $100 \times 1/3 = 33$

(to be rounded off to
 100)

iii) All the applications where the proportionate allotment works out to less than 100 units per applicant, the allotment shall be made as follows:

*Each successful applicant shall be allotted a minimum of 100 units; and

iv) *The successful applicants out of the total applicants for that category shall be determined by drawl of lots in such a manner that the total number of units allotted in that category is equal to the number of units worked out as per (ii) above.

(v) If the proportionate allotment to an applicant works out to a number that is more than 100 but is not a multiple of 100 (which is the marketable lot), the number in excess of the multiple of 100 would be rounded off to the higher multiple of 100 if that number is 50 or higher. If that number is lower than 50, it would be rounded off to the lower multiple of 100. (As an illustration, if the proportionate allotment works out to 250, the applicant would be allotted 300 units. If however the proportionate allotment works out to 240, the applicant would be allotted 200 units). All applicants in such categories would be allotted units arrived at after such rounding off.

vi) If the units allocated on a proportionate basis to any category is more than the units allotted to the applicants in that category, the balance available units for allotment shall be first adjusted against the category comprising applicants applying m number of units and thereafter the remaining, if any surplus still remains, should be adjusted to next higher category and so on till the surplus is fully used.

(vii) As the process of rounding off to the nearer multiple of 100 may result in the actual allocation being higher than the units offered, it would be necessary to allow a 10% margin i.e. the final allotment may be higher upto 110% of the size of the offering.

39. The Date of the Offer Document

The date of the offer document shall be reckoned to be the date when the offer document was filed with the Board.

40. Trust Deed

- (a) The offer date shall mention the date of, and parties to, the trust deed relating to the collective investment scheme.
- (b) The summary of the provisions of the trust deed and the regulation regarding the retirement, removal and replacement of trustee and Collective Investment Management Company.

41. Schemes and investments

All offer documents shall contain:

- (a) All offer documents shall contain the name and description and the date of commencement of operation of every other scheme involving the issue of units to the public conducted by the Collective Investment Management Company within the 5 years immediately preceding the date of the offer document.
- (b) A report by the Collective Investment Management Company summarising the current investment relating to the scheme made up to a date not more than 28 days before the date of the offer document:
- (c) A report by the auditor of the scheme, in respect of every issue of units relating to any other scheme, launched by the Collective Investment Management Company, within the five financial years immediately preceding the date of the offer document, setting out - such information as sufficiently discloses the number of distribution (if any) of income to holders to units relating to a collective investment scheme in each of the 5 financial years immediately preceding the date of the offer document during which those units had been in existence, the amount and each distribution and the nature and value of each of the components of the distribution.
- (d) A report by the auditors of the scheme, setting out the profits or losses of the Collective Investment Management Company in respect of each of the 5 financial years immediately preceding the date of the offer document during which the Collective Investment Management Company was carrying on business, and the rates of dividends (if any) paid by the company in respect of each of those years, and the assets and liabilities of the Collective Investment Management Company as at the last date to which its accounts were made up being a date no more than 12 months before the date of issue of the offer document.

SEVENTH SCHEDULE
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999

[Regulation 27(1)]

ADVERTISEMENT CODE

- 1) A scheme advertisement shall:
 - a) be truthful, fair and clear and shall not contain any statement which is untrue or misleading.
 - b) be set forth in a clear, concise and understandable language. Extensive use of technical, legal terminology or complex language and the inclusion of excessive details which may detract the investor, shall be avoided.
 - c) not contain statements which promise or guarantee an appreciation of rapid profits.
 - d) not contain any information or language that is not contained in the offer document.
 - e) not include any slogans or brand names except the normal commercial name of the schemes.
 - f) not have slogans, expletives or non-factual and unsubstantiated titles.
 - g) contain risk factors giving equal importance in all respects including the print size. The print size of highlights and risk factors in issue advertisements shall not be less than point 9 size. It shall mention the names of schemes, Collective Investment Management Company, trustee, address of their registered office and Registrars to the Issue.
 - h) contain "Risk Factors" in respect of the concerned issue.

Provided that an offer opening / closing advertisement which does not contain the highlights need not contain risk factors.

2) A scheme advertisement shall be considered to be misleading, if it contains-

i) statements made about the performance or activities of the schemes in the absence of necessary explanatory or qualifying statements, which may give an exaggerated picture of the performance or activities, than what it really is.

ii) an inaccurate portrayal of past performance or its portrayal in a manner which implies that past gains or income will be repeated in the future.

3) Any advertisement reproducing or purporting to reproduce any information contained in a offer document shall reproduce such information in full and disclose all relevant facts and not be restricted to select extracts relating to that item.

4) No models, celebrities, fictional characters, landmarks or caricatures or the likes shall be displayed on or form part of the offer documents or advertisements of the scheme.

5) No corporate advertisement of the Collective Investment Management Company shall be issued after 21 days of the filing of the offer document with the Board till the closure of the scheme unless the risk factors as are required to be mentioned in the offer document, are mentioned in such advertisement.

6) No advertisement shall be issued stating that the scheme has been fully subscribed or oversubscribed during the period the scheme is open for subscription, except to the effect that the issue is open or closed. No announcement regarding closure of the issue shall be made except on the last closing date. If the scheme is fully subscribed before the last closing date as stated in the offer document, the announcement shall be made only after the scheme is fully subscribed and such announcement is made on the date on which the issued is to be closed.

7) Announcement regarding closure of scheme shall be made only after the trustee is satisfied that at least minimum number of units have been subscribed and a certificate has been obtained to that effect from the Registrar to the Issue.

8) No incentives shall be offered through any advertisements to anyone associated with marketing the issue.

9) In case there is a reservation for the Non-resident Indians, the scheme advertisement shall specify the same and indicate the place in India from where the individual NRI applicant can procure application forms.

10) The advertisement shall not compare one scheme with another, implicitly or explicitly, unless the comparison is fair and all information relevant to the comparison is included in the advertisement.

11) If any existing collective investment scheme indicates the past performance of the scheme in advertisements, the basis for computing the rates of return/yield and adjustments made (if any) must be expressly indicated with a statement that, such information is not necessarily indicative of future results and may not necessarily provide a basis for comparison with other investments.

12) Advertisements on the performance of a scheme or its Collective Investment Management Company shall compare the past performances only on the basis of per unit of statistics as per these regulations. Advertisements for NAVs, if any, must indicate the past as well as the latest NAV of a scheme. The yield calculations shall be made as provided in these regulations.

13) The trustee shall:

i) ensure strict compliance by the Collective Investment Management Company set with the code of advertisement set out above.

ii) obtain an undertaking from the Collective Investment Management Company to the effect that the Collective Investment Management Company shall not directly or indirectly release, during any conference or at any other time, any material or information which is not contained in the offer documents.

iii) ensure that the Collective Investment Management Company obtains approval in respect of all scheme advertisements and publicity materials from them.

EIGHTH SCHEDULE

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999

[Regulation 51]

PROCEDURE FOR CONDUCT OF MEETINGS

MEETINGS:

Procedure relating to conduct of meeting are as follows:

The trustee or unit holders holding one-tenth in nominal value of the unit capital of the scheme may call a meeting of the unit holders in the manner as set out below.

i) Within 21 days of the receipt of the notice from the unit holders, the trustee shall call a meeting of the unit holders by causing to send a notice by post of the proposed meeting at

least 7 days before the proposed meeting to each of the unit holders or, in the case of joint holders, to the joint holder whose name appears first in the records.

ii) The trustee shall preside as chairman at every meeting.

iii) Any unit holder may appoint another person as his proxy to attend and vote instead of himself.

iv) Proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

v) Each unit holder shall have one vote for every 1.00 unit of capital contributed by him (or his predecessor in title). Except where expressly provided to the contrary in the deed or the regulations, all decisions relating to the scheme shall be by ordinary resolution. Equality of voting shall result in the resolution being deemed lost. The Chairman shall have a casting vote. An extraordinary resolution shall be carried if three-quarters of the votes are in favour of the resolution.

vi) No business shall be transacted at a meeting without a quorum. Quorum shall be met if unit holders (including proxies) holding at least one-tenth in nominal value of the unit capital of the scheme are present at the meeting.

vii) The Collective Investment Management Company shall keep a minute book in which the Minutes and Resolutions of each meeting shall be recorded.

viii) At any meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is demanded by the Chairman or by any unit holder present in person.

ix) Entry of a resolution in the Minute Book shall be conclusive evidence of the number of votes recorded in favour of or against the resolution.

x) A resolution of the unit holders shall be invalid if it constitutes a fraud on those unit holders who oppose the resolution.

NINTH SCHEDULE**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****(COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME) REGULATIONS, 1999****ACCOUNTING NORMS, INVESTMENTS AND EXPENSE CEILING****[Regulations 21(13), 43(1), 44(4)(iii), 71(1)(e)]****PART I - CEILING ON EXPENSES**

The expenses incurred shall be subject to a ceiling as specified below:

(1) Initial Issue Expenses

(a) These may include:

- cost of offer documents and related costs;
- marketing and selling expenses including agents' commission, if any;
- fees to Lead managers, if any, Registrars and collecting banks
- initial rating and appraisal fees.

(b) These expenses shall be borne by the scheme.

(c) These expenses shall not exceed

- (i) 7.00 per cent of the funds raised under the scheme for a scheme of duration upto 8 years and
- (ii) 9.00 per cent of the funds raised under the scheme for a scheme having a duration of more than 8 years.

(d) These expenses shall be amortized equally over a period not exceeding seven years or the period of the scheme, whichever is less.

(2) Management and Advisory Fees to CIMC

(a) Such fees may consist of:

- Basic Fee
- Incentive Fee

(b) The 'basic fee' shall not exceed:

- (i) 1.00 per cent each year of the funds raised under the scheme for the first five years of operation of the scheme;
- (ii) 1.25 per cent each year of the funds raised under the scheme for the next five years of operation of the scheme;
- (iii) 1.50 per cent each year of the funds raised under the scheme for the subsequent period thereof till the termination of the scheme.

Incentive fees

The incentive fees shall not exceed 25 per cent of the excess return realised over and above the indicative return as shown in the offer document (excluding the unit capital) at the time of the termination of the scheme. In case the return at the termination of the scheme is less than or equal to the indicative return as shown in the offer document, then no incentive fees shall be aid.

(3) Other Expenses

Only the following expenses should be borne by the scheme namely :

- registrar services for transfer of units sold or redeemed;
- fees and expenses of trustees;
- audit fees;
- subsequent rating and appraisal fees;
- listing fees;
- Other direct costs (if any) which are incidental to the operation of the scheme, as may be approved by trustee;

(4) All other expenses shall be borne by the CIMC.

PART II - ACCOUNTING NORMS

Plantation - Scheme

1. Accounting norms for plantation scheme

2. Unit Capital

2.1 All amounts received from an investor, by whatever name called, during the period the scheme is open for subscription shall be treated as towards the sale of units of the scheme and shall be accounted as Unit Capital.

2.2 Unit capital will be disclosed in the Balance Sheet of the Scheme under the head "Sources of Funds" (in the same manner as Share Capital in the case of a limited company). No portion of Unit capital shall be apportioned to revenue or to any other account under any circumstances.

3. Costs Relating To Land

3.1 **Land Acquired with Ownership Rights** should be accounted as a Fixed Asset in accordance with Accounting Standard 10 ('AS-10') on "Accounting for Fixed Assets" issued by ICAI.

In respect of Land with ownership rights, the cost of the land should be amortised over the scheme period by way of a suitable charge to 'Crop Development Expenses'.

3.2 **Land acquired under lease** may either be against:

- Payment of (non-refundable) premium; or
- Payment of monthly or periodic lease rentals

Land acquired against payment of non-refundable premium should be accounted as a Fixed Asset and separately disclosed in the Fixed Assets schedule. Such premium paid for lease-hold land should be capitalised as cost of land and amortized over the lease period or the period of the scheme, whichever is less.

In respect of land acquired against the payment of periodic lease rentals, such amounts shall be charged to the profit and loss account.

The following disclosures are required in the financial statements:

- Period of Lease
- Owner of land

- Relationship of owner with trustees and directors of CIMC
- If lease period is shorter than tenure of the Scheme, the period of lease and conditions for future renewals of lease.

3.3 Land development Expenses

These include expenses on:

- New access roads and Fencing
- Major changes in land contours
- Levelling, uprooting and terracing
- Regular upkeep and maintenance of land

Expenses of a Capital nature should be added to the cost of land.

In case of leasehold land, these expenses should be written off over the period of the lease or the period of scheme, whichever is less.

Expenses of a revenue nature should be charged to the Profit and Loss Account in the year in which they are incurred.

3.4 Infrastructure and other facilities shall include:

- Roads and Fencing
- Security and Research and Development Buildings
- Drip Irrigation systems, water systems
- Agriculture Equipments and Production facilities

These should be accounted as Fixed Assets in accordance with AS-10 on “Accounting for Fixed Assets” issued by ICAI.

3.5 IAS 36 requires that impairment losses in respect of assets should be recognised. Impairment arises whenever an asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. All impairment losses should be provided for.

3.6 In case such assets are taken on lease, then the amounts spent should be accounted on the same basis as mentioned in Paragraph 3.2 and the disclosure requirements mentioned therein will also apply.

4. Fixed Assets (other than land and related infrastructure facilities)

4.1 Such Fixed Assets should be accounted in accordance with AS10 on “Accounting for Fixed Assets” issued by ICAI – Basically that the cost of a fixed asset comprises its purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use.

4.2 These assets should be depreciated as per Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

4.3 Capital Subsidies received should be accounted as per Accounting Standard (‘AS’) – 12 on “Accounting for Government Grants” issued by ICAI – Basically that the recognition of a grant should depend on assurance of the compliance of conditions and certainty of receipts and grants relating to specific fixed assets should be deducted from the gross value of assets in arriving at their book value.

4.4 As required by IAS 36, impairment losses in respect of assets should be recognised. Impairment arises whenever an asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount.

4.5 In case such assets are taken on lease, then the amounts spent should be accounted on the same basis as mentioned in Paragraph 3.2 and the disclosure requirements mentioned therein will also apply.

5. Crop Development Expenses

5.1 There are generally expenses incurred for development and upkeep of Crop. This includes expenses on:

- Soil Manuring.
- Sapling and crop Plantation.
- Regular maintenance and upkeep of crop.
- Lease rentals paid for land and for any other assets directly attributable to crop development.
- Amount proportionately amortised over the scheme period relating to cost of land.
- Depreciation and maintenance of fixed assets directly attributable to crop development.
- Other expenses directly attributable to crop development

These expenses should be accounted as “Crop Development Expenses”. They should be disclosed as a separate item appearing between “Fixed Assets” and “Current Assets” in the Balance Sheet.

5.2 The total of Crop development expenses at the end of the year should be compared with Net Realisable Value (‘NRV’). NRV would generally mean the amount that would be realised in the normal course, in case the standing crops are disposed off on that day. NRV can be determined on the basis of estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost to be incurred in future for bringing the crop to maturity, and the cost necessarily to be incurred to make the sale. In case the NRV is lower than the total of the crop development expenses at the year end, then a suitable provision for the difference between these two figures should be made and disclosed as follows:

Crop Development Expenses (At Cost)	X	
Less: Provision for diminution in value	Y	
	<hr/>	X-Y

5.3 The crop development expenses and the provision for diminution will be carried forward to the next year at gross values. A similar exercise would be done at the end of each year. In case the NRV at the end of the second or subsequent year is greater than/or equal to cost in the respective year, then it will be possible to recoup the provision account by transferring it to the credit of Profit and Loss Account only to the extent such a provision was made in the past. The basic principle of valuation at lower of Cost or NRV, would still hold good every year. In case the crop is at such a stage that it is not possible to determine NRV, these expenses should be valued At Cost and a suitable disclosure to that effect should be made in the financial statements. These expenses will be set off against income arising from the sale of crops, either in stages or at the terminal point.

5.4 Considering the peculiar nature of this expenditure and the long production cycle, “Crop Development Expenses” should be separately disclosed between “Fixed Assets and Current Assets” as discussed in Paragraph 5.1 above.

6. Investments

6.1 All investment should be carried at lower of cost and fair value determined either on an individual investment basis or by category of investment, but not on an overall (or global) basis.

6.2 In respect of quoted investments, market value generally provides the best evidence of fair value.

6.3 Unquoted investments in debt instruments should be valued on a yield to maturity basis, the capitalisation factor being determined for comparable traded investments and with an appropriate discount for lower liquidity

7. Inventory Valuation

Inventories other than Crop Development Expenses should be valued as per the basic principles laid down by AS 2 on Inventory Valuation – Inventory should be valued at the lower of cost and net realisable value and the Accounting Policy for valuation should be disclosed in the financial statements.

8. Revenue Recognition

8.1 Revenue should be recognized as per Accounting Standard ('AS') – 9 on "Revenue Recognition" issued by Institute of Chartered Accountants of India, to the extent it is applicable – Revenue should be recognised only if there is a reasonable certainty of collectibility or measurability.

8.2 Income would generally arise from the following sources:

- Sale of Crops - the sale proceeds of crops arising at periodical intervals should be accounted during the year in which the sale has been effected. The cost allocable to such sale proceeds should be set off against the crop development expenses account and the surplus, if any, should be transferred to Profit and Loss account.
- Sale of Residuals and Scraps - the sales proceeds shall be accounted as income in the year of sale and credited to Profit and Loss account.
- Income from Investments - income arising out of investments of surplus bank balances, etc. shall be accounted on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.
- Dividend from Investments - dividends, if any, will be recognized when the right to receive payment is established.
- Sale of Standing Crops at terminal point - sale proceeds/transfer value of the standing crops at the terminal point shall be accounted as and when they are disposed off/transferred. The profit arising on such transactions over the book value shall be accounted at the point of sale/disposal; this should be set off against the crop development expenses.

9. Expenses

9.1 Expenses other than Crop Development Expenses can be broadly classified as under:

- Initial Marketing and Launch Expenses
- Normal Business Expenses

9.2 Initial issue expenses

Initial issue expenses may be treated as deferred revenue expenses to be written off over eight years or duration of the scheme whichever is earlier.

9.3 Normal Business Expenses would include:

- Registrar services for transferor of units sold or redeemed
- CIMC and trustee Fees
- Depreciation
- Audit Fees
- Subsequent Rating and Appraisal Fees
- Listing Fees
- Other costs, (if any), which are incidental for the operation of the scheme, as may be approved by trustees.

These expenses shall be treated as an expense of the year in which they are incurred and written off to the Profit and Loss Account.

10. Returns to Investors

10.1 Interim Returns to investors in respect of CIS can be paid only out of the distributable surplus of the CIS. Interim Returns can be paid only in cash and not in kind.

10.2 "Distributable surplus" means the profits of the CIS after:

- Providing for all expenses on accrual basis including depreciation as discussed in paragraph 4.2 above
- Providing for diminution in value of crop development expenses as discussed in paragraph 5.2 above
- Fully setting off the debit balance in Profit and Loss account, if any
- Transferring 50% of the remaining balance to a separate reserve called "Special Reserve"

10.3 The amount of interim returns distributed to investors should not exceed the distributable surplus.

10.4 The balance in the Special Reserve cannot be utilised for any purpose except for distribution to unitholders at the termination of the scheme.

10.5 At the end of the tenure of the Scheme, the surplus of the scheme, if any, shall be calculated on the basis of realisable value of all the assets, including land, of the Scheme. The surplus of the scheme distributed in cash shall be in proportion to unit capital.

Accounting norms: Livestock Scheme

1. Costs relating to owned land

1.1 Land acquired with ownership rights should be accounted as a Fixed asset in accordance with Accounting Standard 10 (AS-10) on "Accounting for Fixed Assets" issued by ICAI.

1.2 Cost of such land should not be amortised over the scheme period (refer paragraph 2.3 above).

2. Livestock development expenses

2.1 There are generally expenses incurred on rearing and development of livestock including maintenance and upkeep. This includes expenses on:

- Cost of base stock.
- Food costs.
- Medicines and other maintenance.
- Cost of artificial insemination.
- Lease rentals paid for land and for any other assets directly attributable to livestock development.
- Depreciation and maintenance of fixed assets directly attributable to livestock development.
- Any other expenses directly attributable to livestock development.

These expenses should be accounted as "Livestock Development Expenses". They should be disclosed as a separate item appearing between "Fixed Assets" and "Current Assets" in the balance sheet. (Reference is invited to Paragraph 5.1)

2.2 Valuation of livestock development expenses and provision for diminution in value would be in the same manner as in respect of crop development expenses which is discussed in Paragraphs 5.2 and 5.3.

3. Livestock Trading

3.1 Separate quantitative information should be maintained in respect of livestock that is procured for resale without being used in rearing/development activity. An annual trading account should be prepared in respect of Livestock traded during the year (which shall be exclusive of Livestock under rearing/development).

3.2 A suitable annual charge should be made in respect of cost of maintenance etc of the Livestock which remained for trading purpose only. The cost of maintenance etc to be charged to the Livestock trading account shall be calculated on the basis of quantitative proportion of Livestock held under rearing/development and for trading.

4. Valuation of by-products

4.1 Inventory of by-products at the year end (i.e. manure in case of Goat, eggs in case of Poultry etc.) should be carried at "lower of cost or market value".

4.2 Cost of by product shall be calculated on the basis of specific cost incurred on the by-product after the point of separation to make it marketable.

PART III - FORMAT OF FINANCIAL STATEMENTS

Basic Framework relating to Financial Statements

1. Scheme wise financial statements

1.1 Broadly, financial statements would consist of

- Balance sheet
- Revenue account

1.2 These should be prepared scheme wise

2. Contents of scheme wise Balance sheet

2.1 Asset side of the balance sheet

The assets of the balance sheet shall be grouped into the following categories

- Fixed assets
- Investments
- Crop development expenses
- Current assets
- Deferred revenue expenditure

I. Fixed assets

Cost, accumulated depreciation and net block should be disclosed for each of the following:

- Land
- Leasehold land
- Land development expenses
- Infrastructure and other facilities
- Buildings
- Plant and machinery
- Furniture and fixtures
- Research and development assets
- Others

II. Investments

The following types of investment shall be separately disclosed:

- Central or State Government securities
- Deposits with scheduled banks
- Debentures, Bonds and Deposits with public sector companies and financial institutions
- Other Investments

III. Crop Development Expenses

The following information should be disclosed:

- Opening balance
- Expenses incurred during the year
- Deductions
- Closing balance

In addition, net realisable value at year end and the Break up of various expenses included in closing balance should be disclosed.

The closing balance in provisions for diminution in value in Crop Development Expense Account, if any, will be shown as a deduction from closing balance of Crop Development Expenses.

IV. Current assets

The following should be separately disclosed:

- Balances with banks in current account.
- Cash on hand
- Sundry debtors, distinguishing between good and doubtful
- Inventories

- Outstanding and accrued income
- Advances recoverable in cash or kind
- Deposits
- Others

V. Deferred revenue expenditure

The following should be disclosed:

- Opening balance
- Additions during the year
- Amount amortised during the year
- Closing balance

VI. The debit balance in Profit and Loss Account, if any, shall be brought out.

2.2 Liability side of the balance sheet

Liabilities in the balance sheet shall be grouped into the following categories:

- Unit Capital
- Reserves and Surplus
- Current liabilities and provisions

I. Unit Capital

Unit capital (including number of units and face value per unit)

II. Reserves & Surplus

The following should be separately disclosed:

- General reserve
- Revaluation reserve

- Special reserve
- Any other reserve (disclosing its nature)
- Surplus in Profit and Loss account

III. Current liabilities and provisions

(a) Current Liabilities

The following should be separately disclosed

- Sundry creditors
- Statutory liabilities
- Bank account overdrawn as per books
- Unclaimed distributed income
- Others

(b) Provisions

The following should be separately disclosed:

- Provision for gratuity
- Proposed income distribution on unit-capital
- Provision for taxation
- Other provisions

IV. Contingent liabilities

Disclosure should be made of all contingent liabilities, showing separately the nature and amount of each such liability.

3. Contents of scheme wise Revenue account

3.1 Income

The following should be separately disclosed:

- Surplus on Sale proceeds from crops
- Dividend
- Interest
- Profit on sale/fixed assets and investments
- Sale of residuals and scrap
- Other income (indicating nature)

3.2 Expenses and losses:

The following should be separately disclosed:

- Crop development expenses also disclosing each major item of expense under this head
- Provision for doubtful debtors and other assets
- Loss on sale of fixed assets and investments
- Management fees
- Trusteeship fees
- Registration and local charges
- Audit fees
- Repairs and maintenance
- Deferred revenue expenses written off
- Depreciation of fixed assets

- Registration fees
- Other operating expenses

3.3 Increase/decrease in amount of Crop Development Expenses.

4. Accounting policies

Accounting policies in respect of the following should be separately disclosed at one place and form part of the financial statements:

(a) Fixed assets

1. Land
2. Others

(b) Depreciation

1. Land
2. Others

(c) Investments

(d) Crop Development Expenses (major items under this head should be disclosed)

(e) Inventories

(f) Revenue recognition

(g) Retirement benefits

(h) Foreign currency transactions

(i) Deferred revenue expenditure

5. Approval and authorisation

The financial statements shall be signed by the scheme wise fund managers and the Board of trustees and reported upon by the Auditors. They should be approved at a meeting of the Board of Directors of the Collective Investment Management Company and also at a meeting of the trustees or in case of a trustee company, by the Board of directors of the trustee Company.

6. Auditors report

6.1 All funds operating CIS shall be required to get their accounts audited in terms of a provision to that effect in their trust deeds. The Auditors' Report shall form a part of the Annual Report. It should accompany the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Revenue Account. The auditor shall report to the Board of trustees and not to the unit-holders

6.2 The auditor shall state whether:-

(a) he has obtained all information and explanations which, to the best of his knowledge and belief, were necessary for the purpose of his audit.

(b) the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Revenue account are in agreement with the books of account of the scheme.

6.3 The auditor shall give his opinion as to whether:

(a) The Balance Sheet gives a true and fair view of the schemewise state of affairs of the scheme as at the balance sheet date, and

(b) The Profit and Loss Account gives a true and fair view of the surplus/deficit of the scheme for the year/period ended at the Balance Sheet date, and

(c) The Revenue Account gives a true and fair view of the schemewise surplus/deficit of the scheme for the year/period ended at the balance sheet date.

